हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

17/03/2017/1100/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः3880

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिलावार विस्तृत उत्तर दिया है और इसमें बताया हुआ है कि कुल 191 व्यक्तियों को घर बनाने के लिए जमीन आबंटित की गई है। जो जिलावार ब्योरा दिया गया है उसमें तीन जिलों, जिसमें कांगड़ा में 91, सिरमौर में 30 और सोलन में 42 लोगों को भूमि आबंटन हुआ है। इन तीन जिलों में 191 में से 163 लोगों को घर बनाने के लिए जमीन आबंटित की गई है। बाकी अन्य जितने जिले हैं उनमें केवल 28 लोगों को ही घर बनाने के लिए जमीन आबंटित की गई है। इसके क्या कारण हैं? क्या अन्य जिलों में भूमिहीन लोग नहीं हैं या कानून में कोई जटिलताएं हैं? दूसरे, कितनी जमीन अर्बन एरिया में बांटी गई तथा कितनी रूरल एरिया में बांटी गई? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने प्रदेश में ऐसा कोई सर्वे करवाया है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास घर बनाने के लिए भूमि नहीं है? अगर सर्वे नहीं करवाया है तो क्या सरकार ऐसा कोई सर्वे करवाएगी और यदि ऐसे लोग हैं तो क्या सरकार उनको घर बनाने के लिए जगह देने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, इस सरकार की यह मंशा थी कि हिमाचल प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जिनके पास घर बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं है उनमें कुछ महिलाएं है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं तो उनके लिए वीरभद्र सिंह जी ने एक नीति बनाई और नीति को हम लागू कर रहे हैं। इसमें जहां तक सर्वे करने की बात है तो कोई सर्वे नहीं किया गया है लेकिन इसकी हमने वाइड पब्लिसिटी की है। हरेक तहसील लैवल पर कहा गया है कि जिनके पास घर बनाने के लिए कोई जमीन नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा और शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा जमीन देने का हमने फैसला किया है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

17.03.2017/1105/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 3880 ः-----जारी-----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः---जारी---

उसमें हमने रिलैक्स कर दिया है कि अगर टी0सी0पी0 के तहत दो से तीन बिस्वा की जरूरत पड़ेगी तो हम उनको तीन बिस्वा भी दे देंगे। यह स्कीम मांग पर आधारित है। यह demand given scheme है। जो लोग तहसीलदार के पास आएंगे वे बताएंगे, ठीक है जिन 191 लोगों को हमने भूमि आबंटित की है उसमें से 95 लोग अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं, 31 व्यक्ति ओ0बी0सी0 से सम्बन्धित है और 5 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है। यह ठीक है कि कुछ जिलाधीशों ने इसमें ज्यादा काम नहीं किया है। सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू और सोलन के जिलाधीशों ने इसमें काफी इनिशेटिव लिया है। दूसरे जिलों जैसे मण्डी में सिर्फ दो केस हुए हैं, ऊना में दो केस है, हमीरपुर में तीन केस है, लाहौल-स्पिति में एक केस है और शिमला में भी एक केस है। हमने जिलाधीशों को समय-समय पर हिदायतें दी है। जो लोग बिल्कुल भूमिहीन है उनको प्राथमिकता दी जाए। तहसीलदारों को हिदायतें दी जाए और अगर उनकी शिनाख्त भी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, **मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो पात्र व्यक्ति होंगे और हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव जिनके पास राजस्व विभाग भी है उनको मैं कहूंगा कि जिलाधीशों को शीघ्रातिशीघ्र इस बारे में हिदायत दें कि जल्दी से जल्दी उन प्रार्थना पत्रों को जो लम्बित पड़े हैं छः महीने के अन्दर-अन्दर डिस्पोज ऑफ करें।** यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री रविन्द्र सिंह (प्राधिकृत)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय मंत्री महोदय ने इस कथन के बारे में ज़वाब दिया इसके अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो जानकारी आपने यहां पर उपलब्ध करवाई है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की डायरैक्शन के उपरान्त एक नीति

बनाई है वह नीति आपने क्या बनाई, उसकी प्रतिलिपि इस माननीय सदन में उपलब्ध करवाएंगे?

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे भूमिहीन है जिनके पास घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है। ऐसे प्रदेश के कितने परिवारों/लोगों ने एप्लाई कर रखा है? जो 191 को आपने जमीन दी और कब तक आप सभी को जिन्होंने एप्लाई कर रखा है घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवा देंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय जैसे कि मैंने कहा कि यह demand given scheme है। जिस व्यक्ति की अपनी जमीन नहीं है वही डी0सी0 को एप्लाई करेंगे और वह तहसीलदार को केस भेजकर वैरिफाई करेंगे। इसमें जो पात्र व्यक्ति होंगे उनको जमीन दी जाएगी। यह स्कीम मुख्य मंत्री के आदेशानुसार राजस्व विभाग केबिनैट में ले गए थे और केबिनैट ने इस स्कीम को मंजूरी दी है। यह स्कीम गरीबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारी सरकार की स्कीम है। जहां तक हमने नीति बनाई है यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसको हम टेबल ऑफ द हाऊस में भी रख देंगे। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो मैं बोल भी देता हूं। **अभी 4000 एप्लिकेशन्ज लम्बित पड़ी हैं। मैंने कहा है कि जो इसमें पात्र व्यक्ति होंगे उनको छः महीने के अन्दर-अन्दर उनकी एप्लिकेशन्ज डिस्पोज ऑफ कर देंगे और उनको जमीन देने का प्रबन्ध करेंगे।**

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उप मण्डल बैजनाथ में कितने लोगों ने एप्लाई किया और कितनों को जमीन मिली? जो सूचना यहां पर रखी गई है उसके मुताबिक केवल तीन व्यक्तियों को बैजनाथ में जमीन मिली है। वहां पर कई लोग पात्र हैं। जिन्हें कई-कई चक्कर पटवारियों के काटने पड़ते हैं और फिर भी उन्हें जमीन नहीं मिलती इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे कहा जो लोग एप्लाई करेंगे उनको ही जमीन देंगे और जो पात्र व्यक्ति होंगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

17.03.2017/1110/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 3880 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

मैं तो डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने 91 भूमिहीनों को तीन-तीन और दो-दो बिसवे जमीन एलॉट की है। He has done commendable job. I appreciate his action. जहां तक दूसरे डिप्टी कमिश्नर्ज़ हैं जिन्होंने इसमें ज्यादा इंट्रस्ट नहीं लिया है हम उनको हिदायद देंगे कि जो एप्लीकेशन्ज़ उनके पास आई हैं उन्हें छः महीने के अंदर-अंदर डिस्पोज़ ऑफ करें ताकि लोगों को जमीन मिले और वे उस पर अपना मकान बनाएं। मुख्य मंत्री महोदय ने जो आवास योजना शुरू की है, पहले उसमें 75 हजार रुपया देते थे लेकिन अब 1 लाख 25 हजार रुपया मकान बनाने के लिए बजट में घोषणा की है।

अध्यक्षः लास्ट सप्लीमैंटरी, श्री रविन्द्र सिंह।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय मंत्री महोदय ने यहां बताया कि इनके पास अभी भी चार हजार एप्लीकेशन्ज़ लम्बित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितना समय इनकी छंटनी में लग जायेगा कि इनमें से कितने पात्र हैं और उन पात्र व्यक्तियों को कब तक दो या तीन बिसवे जमीन शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करवायेंगे?

अध्यक्षः इन्होंने छः महीने के अंदर बोल दिया है कि उपलब्ध करवायेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो divorcee हैं जिनको न तो सुसराल वालों ने जमीन दी है और न ही अपने माता-पिता के पास वापिस आकर उनको भूमि मिली है, क्या उनको लैंडलैंस में गिना जायेगा और घर बनाने के लिए उनको भी शहरी क्षेत्र में दो बिसवे और ग्रामीण क्षेत्र में तीन बिसवे जमीन दी जायेगी?

Health & Family Welfare Minister: Sir, I have already stated that 4000 applications are pending with the respective Deputy Commissioner in the State. He is very much concerned about divorcee. The State Government also

17.03.2017/1110/SS-AG/2

wants to help the divorcee in case they are landless. In case there is a single lady or divorced woman, they will be given preference in the allotment of this land that I may inform you because the Government is very much concerned about their well being. So, as I have said, Sir, these applications will be scrutinized by the respective Deputy Commissioner and will be disposed of within six months and whosoever is found eligible they will be allotted the land accordingly.

Chief Minister: My esteemed colleague, the Revenue Minister has given full detail of the matter. But I do accept the concern of the people regarding this, especially the people who have applied for it. So, I want to say that all these cases will be decided within three months. Within three months even if they have to work overtime these cases will be definitely decided within three months.

Concluded

17.03.2017/1110/SS-AG/3

प्रश्न संख्या: 3881

श्री राम कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आंगनवाड़ी भवन बन रहे हैं पहले इनमें 2 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी और उसके बाद फिर यह राशि साढ़े चार लाख हुई। अब शायद यह 7 लाख हो गयी है। मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन पंचायतों में तीन आंगनवाड़ी भवन ऐसे हैं जिनके लिए सी0डी0पी0ओ0,

धर्मपुर ने बार-बार पंचायतों से पत्राचार किया और पंचायतों की तरफ से यह लिखा गया कि यह दो लाख की राशि पर्याप्त नहीं है क्योंकि वहां पर खच्चरों के माध्यम से कैरेज़ होकर मैटीरियल जायेगा। इसलिए दो लाख रुपया में वह आंगनवाड़ी भवन नहीं बनाया जा सकता। तो मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि ग्राम पंचायत गोयला के गांव बड्डुल में, ग्राम पंचायत वुघार कनैतां और पट्टा वाडियां और जाडला के जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों को दो या ढाई लाख रुपये की राशि पूर्व में स्वीकृत की गई थी, क्या उन्हें अतिरिक्त धनराशि देने का आश्वासन देंगे?

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2017/1115/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3881 जारी---

श्री राम कुमार जारी---

दूसरे, जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों का इन्होंने अपने जवाब में जिक्र किया कि 9 लाख रु0 की अतिरिक्त धनराशि दी जा चुकी है, मैं जानना चाहूंगा कि वे कौन से आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जिनके लिए यह 9 लाख रु0 की धनराशि दी गई है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें पूछी है कि जो पहले दो लाख रु0 था, क्या उसमें अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी? जहां तक पांच आंगनबाड़ी केन्द्रों का इन्होंने जिक्र किया है, उसकी डिटेल भी मैं दे देता हूं।

सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2006-07 में जब ये 2 लाख रु0 होते थे तो पूरी स्टेट गवर्नमैंट फंडिंग होती थी। कुछ एस.सी. सब- प्लान से भी दिया जाता था और 2007-08, 2008-09 तक 75:25 के अनुपात में यह राशि बंटती गई और

2014-15 में साढ़े चार लाख और अब 2016-17 तक यह सात लाख रु0 हो गई है और इसमें केन्द्रीय सरकार का 90 और स्टेट गवर्नमैंट का 10 प्रतिशत अनुपात है। जहां तक माननीय सदस्य ने 2 लाख रु0 के बारे में पूछा तो यह निर्धारित दर के अनुसार दिया गया है परन्तु यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि वहां पर बहुत दिक्कत है और वहां तक खच्चरों से भी जाना पड़ता है तो उस पर इनको अतिरिक्त राशि दे दी जाएगी।

जहां तक इन्होंने पांच आंगनबाड़ी केन्द्रों के बारे में पूछा है, उनमें सभी में राशि दे दी गई है परन्तु यदि आपको यह कम पड़ती है तो वह राशि भी आपको दे दी जाएगी और जो भी इसमें कमी होती है, वहां पर क्या स्थिति है, यह एक्सप्लेन करना जरूरी है, वह एक्सप्लेन करें तो आपको वह अतिरिक्त धनराशि भी दे दी जाएगी।

प्रश्न समाप्त

17.03.2017/1115/केएस/एजी/2

प्रश्न संख्याः 3882

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गई है, मुझे लगता है कि यह सही सूचना नहीं दी गई है। जो इस प्रश्न के "क" भाग में जवाब दिया है, 1 जनवरी, 2013 को देहरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में तहसील देहरा ही सृजित थी। इसमें सम्मिलित कानूनगों एवं पटवार वृत्तों का विवरण भी दिया गया है। इसमें नगरोटा सूरिंया जो सब तहसील थी उसका जो कानूनगो सर्कल बिलासपुर, जो सारे का सारा देहरा में पड़ता है, यह प्रथम जनवरी, 2013 को भी नगरोटा सूरियां उप-तहसील में ही शामिल था। जिसमें पटवार सर्कल है गुलेर, नन्दपुर, सरकरी, बिलासपुर धार, चन्दुआ ये उसका हिस्सा हुआ करते थे।

उसके उपरान्त यहां पर डीलिमिटेशन कमिशन ने इकाई एक युनिट मानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र है वह इकाई होगा। आपकी सरकार बनी और उसके उपरान्त आपने सारे

विधान सभा क्षेत्र को छिन्न-भिन्न कर दिया। देहरा विधान सभा क्षेत्र को आपने तोड़कर रख दिया। एक तहसील डाडासीबा बनाई । मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है लेकिन वहां की जनता, "ग" भाग में जो आपने जवाब दिया है, मैंने पूछा था कि क्या वहां की जनता व पंचायतों से आपने कोई एन.ओ.सी. लिया था, उनको शामिल करने के लिए क्या कोई आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई ? आपने कहा, जी, नहीं। जबकि उन्होंने चाहा नहीं था और डाडासीबा में भी आपने जा कर तहसील में मेरे दो पटवार सर्कल वहां पर शामिल कर दिए। जबकि मैंने डी.सी. महोदय के माध्यम से आपको भी रैप्रिजेंट किया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या जो पंचायतें नहीं चाहती, जो पटवार सर्कल हरिपुर सब तहसील में नहीं जाना चाहते, अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय, 2 फरवरी को बनखण्डी में जा कर आए थे, वहां पर भी लोगों ने इनको कहा होगा । बनखण्डी को, त्रिपल को और हमारे तीन-चार पटवार सर्कल और हैं, उनको देहरा साथ में पड़ता है। आपने उन पंचायतों

17.03.2017/1115/केएस/एजी/3

को, उन पटवार सर्कलों को लिया और हरिपुर में मिला दिया जो कि 12 किलोमीटर दूर है । यह जो सारा का सारा किया है, क्या इसको फिर से आप जिला प्रशासन को डी.सी. महोदय की डायरैक्शन देंगें कि जैसे वहां की जनता चाहती है, मेरे कहने पर नहीं जो वहां के लोग, वहां की पंचायतें चाहती हैं, क्या उनको वहां पर वैसे का वैसा इम्पलीमैंट करवाएंगें, यह माननीय मंत्री महोदय बताएं?

मंत्री जी, श्री टी.सी.वी. की बारी में---

17/03/2017/1120/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
प्रश्न संख्याः 3882 ..... क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, इनको खुशी होनी चाहिए, पहले देहरा ही एक तहसील थी, जिसमें 44 पटवार सर्कल थे और उसमें 4 कानूनगो सर्कल थे। सरकार की नीति है 'प्रशासन जनता के द्वार' और जब माननीय मुख्य मंत्री जी फिल्ड में जाते हैं, तो लोगों की मांग पर नई उप-तहसीलें, सब-तहसीलें और सब-डिविज़न खोले जाते हैं। अभी तक अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले 4 सालों में 15 नये एस0डी0एम0 कार्यालय, 13 नई तहसीलें और 31 नई उप-तहसीलें हिमाचल प्रदेश के अंदर खोली हैं। in order to give relief to the local people who are residing there. आपके चुनाव क्षेत्र में 4 कानूनगो सर्कल थे, पहले एक-एक कानूनगो सर्कल 12-14 पटवार सर्कल का होता था, अब 5-6 पटवार सर्कल में एक कानूनगो सर्कल होगा। इस तरह से आपके कानूनगो सर्कल भी बढ़े हैं, डाडासिबा तहसील और हरिपुर उप-तहसील बनी है। इसके अलावा एक उप-तहसील परागपुर भी बनी हैं। परागपुर एक हैरिटेज़ विलेज़ है, उसको भी हमने उप-तहसील बनाया है। जब हम कोई युनिट गठित करते हैं, तो कोई फॉर्मल कंस्लटेशन पंचायत से नहीं की जाती है It is purely an administrative matter. तहसीलों, उप-तहसीलों और कानूनगो सर्कल का गठन करने के लिए अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं और यदि लोगों के सुझाव आएंगे which are for the convenience of the people, the Government will definitely consider those views.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय मंत्री महोदय ने यहां जवाब दिया है, मैं पहले ही पंचायतों के प्रस्ताव आपको और उपायुक्त, कांगड़ा को रिप्रेजेंट कर चुका हूं। आपने डाडासिबा में 2 पटवार सर्कल चनौर और वैंह वहां पर मिलाए हैं। इन दोनों की पटवार सर्कल के लोग डाडासिबा को जाने के लिए तैयार नहीं है। देहरा, देहरा विधान सभा चुनाव क्षेत्र का केन्द्र है, वहां से जितनी दूर हमारा सकड़ी का इलाका पड़ता है, उतनी ही दूर चनौर का पटवार सर्कल पड़ता है। जबकि इन पंचायतों ने आपको और

डी0सी0, कांगड़ा को लिखकर दिया है। इसके साथ ही जो बनखंड़ी का इलाका है, यहां के लोग भी देहरा में रहना चाहते हैं ये भी हरिपुर नहीं जाना चाहते हैं। जो केस आपको पहले रिप्रेजेंट किए जा चुके हैं, क्या उनको जैसे वे पहले थे, वैसे ही रहने दिया जाएगा? आपने नई तहसीलें, उप-तहसीलें खोली हैं, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं और न मैंने किया है,

17/03/2017/1120/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

लेकिन ये जहां पर खोली जाये, वहां पर लोगों को लाभ देने के लिए खोली जानी चाहिए, लोगों को तंग करने के लिए नहीं खोली जानी चाहिए। लोग वहां नहीं जाना चाहते हैं और आप उनको जबरदस्ती भेज रहे हैं।

Health and Family Welfare Minister: Hon'ble Speaker, Sir, of course, the Hon'ble Member has given a proposal. We will definitely ask the Deputy Commissioner, Kangra, to look into the matter about the two Patwar Circles, which you want to be included with other. We would also like that the Gram Sabha or those Panchayats or Patwar Circles should also, i.e. is Gram Sabha not Gram Panchayats and that was a Gram Panchayat Resolution, Sir, because these administrative units are created for the convenience of the people, if Gram Sabha wants itself to exclude from the Sub-tehsil and include in Circle, definitely Government will examined it, keeping in view the administrative and people convenience.

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

17/03/2017/1125/ एन0एस0/ए0एस0/1

प्रश्न संख्याः -3883

श्री खूब राम : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा कि आनी विधान सभा क्षेत्र के अंदर 24 आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत हैं। इसमें आयुर्वेदिक औषधालय जटेहड़, खणाग एवं उर्टू में हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी ने बजट का भी प्रावधान किया है। आयुर्वेदिक औषधालय जटेहड़ के भवन के निर्माण के लिए 15.83 लाख रूपये की राशि और खणाग के लिए 17.52 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त 4.50 लाख रूपये की राशि उर्टू आयुर्वेदिक औषधालय के लिए दी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह राशि कब पी0डब्लयू0डी0 विभाग को भेजी गई है और कब तक इनके टैंडर लग जायेंगे? यह राशि वर्ष 2016 को सैंक्शन हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि कब तक इनकी टैंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जटेहड़ और खणाग के भवनों के लिए जो पैसा दिया है क्या वह पर्याप्त है? यह भवन कब तक बन करके तैयार हो जाएंगे ताकि इसमें हम भवन चला सकें।

सहकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आनी क्षेत्र में 24 आयुर्वेदिक औषधालय हैं। इनमें से तीन डोनेशन पर और तीन प्राईवेट चले हुए हैं तथा वहां का काम चालू है। माननीय सदस्य ने कहा है कि जो 4.50 लाख रूपये की राशि दी है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सिराज मण्डल, निरमण्ड के पक्ष में वर्ष 2016 में जारी कर दी गई है। मैं इसको चैक करूंगा कि यह राशि वहां पर क्यों नहीं पहुंची है और इसको तुरन्त जारी कर दिया जाएगा। अगर इसका काम नहीं हुआ है तो मैं इसको चैक कर लूंगा।

17/03/2017/1125/ एन0एस0/ए0एस0/2

प्रश्न संख्याः -3884

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग में शुरू की इकाई पटवारी है। पटवारी का सहयोगी नम्बरदार है, जिनको घर-घर जा करके मामला भी इक्ट्ठा करना पड़ता है। जब भी कोई रजिस्ट्री तहसील में होगी तो नम्बरदार को ले जाना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप अपनी सरकार को बड़ी पारदर्शिता की सरकार

बोलते हैं। इस बेसिक इकाई जिनको इतना काम करना पड़ता है, इस मामले को आप कब तक विचारधीन रखेंगे या जल्दी इसका निर्णय लेंगे? माननीय मंत्री जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि Numberdaar is an important functionary of the Revenue Department. पहले वे जितना रैवेन्यू कोलैक्ट करते थे उसका इनको 20 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता था। फिर वर्ष 1997 में जब हमारी सरकार थी, हमने वह हिस्सा बढ़ा करके जितना ये रैवेन्यू इक्ट्ठा करते थे उसका 50 प्रतिशत देने का फैसला किया। वर्ष 2012 में उस समय की सरकार ने फैसला लिया कि नम्बरदारों को एक साल का मानदेय 2000 रूपये दिया जाए। मैं समझता हूं कि यह न्यायोचित नहीं है। जैसा आपने कहा मैं भी इस बात को मानता हूं। नम्बरदार बहुत महत्वपूर्ण फंक्शनरी है। हर वक्त नम्बरदार की जरूरत रहती है। जब भी कोई रजिस्ट्री होती है तो नम्बरदार की गवाही लगती थी। नम्बरदार की हाजिरी में इंतकाल चढ़ता है। उनको पिछली सरकार ने सिर्फ 2000 राशि दी थी। वर्तमान सरकार महसूस करती है कि यह राशि बहुत कम है। इसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है। नम्बरदारों के साथ एक बार नहीं हमने तीन-चार बार मीटिंग्ज़ की हैं। वे मुख्य मंत्री जी को मिले हैं। मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं। मण्डी में हमने सारे हिमाचल प्रदेश के नम्बरदारों के साथ मीटिंग की। इसलिए मैंने कहा कि Matter is under the active consideration of the State Government and we will definitely look into the genuine demands of Numberdaars, keeping in view our financial position.

समाप्त

अगला प्रश्न, श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

17/03/2017/1130/RKS/DC/1

<u>प्रश्न संख्याः 3885</u>

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की जानकारी में बतलाना चाहूंगा कि जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत पीरन, सतलाई, दरभोग व कोटी हैं, मुझे इन पंचायतों का उत्तर प्राप्त हो गया है कि वर्ष 2011 से पूर्व किन-किन जंगलों से इन पंचायतों को टी.डी. उपलब्ध करवाई जाती थी। लेकिन उत्तर में यह नहीं दशार्या गया है कि वर्तमान में टी.डी. कहां से उपलब्ध हो रही है? माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 2011 से पूर्व जिन जंगलों से नियमानुसार ग्रामीणों को लकड़ी दी जाती थी, वह लकड़ी वर्तमान में भी उन्हीं जंगलों से दी जाए। सैटलमैंट में यह जंगल चेंज न किए जाएं। साथ ही डुमी ग्राम पंचायत जिसका क्षेत्र टूटू पड़ता है वहां पर भी टी.डी. का ऐसा ही मसला है। वहां पर पुस्त-दर-पुस्त लोग रह रहे हैं। क्योंकि जब तक रेवन्यू डिपार्टमैंट लिखकर नहीं देता तब तक वन विभाग टी.डी. नहीं दे सकता है। यहां आधे गांव को टी.डी. मिलती है और आधे गांव को नहीं मिलती है। Please look into this matter immediately ताकि लोगों को उनके राइट मिल सके।

उद्योग मंत्री(प्राधिकृत)ः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि टी.डी. किसी भी तरह बंद नहीं की गई है। टी.डी. बदस्तूर मिल रही है। टी.डी. राइट हॉल्डर्स को ही मिलती है। ग्रीन फैलिंग पर प्रतिबंध है इसलिए सूखे पेड़ो से टी.डी. दी जाती है। माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में ही 123 क्यूबिक मीटर में 54 पेड़ों की टी.डी. दी गई है। हाउसिंग कॉलोनिज़ या जिन लोगों ने जमीन खरीदकर मकान बनाए हैं उन लोगों को टी.डी. का अधिकार नहीं है। जंगलों के बारे में माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है यह प्रश्न माननीय राजस्व मंत्री से संबंधित है। क्योंकि यह रेवन्यू का मसला है। जंगल बदले हैं और यह बंदोबस्त का मसला है। मैं भी इस सदन के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो माननीय सदस्य आग्रह कर रहे हैं उस पर आप गौर करें। डिपार्टमैंट को भी मैं इस बारे में निश्चित दिशा-निर्देश दे दूंगा।

17/03/2017/1130/RKS/DC/2

प्रश्न संख्याः 3886

श्री वीरेन्द्र कंवरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको पट्टे दिए गए हैं। सन् 1975 के बाद कुटलैहड़ में कुछ पट्टे दिए गए थे। उस समय फोरैस्ट सुपरिन्टेंडेंट राजा मेहन्द्र पाल जी थे। वे पट्टे उनके द्वारा दिए गए थे। रेवन्यू रिकॉर्ड में इसका इन्द्राज भी हुआ है। इसमें काश्तकार भी लगे हुए हैं। अब यह तीसरी पीढ़ी चली हुई है परन्तु वे अभी तक मालिक नहीं बने हैं। मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि जिन लोगों को अलॉटमैंट्स हुई , रेवन्यू रिकॉर्ड में उनकी एंट्री है, क्या उन लोगों को मालिकाना हक मिलेगा? नम्बर दो, रेवन्यू डिपार्टमैंट ने भी उस समय पट्टे दिए थे। रेवन्यू डिपार्टमैंट में जो पट्टाधार थे अब उनके खिलाफ एनक्रोचमैंट की मिशल्ज़ बन रही है। क्या वे जहां पर स्थापित हैं वहीं पर उनकी कॉरैक्शन कर दी जाएगी।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

17.03.2017/1135/SLS-DC-1

प्रश्न संख्या : 3886 ....क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : स्पीकर सर, यह बात ठीक है कि राजा महेन्द्र पाल सिंह कुटलैहड़ फोरैस्ट का सुपरिटैंडैंट फोरैस्ट था। He was just like a DFO. जो हमारे DFO होते हैं, वैसा ही था। साथ में वह उस जंगत का मालिक भी था। लेकिन जैसे ही 'Ceiling of Land Holdings Act ,1972' लागू हुआ, उसके तहत यह सारी भूमि along with the forest that vests with the State Government. हमने इसमें सारा रिकॉर्ड चैक किया है। There is no evidence to show that some competent authority has given them the possession of this land. I agree with you that there is a entry in the Jamabandi, which shows that they are in possession of the land. Of course

the Jamabandi constitute the part of record of rights and presumption of truth is a attched to the record of rights. We have two alternatives either to dispose of them as encroachers or we can take sympathetic decision and allow them to find out some way how we can give ownership rights to them. **This matter is under the active consideration of the State Government.**

श्री वीरेन्द्र कंवर : माननीय अध्यक्ष जी, जो रैवन्यु ने पट्टे दिए हैं और इन भूमिहीन लोगों को जो पट्टे दिए गए हैं उनके द्वारा ये वहां पर बसा दिए गए। अब रैवन्यु रिकॉर्ड बता रहा है कि उनकी जगह वहां नहीं, किसी दूसरे स्थान पर है। उन्होंने वहां पर मकान बना लिए हैं और वे वहां पर भूमि भी जोत रहे हैं। में आपसे यह आश्वासन चाहता हूं कि उनकी करैक्शन करके, जो जहां पर हैं, उनको वहीं पर स्थापित कर दिया जाए। साथ ही, जो कुछ डैम आउस्टीज थे, जिनको वहां पर ज़मीनें दी गई थीं, उनके साथ भी वैसा ही हुआ। उनकी भी अब एनक्रोचमैंट की मिसिल्ज बनी हुई हैं। मैं यह चाहता हूं कि इन दोनों केसिज में, उनके ख़िलाफ़ जो एनक्रोचमैंट की मिसिल्ज बनी हैं, सरकार उन मिसिल्ज को वापिस ले और लैंड रिकॉर्ड में उनकी भूमि को करैक्ट कर दिया जाए।

17.03.2017/1135/SLS-DC-2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये सिर्फ़ 8 व्यक्ति हैं जिनके नाम मैंने इसमें दिए हैं। इन 8 व्यक्तियों की रैवन्यु रिकॉर्ड में पौजैशन के कॉलम में एंट्री है। इनके बारे में सरकार विचार करेगी।** मैंने कहा कि हमारे पास दो तरीके हैं। या तो उनको बेदख़ल करें because they were not provided possession by some competent authority. उनके पास पट्टे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी **सरकार सीमांत एवं मझौले किसानों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, अगर उनके पास कोई और ज़मीन नहीं होगी तो सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उस एरिया में सैटलमैंट हो रहा है। सैटलमैंट में भी वह रिकॉर्ड हो जाएंगे, चाहे नाजायज कब्जे के रूप में होंगे या जैसे भी होंगे। इस पर सरकार विचार करेगी। जहां तक आप दूसरी बात कर रहे हैं कि कुछ और लोग हैं जिनको वहां ज़मीन मिली थी जबकि**

पटवारी ने कब्जा कहीं दूसरी जगह पर दिखाया है, उन मामलों में भी देखेंगे। अगर वह एक्सचेंज का केस बनता होगा तो एक्सचेंज के केस में भी हम उनको रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। **These cases will be decided purely on merit and in accordance with the Rules and Law.**

श्री वीरेन्द्र कंवर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि वहां पर कुछ डैम आउस्टीज हैं जिनको उस समय ज़मीन अलौट हुई थी। पहले वाले केस की ही तरह इसमें भी रैवन्यु वालों ने बताया कि आपकी ज़मीन यहां है और वे वहां पर स्थापित हो गए। उन्होंने वहां पर गौशालाएं बना लीं और मकान भी बना लिए। लेकिन अब रैवन्यु डिपार्टमैंट ने उनको एनक्रोचर्ज़ करार दे दिया। उनको कहते हैं कि आपकी ज़मीन यहां नहीं बल्कि दूसरे नंबर में है। क्या आप ऐसे केसिज में भी कोई नीतिगत फ़ैसला लेंगे कि उनको रिलीफ दी जाएगी।

Health and Family Welfare Minister: Speaker Sir, I don't have this information with me because this is not relevant to the present question. ये प्रश्न पट्टेदार का था। अब जो प्रश्न माननीय सदस्य पूछ रहे हैं यह किसी और का पूछ रहे हैं जिनको

जारी .. श्री गर्ग जी

17/03/2017/1140/RG/AG/1

प्रश्न सं. 3886---क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्री---जारी

कोई जमीनें उन्हें नौतोड़ में मिली थीं और उन्होंने कब्जा किसी और जगह पर किया है। अगर माननीय सदस्य उनके बारे में अलग से प्रश्न करेंगे और उनके नाम वगेरह बताएंगे, तो सरकार उस पर फिर विचार करेगी keeping in view the Revenue Law into consideration.

17/03/2017/1140/RG/AG/2

प्रश्न सं. 3887

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विभागीय उत्तर के अतिरिक्त यहां इनको यह भी बताना चाहूंगी कि गगरेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए 16 नलकूप बोर किए गए थे जिनमें से 8 नलकूपों का कार्य पूर्ण करके सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है तथा शेष 8 नलकूपों को पर्याप्त बजट न होने के कारण कार्यशील नहीं किया जा सका। फिर भी हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा-से-ज्यादा इनके क्षेत्र के लिए कर सकें, तो अच्छा है। इसलिए इन 8 नलकूपों को सिंचाई के लिए प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत शैल्फ में 3.60 करोड़ रुपये की योजना को सम्मिलित किया गया है। इसे भारत सरकार को भेजा गया है और इसकी स्वीकृति अपेक्षित है। इसके पश्चात वर्तमान में जिला ऊना में नलकूप पर आधारित 524 उठाऊ सिंचाई तथा 196 उठाऊ पेयजल योजनाएं हैं और गत चार वर्षों से इन योजनाओं के रख-रखाव के लिए 26.77 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस विवरण से माननीय सदस्य को सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। यदि माननीय सदस्य कुछ और पूछना चाहें, तो पूछ सकते हैं।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं क्योंकि बड़ेरा, दओली, कैलाशनगर (नकडोह), ऑयल, शिवबाड़ी-1 एवं 2 योजनाओं को दस वर्ष हो चुके हैं। ये ए.आई.वी.पी. से टैस्टिंग बोर के रूप में कील गई थी। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इनको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भेज दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितने समय में ये हो जाएंगी? क्योंकि इनको दस वर्ष तो पहले ही हो चुके हैं। पिछली बार भी चुनावों का मुद्दा यही था और इस बार भी लोग पूछ रहे हैं कि इन नलकूपों को आप कब बनाएंगे? ये बोर तो कर दिए हैं और हर जगह ढक्क्न ऊपर लगाकर बैल्ड कर दिया गया है। क्या चुनावों से पहले इनके लिए फण्ड्ज मिल जाएंगे?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बता सकती हूं कि जो यह प्रस्ताव जो भेजा गया है, अगर इनको चाहिए, तो वह इनको दे देंगे। हम कब तक इसको तैयार कर सकेंगे, यह देखने वाली बात है। आप थोड़ा विश्वास रखिए, मैं इनको कह रही हूं।

17/03/2017/1140/RG/AG/3

श्री राकेश कालिया : क्या इसको कितने निर्धारित समय में पूर्ण कर लेंगे।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको कहना चाहूंगी कि इन प्रोजैक्ट्स को कम्पलीट करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा कोशिश है कि हम इसको जल्दी-से-जल्दी कम्पलीट करें। ये हम पर विश्वास रखें।

17/03/2017/1140/RG/AG/4

प्रश्न संख्या : 3888

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि सिचुएशन पहले से इंप्रूव हुई है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन फिर भी सिविल अस्पताल, सरकाघाट में डॉक्टर्ज के 15 पद सृजित हैं और अभी वहां 10 पद भरे गए हैं। उसमें से 5 विशेषज्ञ हैं। लेकिन जो स्पेशलिस्ट्ज नहीं हैं, they are more important. गायनॉकॉलॉजिस्ट, मैडिकल स्पेशलिस्ट, ई.एन.टी. स्पेशलिस्ट और एनैस्थीसिया देने वाला डॉक्टर नहीं है। मैं चाहूंगा कि यदि इसमें से गायनॉकॉलॉजिस्ट और मैडिकल स्पेशलिस्ट जल्दी-से-जल्दी से पोस्ट करने की कृपा करेंगे, तो माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त जो पैरा मैडिकल स्टाफ है उसमें लैब टैक्नीशियन का एक पद सृजित है जो भरा हुआ है, लेकिन पूरे अस्पताल में इतनी बड़ी जनसंख्या को यह कैटर करता है उसमें एक ही लैब टैक्नीशियन है और यदि वह छुट्टी पर चला जाए या किसी कारण अनुपस्थित हो जाए, तो फिर सारे अस्पताल का काम ठप्प हो जाता है। इसलिए चीफ लैब टैक्नीशिन का पद जो रिक्त है उसको भरने की कृपा करें। साथ में जो पी.एच.सीज. है ओवर फ्लो भी इन पर जाता है और

9 पी.एच.सीज. में से चार पी.एच.सीज में डॉक्टर नहीं है। यदि वहां डॉक्टर्ज नहीं हैं, तो इसी अस्पताल पर लोड बढ़ेगा। तो क्या इन चार पी.एच.सीज. में भी डॉक्टर्ज को पोस्ट करने का कष्ट करेंगे।

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2017/1145/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3888 क्रमागत--------

Health & Family Welfare Minister: Speaker, Sir, at least I am thankful to the Hon'ble Member. He is very honest and conveyed his thanks to the department. As you know we are shortage of Doctors. We are shortage of Post Graduate Doctors. In spite of that, we have posted five Post Graduate Doctors in his Civil Hospital because I know the catchment area of that area is much more. We are constructing a huge building costing about Rs. 12 crores for Civil Hospital, Sarkaghat. We have posted about 120 Doctors. I know in your three PHCs we have also posted Doctors. The post of Chief Lab Technician is very important. There is one Lab Technician. There is overall shortage of paramedics also in the Health Department. We are taking up the matter with the Finance Department and we will try that within 4-5 months all the posts of paramedics are also filled. Otherwise also every post i.e. paramedics, Staff Nurses and Ward Sisters, is filled up in your hospital. As soon as Medical Specialist and Gynaecologist are available to us, definitely I will try to accommodate.

17/03/2017/1145/MS/AG/2

प्रश्न संख्याः 3889

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदया ने सूचना दी है इसमें मेन तीन बातें बताई हैं, जिनमें पहली, dispute at site. दूसरी, आरबिट्रेशन केस और तीसरा बता दिया additional funds required. मुझे लगता है कि ये तो विभाग का एक्सक्यूज है। जो dispute at site है उसको सोल्व करना चाहिए। इसी तरह से आरबिट्रेशन केस में भी कोई स्कीम बन्द नहीं होती है। आरबिट्रेशन केस चलता रहेगा और स्कीम का काम भी चलता रहना चाहिए। जो वर्ष 2007-08 की स्कीमें हैं उनको चले हुए 10 साल का समय हो गया है। उनके लिए एडिशनल फण्ड्ज अरेंज होने चाहिए। इस बारे में मैं दो-तीन बातें पूछना चाहूंगा। पहला, जो नालागढ़ की स्कीमें बताई गई हैं इनमें तीन स्कीमों में बता दिया है कि dispute at site. मैं जानना चाहता हूं कि जो झगड़ा है वह क्या है तथा कब तक सुलझा लिया जाएगा? दूसरा, नालागढ़ चुनाव क्षेत्र की तीन और स्कीमें हैं जिनका इसमें नाम ही नहीं लिखा है। मुझे लगता है कि आपको बता दिया होगा कि ये स्कीमें पूरी हो गई हैं जबकि वास्तव में ये स्कीमें पूरी नहीं हुई हैं। इन तीन स्कीमों के नाम हैं-पहली स्कीम; एल0आई0एस0 रामपुर-बसवाला-मंगता-प्लासी, दूसरी स्कीम; एल0आई0एस0 ढांग-अप्पर कंदरवाल और तीसरी स्कीम; एल0आई0एस0 गझैड़ हैं। ये तीन स्कीमें हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि जो आपके पास विभाग की सूचना होगी उसमें लिखा होगा कि ये स्कीमें कम्पलीट हो गई हैं जबकि ये कम्पलीट नहीं हैं। मैं स्वयं साइट पर जाकर आया हूं और लोगों की बार-बार डिमाण्ड है कि इनको कम्पलीट करके चलाया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि जो इन तीनों स्कीमों का झगड़ा है वह कब तक सुलझा लिया जाएगा? इनका लैटेस्ट स्टेट्स क्या है तथा कब तक इनको पूरा कर दिया जाएगा? क्या इनके बारे में माननीय मंत्री जी कोई आश्वासन देंगी?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जो इनकी 50 योजनाएं हैं उनकी शैल्फ एप्रूव्ड हैं in the State under AIBP during 2007-2008, 2010-2011 and 2013-2014 but are incomplete due to non-availability of sufficient budget. In order to complete the balance work these schemes are being proposed under other heads and sectors उनके लिए किया

17/03/2017/1145/MS/AG/3

जा रहा है। जो तीन ईरीगेशन स्कीम्ज हैं these are also in Nalagarh constituency and are incomplete. I understand that. Due to dispute at site the work of these schemes can be completed on settlement of dispute for which efforts are being made. So, you will have to see. I want to say one point. खासकर आपको जैसे लग रहा है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

17.03.2017/1150/जेके/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3889ः-----**जारी**------

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः-----**जारी**-----

Hon'ble Chief Minister has allocated Rs. 60.00 crore for completion of incomplete Irrigation Schemes, we will see if these schemes can also be covered. We will try and see if we have some more water schemes,हम कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पानी की स्कीमें हैं, परन्तु कई जगह पैसे की जब कमी होती है तो उसमें हमें दिक्कत आ रही है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। **We will try to that.**

श्री के0एल0 ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मुझे रिप्लाई तो नहीं मिलेगा, परन्तु मैंने एक बात मंत्री महोदया से पूछी थी कि तीन स्कीमों का इसमें नाम नहीं है और जिनको मैंने यहां पर पढ़ा तो क्या उनके बारे में मंत्री जी फील्ड से रिपोर्ट मंगवाएंगे? उनको कम्पलीट करने का कोई आश्वासन देंगे। वह तीन स्कीमें कम्पलीट नहीं है। मैं डिस्प्यूट की बात नहीं कर रहा हूं। जो तीन स्कीमों के नाम मैंने यहां पर बताएं हैं, जो आपके रिप्लाई में नहीं दिए गए हैं।

उन तीन स्कीमों की फील्ड से रिपोर्ट मंगवा कर और जो-जो उसमें बैलेंस वर्क हैं उनको करके स्कीमों को कब तक फंक्शनल करेंगे? क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः हमने वही तो बात की है। उसी के लिए हम बन्दोबस्त कर रहे हैं।

श्री के0एल0 ठाकुरः मैडम उन तीन स्कीमों का इसमें नाम नहीं है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः यदि आपको नाम चाहिए तो मैं आपको स्कीमों के नाम दोबारा से लिखा देती हूं। हम आपको कह तो रहे हैं । आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्कीमों को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए और बिना पैसे के तो काम नहीं होता। वही हमारे प्रॉबलम है। You better be careful. हम आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं।

श्री के0एल0 ठाकुरः माननीय मंत्री जी इसमें स्कीमों के नाम नहीं है। ....(व्यवधान).....

17.03.2017/1150/जेके/एएस/2

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः मैं आपको स्कीमों के नाम दे देती हूं। आपको तसल्ली हो जाएगी।

श्री के0एल0 ठाकुरः माननीय मंत्री जी आपने मुझे नाम नहीं देने हैं मैंने आपको स्कीमों के नाम बताने है। ....(व्यवधान).....

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय सदस्य आप हमारी बात को सुन तो लीजिए। आप आराम से बैठ जाएं। जो आपकी तीन स्कीमें हैं जो कि मैंशन्ड हैं which shall also be completed जिनका नाम है। LIS Bansai लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, LIS Khera Nanowal and LIS Sirsa Manjholi. ये तीनों स्कीमें हैं आप क्यों चिन्ता कर रहे हो? अगर तीन और होंगे तो कर लेंगें लेकिन अभी तो जो ये तीन है इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है।

Speaker: Hon'ble Member, you can give three names to the Hon'ble Minister. माननीय सदस्य आप माननीय मंत्री महोदया को स्कीम के तीन नाम दे दें। She will consider it.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री: हमने आपको ईमानदारी से सच्चाई से सब कुछ बता दिया। ....(व्यवधान).....

अध्यक्ष: आप लिख कर तीन नाम दे दीजिए।--(व्यवधान)-- ठीक है आप बोल दीजिए।

श्री के0एल0 ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, जो तीन स्कीमें हैं जो इसमें अपीयर नहीं हुई वे इन्कम्पलीट है और इसमें उनके नाम नहीं है। उनके नाम मैं आपको लिखाना चाहता हूं। एल0आई0एस0 रामपुर पसवाला मंगता प्लासी, एल0एस0 ढांगऔफर चंगरवाल और एल0एस0 बछेड़। ये तीन स्कीमें हैं जिसको आपने कम्पलीट बताया है लेकिन साईट में इन्कम्पलीट है और फंक्शनल नहीं है। फील्ड से इनकी रिपोर्ट मंगवा कर इनको कम्पलीट करें। इसमें थोड़ा-थोड़ा काम बचा है ताकि लोगों को लाभ मिल सके। इसमें बड़ा कम पैसा लगा है। पैसे की कोई समस्या नहीं है।

17.03.2017/1150/जेके/एएस/3

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री: जिन तीन स्कीमों की आप बात कर रहे हैं, इनको एस.ई. देखेंगें। हम आपको चारों स्कीमें दे देंगें। आप तसल्ली रखें । काम तो समय से ही होगा। फंड्ज़ की बात होती है, बिना फंड्ज़ के कोई काम नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं। कम्पलीट करने का समय दे दीजिए। आपने अभी तक तो बात ही नहीं की है। आपने पहले भी एक बार कहा था तो मैंने बोल दिया आपकी पूरी स्कीमों को हम ठीक करवा देंगें। Honestly I am talking to you.

अगला प्रश्न श्री एस.एस. की बारी में..।

17.03.2017/1155/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 3890

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो सूचना इन्होंने सभापटल पर रखी है उसके मुताबिक कुल 20 में से 8 पद आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रिक्त पड़े हैं। उनको इन्होंने 10.3.2017 को भरने के आदेश दे दिये हैं। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। परन्तु अभी तक कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक आया नहीं है, मैं चाहूंगा कि इसके लिए दोबारा से आदेश किये जाएं ताकि ये पोस्टें भरी जाएं।

जहां तक रोहड़ू आयुर्वेद अस्पताल की बात है मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इसका कार्य काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ है और क्योंकि अब यह भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड शिमला में आ रहा है, वहां पर हमारी पकड़ नहीं है। मैंने भी वहां कई बार प्रयत्न किया लेकिन वे मेरे को यह कहकर टालते रहे कि इसका कार्य जल्दी-से-जल्दी होगा। मैं चाहूंगा कि विभाग के माध्यम से इसका कार्य जल्द-से-जल्द शुरू करने के आदेश किये जाएं। माननीय मंत्री महोदय, हमारा रोहड़ू आयुर्वेदिक अस्पताल प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, वह जगह भी ठीक नहीं है। इसलिए इस कार्य को करना का आदेश दिया जाए, यही मेरा आग्रह है।

सहकारिता मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है, हमने 10.3.2017 को आदेश कर दिये थे कि जो आपकी 8 पोस्टें (आयुर्वेदिक चिकित्सक) खाली थीं, उनको भर दिया जाए। मैं इसको कल ही देखूंगा कि इसमें तुरन्त आदेश हो जाएं।

जहां आपने रोहडू आयुर्वेदिक अस्पताल भवन की बात की है, इसकी टेंडरिंग हो गई है और यह काम बी0एस0एन0एल0 के पास है। इसको भी अति शीघ्र करने के आदेश कर दिये जायेंगे।

प्रश्न समाप्त

17.03.2017/1155/SS-AS/2

Question No.: 3891

Shri Ravi Thakur: Hon'ble Speaker, Sir, I would like to ask the Hon'ble Health and Family Welfare and Revenue Minister about the Boundary Demarcation. Is it a subject of Constituency, District or of the State or Is it not a matter of the State? If yes, than inspite of pursuing the matter with the State Government, Revenue and Home Department, individually by me for last three years, why no step has been taken. The National Commission of Scheduled Tribes also intervening in the dispute and after convening a meeting with the Deputy Commissioners of Lahual & Spite, Kargil and Leh, Secretary (Home) to the Govt. of Himachal Pradesh, I.G. Mandi, Joint Secretary (Home), Government of India and Major Vivek, Major General of India, it was decided that a survey of the spot will be conducted in person. Why, after visiting the spot by the Deputy Commissioner and Superintendent of Police, Lahual & Spiti, Deputy Commissioners of Mandi and Kargil and Surveyor, Major General of India, no step has been taken and even after receiving the directions that money be deposited by both the State Governments? Will the Hon'ble Health and Revenue Minister and Secretary (Home) to the Govt. of Himachal Pradesh, take immediate steps to resolve this issue?

17.03.2017/1155/SS-AS/3

Health and Family Welfare Minister: Hon'ble Speaker. Sir, This is very important issue. An issue of Inter State Boundary Dispute between the State of HP and Jammu & Kashmir at Sarchu and Shinkula (District Lahaul-Spiti) in Sheet No. 52H/1 and 52H/9 came to the notice of the Government during the year 2014. A meeting was held to resolve the issue of Inter-State Boundary dispute at Sarchu on 26th August, 2014 which was attended by the Deputy Commissioner, Lahual & Spiti and the Deputy Commissioner, Leh (Jammu Kashmir). It was decided in the meeting that both sides would exchange the Revenue records available with them alogwith detailed reports, which will be submitted to the respective State Governments.

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2017/1200/केएस/डीसी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी---

3. It was decided in the meeting that both sides shall maintain status qua border dispute till the issue is resolved. During the year, 2015 however, the Police Department of District Leh established a Police Chowki at Sarchu on the area falling within the jurisdiction of District Lahaul & Spiti where Forest Department of Lahaul & Spiti have been granting permission to the inhabitant to establish camping sites and other related business.

4. A representative was made by Sh. Tenzin Sonam, Councillor , Lungnak . LAHDC Kargil, to Sh. Ravi Thakur Hon'ble Vice Chairman, National Commission for Scheduled Tribes, Government Of India related to construction

of Padum - Darcha road and to carryout proper demarcation of the Inter State Boundary between HP and Jammu and Kashmir at Sarchu and Shinkula.

5. On the intervention of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) meeting were held during the year 2015 and 2016 to resolve the Inter State boundary issue between the Disrtrict authorities (i.e. Lahaul & Spiti and Leh) of both the states. In the meeting held on 10-06-2016, the Joint Secretary Ministry of Home Affairs directed Survey of India to demarcate the Inter State border as per the Survey of India maps. Thereafter a joint demarcation date was fixed for 10/08/2016 by the Survey of India and a team of Surveyor General of India visited the spot on the same date in the presence of Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti and Deputy Commissioner, Leh alongwith other Forest and Revenue Officers of the both sides.

6. Thereafter no demarcation report of request for the payment of any amount for the Joint demarcation has been received by the State Government of HP

17.03.2017/1200/केएस/डीसी/2

from the Surveyor General of India in the matter. Therefore the question of making any payment does not arise. The demarcation report has not yet been received from the Surveyor General of India.

Sir, we are concerned about the boundary dispute and Himachal Pradesh Government will take all effective steps that our territory will not be encroached by the other State.

प्रश्नकाल समाप्त

17.03.2017/1200/केएस/डीसी/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह, अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2016-17) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति के 237वें मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 308वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम्

ii. विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वन विभाग से सम्बन्धित है;

iii. समिति के 200वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि आवास विभाग से सम्बन्धित है; और

iv. समिति के 277वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 41वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित

अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

17.03.2017/1200/केएस/डीसी/4

अध्यक्षः अब श्री संजय रतन, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगें।

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17),समिति का 69वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जो कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2015 में इंगित ऑडिट पैरा की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री संजय रतन, सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति,(वर्ष 2016-17), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगेः-

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति,(वर्ष 2016-17), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन जोकि पशुपालन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

ii. समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन जोकि वन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

17.03.2017/1200/केएस/डीसी/5

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमानः-

सामान्य चर्चा एवं समापन ।

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा एवं समापन होगा। आज चार ही माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और फिर दोपहर के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगें। अब चर्चा को आरम्भ करते हुए मैं श्री जय राम ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं। Kindly mind your time.

श्री जय राम ठाकुरः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करुंगा कि समय में ही अपनी बात कहूं।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान पर इस माननीय सदन में जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं। इस विधान सभा में मैं भी 20वां बजट प्रस्तुत होते हुए, उस पर चर्चा होते हुए देख रहा हूं। मुझे इस बात का भी सौभाग्य हैं कि 20 के 20 बजट अभिभाषणों के सम्बन्ध में अपनी बात करने का हमें अवसर मिला है । यह बजट वर्तमान सरकार का अन्तिम बजट है

श्री टी0सी0वी0 द्वारा जारी----

17/03/2017/1205/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री जय राम ठाकुर..... जारी

क्योंकि इसके पश्चात् विधान सभा का चुनाव होगा, चनुाव के बाद नई सरकार बनेगी और नया बजट उसमें आएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने से बहुत सारे मित्रों ने बात कही- यह बजट ऐतिहासिक है, आज से पहले कभी इस प्रकार का बजट नहीं हुआ और आने वाले समय में भी इस प्रकार का बजट होने की संभावना नहीं है, ऐसे हमने हमारे मित्रों को बोलते हुए सुना। अध्यक्ष महोदय, हम सोच रहे थे कि इस बजट में ऐतिहासिक क्या है? एक प्रयत्न सरकार की ओर से हुआ, क्योंकि चुनाव का वर्ष है और चुनावी वर्ष में कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, जिसको लोग याद रखें, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई समाधान नही निकल पाया। फिर अंत में निर्णय लिया गया कि बजट भाषण को लम्बा कर दिया जाये। इस तरह से इस कार्यकाल में एक इतिहास बना लिया जाये और उस दृष्टि से साढ़े चार घंटे का बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में दिया। हमने एक साल पहले का बजट भाषण भी देखा, वह भी ऐतिहासिक था, इस दृष्टि से क्योंकि वह भी साढ़े तीन घंटे का था, लेकिन अब साढ़े चार साल का कार्यकाल हो गया है, इसलिए बजट भाषण भी साढ़े चार घंटे से कम नहीं होना चाहिए। किसी बजट भाषण को लम्बा करके उसको ऐतिहासिक मानना, मुझे लगता है कि हमारे मित्रों को बहुत बड़ी गलतफ़हमी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में 10 बजट भाषण सत्ता पक्ष और 10 विपक्ष के देखे हैं, लेकिन जब भी बजट भाषण होता है, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि सत्ता पक्ष का कोई भी विधायक/मंत्री सदन छोड़कर बाहर जाता हों, जब तक भाषण समाप्त नहीं होता है। यह बजट भाषण इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक है, विपक्ष की तो बात छोड़िए, इतना नीरस भाषण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया, सत्ता पक्ष के विधायक को तो छोडिए, मंत्री भी सदन में बैठने, उसको झेलने की स्थिति में नहीं रहे, वे भी सदन छोड़कर बाहर चले गये। उसको भी इतिहास में रखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े आंकड़ों में जाने का मेरा स्वभाव नहीं है और मेरा अर्थशास्त्र बहुत कमज़ोर रहा है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से सहमत हूं कि सरल तरीके से अगर बजट को समझना है, तो उसके पैरा 160 में ज़िक्र किया गया है कि अगर आपके पास एक रूपया है, तो उसमें से कितना पैसा

17/03/2017/1205/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

कहां से आएगा और कैसे उसको खर्च किया जाएगा? उसको सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न होता है। अध्यक्ष महोदय, बजट अनुमानों के अनुसार जो पैरा 160 है, जिसका मैंने यहां ज़िक्र किया है, उसमें कुल प्राप्तियां 77 रूपये 45 पैसे की होगी और जो 22 रूपये 55 पैसे का अंतर रह जाएगा उसको ऋण के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसमें भी जो प्राप्तियां होगी, उसमें भी केन्द्र सरकार के करों का हिस्सा 17.39 रूपये हैं।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

17/03/2017/1210/ एन0एस0/ए0जी0/1

श्री जय राम ठाकुर---- जारी

अगर हम केंद्र सरकार के अनुदान की बात कहें तो 48.16 रूपये का हिस्सा बनता है। अगर हम इसको कुल मिला करके देखें तो लगभग 65 रूपये बन जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण में जिक्र किया गया है कि 22.55 रूपये ऋण लेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें तो लगभग 88 प्रतिशत से ज्यादा केंद्र की मदद और ऋण से इस बजट के प्रावधान का जुगाड़ किया गया है। हम ऐसा बोल सकते हैं। यहां पर हम लम्बे भाषण पर चर्चा कर रहे हैं और लम्बी बातों का जिक्र कर रहे हैं, वह सिर्फ 12 प्रतिशत का ही ऋण है। अध्यक्ष महोदय, जब बजट प्रावधानों का जिक्र होता है तब कुछ संवैधानिक व्यवस्था वाली बातों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। अगर हम आर्टिकल-393 के सबसैक्शन 3 का जिक्र करें, तब उसमें हर प्रदेश के लिए ऋण की सीमा निर्धारित होती है कि आप ऋण लेने की सीमा में कहां तक जा सकते हैं? वर्तमान सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार उस सीमा का उल्लंज्ञन करते हुए उससे पार जाती रही है। आर्टिकल 293 सबसैक्शन 3 के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में इस सरकार का ऋण लेने का अधिकार 2448 करोड़ रूपये का

था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 4011 करोड़ रूपये का ऋण लिया। अर्थात 1563 करोड़ रूपये की राशि ज्यादा ली। जो सीमा निर्धारित थी उससे ज्यादा लिया गया। अगर हम वर्ष 2014-15 की बात करें तब फिर से ऋण लेने की सीमा का उल्लंज्ञन किया गया। 2786 करोड़ रूपये की राशि आप ले सकते थे लेकिन उसके बावजदू भी आपने 4200 करोड़ रूपये की राशि ली। 1414 करोड़ रूपये की राशि आपने ज्यादा ली। आप अपनी लिमिट को क्रोस कर गए। इसी प्रकार अगर हम वर्ष 2015-16 की बात करें तो ऋण लेने की सीमा 3156 करोड़ रूपये की बनती थी लेकिन इसके बावजूद ऋण 3284 करोड़ रूपये का लिया गया। अर्थात 128 करोड़ रूपये का ज्यादा ऋण लिया गया। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से वर्ष 2016-17 में ऋण लेने की बात आती है तो आर्टिकल 293 सबसैक्शन 3 के अन्तर्गत ऋण की सीमा 3540 करोड़ रूपये की थी लेकिन आपने 4075 करोड़ रूपये का ऋण लिया। अगर हम देखें तो लगातार चार वर्षों में सीमा उल्लंज्ञन करके 5000 करोड़ रूपये का ज्यादा ऋण लिया गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि केंद्र में नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार है। हिमाचल एक छोटा-सा प्रदेश है लेकिन इसके बावजूद इस प्रदेश को मदद देने के लिए उन्होंने कभी किसी रूप में कमी नहीं छोड़ी है। स्पैशल कैटेगिरी स्टेट के नाते और अन्य कारणों की वजह से भी उन्होंने कोई कमी नहीं

17/03/2017/1210/ एन0एस0/ए0जी0/2

छोड़ी है। हमें इस बात की खुशी है। आने वाले समय में 72,000 करोड़ रूपये की राशि पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। हमारे सामने वाले मित्र (सत्ता पक्ष) केंद्र की सरकार को पानी-पानी पी करके कोसते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम सत्ता पक्ष में थे तब ये विपक्ष में थे और तब हर माननीय सदस्य खड़ा हो करके एक ही बात कहता था कि अगर यू0पी0ए0 की सरकार (केंद्र सरकार) आपकी मदर न करे तो आप दो कदम चलने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर हम इस बात का जिक्र करें कि केंद्र की सरकार आपको जिस रूप से मदद कर रही है, उस प्रकार से मदद न करे तो आप दो क्या एक कदम भी चलने की स्थिति में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी यहां पर धन्यवाद करने का सिलसिला खत्म है। (व्यवधान)

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

17/03/2017/1215/RKS/AG/1

श्री जय राम ठाकुर...जारी

हमने किया है, कई बार किया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर धन्यवाद करने का रिवाज़ खत्म है। रिवाज़ किस वजह से खत्म है, क्योंकि एहसान याद नहीं रखा जाता। यहां पर एक बात का जिक्र किया जाता है कि दूसरी राजधानी घोषित कर दी गई। मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए अपनी बात कहने की कोशिश की थी। हम इस बात को समझ नहीं पाए कि दूसरी राजधानी का क्या अर्थ है? शिमला वालों के लिए तो दूसरी राजधानी का अभिप्रायः यह है कि पति जब दूसरी शादी करता है और पत्नी के मन में जो सौतन का भाव होता है, वैसा ही है। हम क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें चुनाव से पहले क्यों याद आती हैं? हमारा प्रदेश 68 विधान सभा क्षेत्रों का एक छोटा सा प्रदेश है। यहां पर दूसरी राजधानी की घोषणा की गई। धर्मशाला में आनन-फानन में विधान सभा बनाई और उद्घाटन भी कर दिया गया। उसके बाद जब विधान सभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहला शपथ-ग्रहण धर्मशाला की विधान सभा के अंदर होता है। जिस नैतिक दृष्टि से आप सोच रहे थे, उसका लाभ आपको नहीं मिला। हम यह उम्मीद कर रहे थे कि आप इससे कुछ सिखेंगे। लेकिन आपने नहीं सीखा। इसी प्रकार से इस राजधानी का भी यही नतीजा आने वाला है। दूसरी राजधानी का क्या अभिप्राय है? क्या यह राजधानी 365 में से 360 दिन बंद रहेगी और 5 दिन के लिए खोली जाएगी? जैसे 6 महीने श्रीनगर में और 6 महीने जम्मू में राजधानी रहती है, क्या यहां पर भी आप ऐसे ही दरबार मूव करेंगे? क्या आप धर्मशाला में मात्र राजधानी का फटा लटकाकर जाएंगे? क्या यह इतने तक ही सीमित होगी? क्या धर्मशाला में जो हमारे अधिकारी/कर्मचारी रहते हैं उनको उसी तर्ज पर कैपिटल अलाउंस दिया जाएगा, जैसे शिमला में दिया जाता है? यह बहुत सारे विषय हैं जिन बातों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं? वक्त निकल जाएगा और आप जवाब नहीं दे

पाएंगे। दूसरी बात यह है कि किसको गुमराह किया जा सकता है? 'चुनाव घोषणा पत्र' में जिक्र किया गया कि बेरोजगारों को बरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। कुछ नौजवान गुमराह हो गए। सरकार

17/03/2017/1215/RKS/AG/2

बनी और सरकार बनने के बाद कह दिया गया कि हमने बेरोजगार भत्ते की बात नहीं की है। From the day one प्रदेश बेरोजगार भत्ता देने की स्थिति में नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात अनेकों बार सदन और सदन के बाहर कही है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह भत्ता आपको देना पड़ेगा और यह हमारी ऑनेस्ट कमिटमैंट है। आप उसम समय पार्टी अध्यक्ष थे और पार्टी अध्यक्ष के नाते यह सारी बातें आपके सामने डिस्कस हुई है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अनुभवहीन लोगों ने यह घोषणा पत्र बनाया है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।जब बजट प्रस्तुत किया गया तो बेरोजगारी भत्ता दे दिया गया। दुनिया को तो आपने झूठ बोला परन्तु अपनी पार्टी के नेताओं के साथ भी आपने सत्य नहीं बोला। उनको भी आपने गुमराह किया। क्योंकि प्रश्न पैदा यह हो रहा था कि श्रेय पार्टी को नहीं जाना चाहिए, श्रेय मुझे जाना चाहिए। इसलिए पार्टी के लोगों को भी नहीं बताया गया कि हम क्या कर रहे हैं? बजट भाषण में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान बेरोजगारी भत्ते के लिए किया गया। लगभग 12 लाख बेरोजगार हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। क्या 150 करोड़ रुपये से बेरोजगारी भत्ता पूरा हो सकता है? हम आपकी मंशा से वाकिफ है और आपकी इस मंशा से हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को भी वाकिफ करवाएंगे। मात्र एक महीने के लिए आप यह जुगाड़ कर रहे हैं। यह जुगाड़ का इंतजाम है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

श्री जय राम ठाकुर....जारी

मुख्य मंत्री जी कई दिनों से कह रहे थे कि मैं जुगाड़ से सरकार बना रहा हूं और जुगाड़ से ही चला रहा हूं। उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। जो जुगाड़ आप कर रहे हैं, इस बार यह उलटा पड़ेगा। आप कितनी बार किसको गुमराह कर सकते हो? You can befool one person all the time but you cannot befool all the persons all the time, ऐसा बोला जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने के मित्र सिर्फ़ चुनावी दृष्टि से लाभ लेने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं। इसमें सफलता हासिल नहीं हो पाएगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया कि हमने बहुत से संस्थान खोले हैं। संस्थानों का क्या ज़िक्र करें? कहा कि हमने 1328 स्कूल अपग्रेड किए, नए स्कूल खोले गए, 42 डिग्री कॉलेज खोले, 21 सिविल हॉस्पिटल, 24 सी.एच.सी., 96 पी.एच.सी और 29 हैल्थ सब-सैंटर्ज़ खोले। अध्यक्ष महोदय, संस्थान खोलना एक बात है, उन्हें चलाना दूसरी बात है। वर्तमान सरकार की एक नीति, एक नियम बन गया है, नज़रिया बन गया है कि संस्थान खोलते जाओ और जब उन्हें चलाने की बारी आएगी, तब तक हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और वह इस झमेले को देखेंगे। ...(व्यवधान...अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने मित्र मुकेश जी पर बहुत अफ़सोस हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन संस्थानों को लेकर जब हम यहां से पूछते हैं तो मंत्री और मुख्य मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि हमने पद सृजित कर दिए हैं। पोस्ट क्रिएट करने के लिए केवल कागज़ लगता है जबकि उसे भरने के लिए आदमी लगता है। हमने इतनी पोस्टें क्रिएट की, यह कहने का क्या कोई मतलब बनता है? आप देखिए कि जहां डॉक्टर होना चाहिए वहां डॉक्टर है या ताला लगा हुआ है। इन सारी बातों पर वर्तमान सरकार नहीं सोच रही है। बस फट्टा लगाने की बात है। फट्टा सरकार। यह स्थिति सचमुच में चिंता का विषय है। इस बार जब फट्टे चक दिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फट्टे से भी गुज़ारा नहीं हो पाया। खोले जा रहे इन संस्थानों को लेकर बहुत से मेरे साथियों ने संसाधनों

17.03.2017/1220/SLS-AS-2

का ज़िक्र किया। संसाधन कहां से आएंगे? आपने 45-50 चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन हारे हुए और नकारे हुए लोग बना रखे हैं। किसी स्कीम का शिलान्यास करने के बाद फिर वे भूमि पूजन करते हैं और अगर भूमि पूजन हो चुका हो तो शिलान्यास करते हैं। विधायक प्राथमिकता तक की योजनाओं का वे उद्घाटन किए जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय इस माननीय सदन में नहीं हैं। मैं पहले भी इस माननीय सदन और प्लानिंग की बैठक में कह चुका हूं, क्या हम इस बात पर सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारा केंद्र सरकार का एक प्रोटोकोल बना हुआ है कि अगर कोई उद्घाटन या शिलान्यास होता है तो वहां का सांसद उसमें निश्चित रूप से शामिल होता है, सरकार भले ही किसी भी पार्टी की हो। उस विधान सभा क्षेत्र के विधायक का नाम भी उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन यहां पर बड़ी विचित्र स्थिति है। मुख्य मंत्री जाते हैं, विधायक प्राथमिकताओं का उद्घाटन करने के लिए वहां खड़े हो जाते हैं और साथ में चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन, जिन्हें हमने हरा रखा होता है, उनका नाम अवश्य लिखा जाता है लेकिन विधायक का नाम नहीं लिखा जाता। क्या इस बात पर सोचने की आवश्यकता नहीं है? सांसद चाहे किसी भी पार्टी का हो, केंद्र सरकार की नीति के अनुसार उस क्षेत्र में उस सांसद का ज़िक्र शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिका पर होगा। क्या हम यहां इस बात को नहीं सोच सकते कि विधायक का नाम भी वहां पर होना चाहिए? चाहे वह सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है लेकिन उसके बावजूद उस विधायक का नाम उस विधान सभा क्षेत्र में जब उद्घाटन या शिलान्यास होता है तो यह होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत-सी चीजों पर इस तरह से सोचने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान...आप फिर यही कहेंगे कि जब आप थे। मुकेश जी, लोग अब यह देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हमने जो किया, उसको आप याद नहीं रखते।

जारी .. श्री गर्ग जी

17/03/2017/1225/RG/AS/1

श्री जय राम ठाकुर---जारी

अब लोग उस बात को याद रखेंगे जो आप लोग कर रहे हैं। इसलिए इस बात पर भी सोचने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, संस्थान खाली हैं, उनमें अध्यापक नहीं हैं। लेकिन फट्टे टांग दिए गए हैं। अस्पतालों में चिकित्सक नहीं हैं, लेकिन फट्टे टांग दिए गए हैं। इसलिए इन चीजों पर भी सोचने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, यहां मुझे इस बात का जिक्र करते हुए बहुत हैरानी हो रही है क्योंकि हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश ओ.डी.एफ. (Open Defecation Free) राज्य घोषित कर दिया। तो मैं इस बात का पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि हमारा प्रदेश ओ.डी.एफ. होने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्ष 2012 में ही आ चुका था। जो वर्तमान स्थिति है वही उस समय भी हो गई थी। लेकिन उस समय केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार थी और जब हम वहां गए और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के मंत्री से मिला और भारत सरकार के पंचायती राज सचिव से भी मिला। उन्होंने कहा कि सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन ओ.डी.एफ. में रहा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश को ओ.डी.एफ. घोषित कर देना चाहिए। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन अड़ंगा डाला गया कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाएगा और उस समय इसे ओ.डी.एफ. घोषित नहीं किया गया। वर्तमान सरकार ने किया कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि केन्द्र सरकार ने यह भेदभाव खत्म किया। केन्द्र में एन.डी.ए. और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय मंत्री जी आकर इस प्रदेश को ओ.डी.एफ. घोषित करके जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां हम बहुत सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं कि क्षेत्रवाद की बातें नहीं हैं। हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन क्या व्यवहार में वे सारी चीजें हैं? कहना एक बात होती है और करना अलग बात होती है। अध्यक्ष महोदय, सचिवालय में

फ्राश/चौकीदार/माली लगते हैं उनका इन्टरव्यू हुआ। अभी ताजी-ताजी बात है। उसमें कुल 85 पद थे। उसमें कैसे-कैसे पद भरे जाते हैं मैं यहां बताना चाहता हूं। मेरी जानकारी के

17/03/2017/1225/RG/AS/2

अनुसार शिमला जिले से 38, ऊना जिले से मात्र दो, किन्नौर से दो, सिरमौर से दो और कांगड़ा जो हमारी दूसरी राजधानी है जहां 15 विधान सभा क्षेत्र पड़ते हैं और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वह जिला है वहां से कुल तीन फ्राश मिले। कांगड़ा वाले बधाई के पात्र हैं। उसके बाद बिलासपुर जिले से सात, सोलन से 9, कुल्लू से तीन, हमीरपुर से चार, मण्डी से 12, लाहौल-स्पीति से एक, चम्बा से एक की भर्ती हुई। अब आप ही बताइए कि कांगड़ा वालों को इस बात को सोचना है कि यह फट्टे वाला काम है। आपको फट्टा लगा दिया, आप उसको देखते रहिए और खुश हो जाइए। लेकिन उसके बावजूद व्यवहारिक रूप से आपकी किस प्रकार से चिन्ता की जा रही है, इन सारे आंकड़ों से यह सारा पता लग जाता है।

अध्यक्ष महोदय, यहां बागवानी से संबंधित बातें कही गईं। हमको अपने बागवानों को तोहफा देना चाहिए, बागवानों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि जब ऐन्टी हेलगन लगाई गई थी। हमारे आदरणीय धूमल जी ने एक निर्णय लिया था। सेब की जहां अच्छी फसल होती है, लेकिन चंद मिनट में वहां ओलावृष्टि भी होती है, जिसस करोड़ों रुपये का नुकसान वहां बागवानों को होता था। इसके लिए क्या रास्ता निकाला जाए? आज तकनीक को लेकर एक बात ध्यान में आई कि ऐन्टी हेलगन के परिणाम देखे जाएं। ऐसा सुना है कि उसका परिणाम अच्छा है। उस दिशा में सरकार ने कदम उठाया और ऐन्टी हेलगन लगाई गई। उस समय हमारी साथी कहते रहे कि हेलगन, फेलगन, ऐसे नारे इस सदन में लगाते रहे। क्योंकि इन्होंने उसका विरोध किया था और आज भी ये उसका समर्थन करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बागवानों ने अपने पैसे इकट्ठा करके अपनी ऐन्टी हेलगन लगाकर आपको यह सन्देश दिया है कि ऐन्टी हेलगन का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सही था और इनका विरोध करने का निर्णय गलत था। इस बात को सोचने की आवश्यकता है। इसके साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये ऐन्टी हेलनेट की बात कर रहे हैं और

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2017/1230/MS/AG/1

श्री जय राम ठाकुर जारी-------

आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम उसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी देंगे। अरे भाई, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा केन्द्र सरकार का है। आपका उसमें क्या योगदान है? आप कह रहे हैं कि इसको 80 प्रतिशत करेंगे। ठीक है, उस दिशा में आप लोगों ने सोचा लेकिन अध्यक्ष जी, मैंने इसी माननीय सदन में प्रश्न किया था। मैं क्षेत्रवाद की बात का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। उस प्रश्न का जवाब आया कि 5 करोड़ रुपये का पिछले साल के प्रावधान में से 90 प्रतिशत पैसा शिमला जिला में खर्च किया गया और थोड़ा सा पैसा कुल्लू जिला को दिया गया तथा उसके बाद थोड़ा सा पैसा मण्डी जिला को दिया गया। बाकी पूरे हिमाचल में पैसा नहीं दिया गया। वितरण की व्यवस्था देखिए किस प्रकार से है? इन सारी चीजों को देखते हुए हमें विवश होकर कहना पड़ रहा है कि इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। ओला तो मण्डी, चम्बा और कुल्लू में भी पड़ा, सेब वहां भी तबाह हुए लेकिन उसके बावजूद वहां के बागवानों ने एप्लाई करके सारी फॉरमेलिटीज पूरी कीं और अभी तक भी मेरे गांवों के लोगों को एंटी हेलनेट के लिए पैसा नहीं मिला है।

अध्यक्ष जी, अगर 14वें वित्तायोग की बात करें तो हिमाचल पहला प्रदेश है जिसको 14वें वित्तायोग का पैसा सबसे पहले दिया गया। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की एक सोच है। उन्होंने हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को सबसे पहले 300 करोड़ रुपये के लगभग राशि दी। उसके साथ-साथ आज हमें इस बात को लेकर भी सोचने की आवश्यकता है कि सांसद को सांसद निधि मिलती है और विधायक को विधायक निधि मिलती है। यह पहली बार हमारी केन्द्र की सरकार ने सोचा कि पंचायत को पंचायत निधि की तर्ज़ पर 14वें वित्तायोग में पैसे का प्रावधान करना चाहिए। हां, इस बात का जिक्र ये करते रहे कि हमारे बी0डी0सी0 के सदस्य रह गए और हमारे जिला परिषद के सदस्य रह गए। अरे, आपको किसने रोका? यहां पर आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन तो है। उसमें से आप बजट का प्रावधान करते। इस बात का जिक्र पिछली बार भी हुआ लेकिन उसके

बावजूद कुछ नहीं हुआ। इस बार आपने 42 करोड़ रुपये का जिक्र किया लेकिन उसके बावजूद यह पैसा बहुत कम दिया, जितना पैसा हम उस वक्त देते थे। यानी यह पैसा उसके मुकाबले में बहुत कम है।

17/03/2017/1230/MS/AG/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष जी, मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र किए बिना अब अपनी बात को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष जी हमारे मित्रों ने कहा कि डि-मोनीटाइजेशन से बहुत नुकसान होगा और पार्टी खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुझे नहीं लगता की उस तरफ से कोई माननीय सदस्य ऐसे रहा हो जिसने इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन 11 मार्च के बाद सब बन्द है। अब ये ज्यादा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सबकी बोलती बन्द हो गई है। अरे, पांच प्रदेशों के चुनाव थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा और मणिपुर आपके सामने है। -(व्यवधान)- आप एक स्टेट का जिक्र किए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि जो शोर डाल रहे थे कि पार्टी को बहुत नुकसान होगा तो नुकसान किसका हुआ, यह सबको मालूम पड़ गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का विधायक दल एक सेवन सीटर गाड़ी में विधान सभा के लिए जाएगा। ये है डि-मोनीटाइजेशन। पारदर्शिता होनी चाहिए और इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा और उन्होंने करके दिखाया। इसलिए मैं सामने वाले अपने मित्रों से कहता हूं कि आप जितना भी कहें, सारी बातें एक तरफ हैं लेकिन चुनाव के वर्ष में जो आपने यह बजट प्रस्तुत किया है यह सचमुच में किसी भी वर्ग को खुश करने वाला नहीं है बल्कि निराश करने वाला है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इसमें कांग्रेस पार्टी का भी भला नहीं है, प्रदेश के भले का तो सवाल ही नहीं है। मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने इस प्रकार का वातावरण पूरे देश क्या पूरी दुनिया में खड़ा किया हुआ है जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। जहां हमारे साथी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अरे, हरियाणा में

जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और जहां हमारी जमानतें तक जब्त हो जाती थीं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आप आसाम देखिए, वहां हमारे पास खड़े करने के लिए कण्डीडेट नहीं होते थे वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मणिपुर में एक भी भारतीय जनता

17/03/2017/1230/MS/AG/3

पार्टी का मैम्बर नहीं था और आज वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिपीट किया है। उत्तराखण्ड में आपका मुख्य मंत्री दो सीटों से लड़ा और दोनों ही सीटों पर चुनाव हार गया। इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसलिए अध्यक्ष जी, जो बजट पर यहां चर्चा हो रही है, उसमें आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन मैं इस बजट का समर्थन करने की स्थिति में नहीं हूं। धन्यवाद।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

17.03.2017/1235/जेके/डीसी/1

अध्यक्षः अब श्री जगजीवन पाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव(जगजीवन पाल)ः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने 10 मार्च, 2017 को जो बजट पेश किया है उस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, चार-पांच दिन से लगातार चर्चा चल रही है। आदरणीय विपक्ष के नेता, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की भी इसके ऊपर चर्चा सुनी। उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से और विपक्ष की ओर से भी चर्चा सुनी। इन बजट अनुमानों में आदरणीय मुख्य मंत्री

जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश को ध्यान रखते हुए, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और पूरे हिमाचल की समान, स्वार्गीण, एक समान तरक्की को दर्शाते हुए बजट पेश किया है। इसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। 20वां बजट उन्होंने पेश किया है और जो उनका अपना अनुभव है अध्यक्ष महोदय उस पूरे अनुभव को उसमें उतारने की कोशिश की गई है। पूरा साल इसके ऊपर काम किया जाए और हिमाचल प्रदेश को कैसे उन्नति की ऊंचाईयों की ओर आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए इसमें प्रयत्न किया गया है। पता नहीं कि आलोचना करने के लिए आलोचना होती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यजब शुरू करते हैं तो पहले यही करते हैं कि साढे चार घंटे जो बजट भाषण दिया गया उसकी आलोचना करते हैं। कई बार अखबारों में भी आता है। ठीक है, मुख्य मंत्री जी की आयु बढ़ी है और आयु बढ़ने के साथ-साथ तजुर्बा भी बढ़ता है। उसी तजुर्बे के साथ इस बजट को पेश किया गया। साढे चार घंटे तक एक घूंट पानी का नहीं पीया और कई सदस्य इधर-उधर विपक्ष के जा रहे थे तो उन्हें मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि यदि किसी को लघुशंका आई है तो जा सकता है मैं तो पढ़ रहा हूं। उनका इस तरह से खड़ा रहना यह दर्शाता है कि मुख्य मंत्री जी की सेहत कैसी है। कभी-कभी आप सवाल उठाते रहते हैं। आप लोग कहां कामना करते हैं आप तो कुछ और ही सोचते हैं। मैं तो दुआ करता हूं कि मुख्य मंत्री जी की सेहत ऐसी ही रहे। ये 4 घंटे तो क्या 5-5, 6-6 घंटे का भाषण देने की शक्ति इनको भगवान दें। ऐसी हम कामना करते हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

17.03.2017/1240/SS-AG/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) क्रमागतः

आप चिन्ता मत करो जब सातवीं बार आयेंगे तो ये साढ़े चार घंटे क्या छः घंटे भी पढ़ेंगे और बड़ा बजट पढ़ेंगे। आपकी चिन्ता और धड़कने आहिस्ते-आहिस्ते इस बजट को देखने के बाद बढ़ रही हैं। जहां तक पूर्व मुख्य मंत्री, श्री प्रेम कुमार धूमल, विपक्ष के नेता कोई बात कहते हैं तो वह सजती है। आलोचना होती है, हम मानते हैं। लेकिन कल हमने सुजानपुर

के विधायक, श्री नरेन्द्र ठाकुर जी की चर्चा भी सुनी। वे भी मुख्य मंत्री के लिए चर्चा में बोल रहे थे कि यह बजट भाषण आधे घंटे में पढ़ा जा सकता था और कई थोड़ी ऊल-जलूल बातें भी कहीं, जोकि अच्छा नहीं लगता। जिस व्यक्ति के लिए रात-दिन मुख्य मंत्री जी ने एक किया हो और वे जब इस तरफ (सत्ता पक्ष) बैठते थे तो हम लोगों ने भी किया है। अब इतनी बोली बदल जाए तो यह हैरान करने वाली बात है।

इस बजट में आशा वर्कर्ज़ के लिए एक आशा पैदा की है जो घर-घर जाकर हमारी माताओं, बहनों और बच्चों का हाल-चाल पूछती हैं और उनको उसका मानदेय मिलता है। मुख्य मंत्री जी ने उनमें एक आशा पैदा की है। एक हजार रुपया महीने का लगाकर उनमें एक आशा की किरण जगाई है। आप लोग उसकी भी तारीफ नहीं कर रहे हैं तो बड़े दुख की बात है। मैं थोड़ा-सा इतिहास में जाना चाहता हूं कि जब 1998 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उस वक्त एक फरमान आया था। जो हमारे मुख्य मंत्री थे वे तो विधवा, ओल्ड ऐज़ और अपंग पैंशनें लगाते थे लेकिन यह कभी नहीं कहते थे कि उस गांव में कोई मरेगा तो उसके बाद किसी दूसरे को पैंशन लगेगी। लेकिन आपके वक्त एक फरमान आया कि जिस गांव में कोई मरेगा तो दूसरे को पैंशन लगेगी। --(व्यवधान)-- मैं 125 वोटों से हार गया था। उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन फार्म मैं ज़रूर भरता था तो पंचायत में यही बोलते थे कि एक मरेगा तब दूसरे को पैंशन लगेगी। आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री जी, यह सच्चाई है। यह पुरानी प्रथा नहीं थी, यह प्रथा आपके समय से चली थी। वर्तमान मुख्य मंत्री जी जब गांव-गांव जाते थे तो दो वर्ष पहले हमने आग्रह किया कि कुछ

17.03.2017/1240/SS-AG/2

माताएं, बहनें और बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बेटे उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में डेली वेज पर हैं तो उनके बुजुर्गों को भी पैंशन नहीं लगती है क्योंकि पटवारी वापिस भेज देता है। उनकी ज्यादा आमदनी लिख देता है। मुख्य मंत्री जी ने उनके दर्द को समझा और 1200 रुपये प्रतिमाह पैंशन 80 साल से ऊपर आयु के बुजुर्गों को लगाई और जब 7200-

7200 रुपये के मनी ऑर्डर उन लोगों को मिले तो उन बुजुर्गों की खुशी देखने वाली थी। जो व्यक्ति 70 परसैंट से ऊपर अपंग हैं, मंदबुद्धि हैं, उनको भी किसी पटवारी से रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके लिए 1250 रुपये प्रतिमाह पैंशन कर दी है। इस तरीके से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक नया काम करने की कोशिश की है

जारी श्रीमती के0एस0

10.03.2017/1245/केएस/एजी/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) जारी--

और उसमें यह नहीं कहा है कि भाजपा का है, कांग्रेस का है, कम्युनिस्ट है या कोई और है। उसमें कोई पाबन्दी नहीं रखी है और यह मुख्य मंत्री जी का काबिलेतारीफ कदम है। कल हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी जो कि लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, पहला नम्बर बोलने का विपक्ष की तरफ से इनका ही था। उनको पीड़ा है। मैं समझता हूं कि इनको पीड़ा है कि शिमला स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बना? मुझे यह समझ नहीं आता कि ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पर चिल्ला रहे हैं, ये एक तरफ बोलते हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार है और प्रधान मंत्री जी बड़ा काम करने वाले हैं। अरे, धर्मशाला स्मार्ट सिटी बन गई तो उससे आपको क्या चिढ़ हो रही है? वहां का स्मार्ट मंत्री और स्मार्ट सिटी। आप स्मार्ट नहीं है तो हम उसमें क्या करें, हमारा क्या दोष है? अभी जय राम ठाकुर जी कह रहे थे कि दिल्ली से तो बड़ा भारी पैसा मिल रहा है। अगर आपको इतना पैसा मिल रहा है, इतनी आपकी चलती है, प्रधान मंत्री आपके हिन्दुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में हवाई जहाज से दौड़े रहते हैं और आप बोल रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है तो शिमला को भी स्मार्ट सिटी बनवा लो। सोलन या मण्डी को भी बनवा लो, चम्बा को भी बनवा लो, तब मज़ा आएगा । धर्मशाला बनी है उससे आप लोगों को क्यों चिढ़ हो रही है? आप दिल्ली जाओ और वहां से शिमला को भी स्मार्ट सिटी करवा लो। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आजादी के 70 वर्ष के बाद *** आज के अंग्रेज कुछ और किस्म के हैं लेकिन आजादी

के पहले जो यहां इस राजधानी में अंग्रेज राज करते थे, याद रखिए उस समय के *** जो माल रोड़ पर हमारे हिन्दुस्तान के लोगों को चलने नहीं देते थे और यह कहते थे कि "Dogs and Indians are not allowed to enter the Mall Road" *** (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने *** कहा कि वे ऊटी गए, कहीं दूसरी जगह गए, दूसरे प्रदेशों में गए लेकिन उन्होंने राजधानी शिमला को ही चुना इसलिए वे अच्छे थे। *** वे भारतीय जनता पार्टी में हैं। (व्यवधान)

————————————————————————————

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

10.03.2017/1245/केएस/एजी/2

अध्यक्षः रवि जी, आप क्या बोल रहे हैं ? आप इनके बाद बोल लेना।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं वही बोल रहा हूं जो इन्होंने यहां पर कहा है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कहा कि श्री सुरेश भारद्वाज जी *** यह बिल्कुल गलत है। ये पूरी तरह से देशभक्त हैं। याद कर लें 23 जनवरी, 2016 का वह दिन, मझीन का क्षेत्र था जहां माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पब्लिक मीटिंग में कहा था,

श्री टी.सी.वी. द्वारा जारी

————————————————————————————

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

17/03/2017/1250/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

श्री रविन्द्र सिंह... जारी

अंग्रेजों का जमाना था, -(व्यवधान)-

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल): मैंने तो अंग्रेजों की बात की है ये राजा, रजवाड़ाशाही में कहां पहुंच गये? मुझे इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। -(व्यवधान)-

अध्यक्षः आप वाईंडअप कीजिए।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल): जहां तक सुरेश भारद्वाज जी ने और बाकी जो इनके वक्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि दिल्ली से विशेष दर्ज़ा हिमाचल प्रदेश को हासिल है, तो क्या यह विशेष दर्ज़ा पहले नहीं था? पहले हमें जो स्कीमें मिलती थी, वह 90:10 में थी। -(व्यवधान)-

अध्यक्षः आप एक मिनट बैठ जाइये।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, ये आपकी बात भी नहीं सुन रहे हैं और हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं। -(व्यवधान)-

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष जी ने मुझे अलाऊ किया है। -(व्यवधान)-

Speaker: Don't exchange arguments.

17/03/2017/1250/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, माननीय सदस्य, मुख्य संसदीय सचिव हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, उसकी गाड़ी और कोठी में ये चलते हैं और विधान

सभा में लोगों ने इनको भेजा है, शालीनता से बात करने के लिए और जो यहां पर बोला गया है उसके आधार पर ये जो मर्ज़ी बोलें, बोल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की बात कि अंग्रेजों की तारीफ़ की, एक भी शब्द अगर अंग्रेजों की तारीफ़ का मिल जाएगा, तो मैं इस सदन को छोड़ दूंगा और आप भी तैयारी करो कि इस सदन को छोड़ देंगे। -(व्यवधान)- मैंने सदन में कहा है कि अंग्रेजों ने सारा हिन्दुस्तान ढूंढ़ा और उनको शिमला सबसे अच्छा लगा। शिमला से 5 देशों की राजधानी चलती थी। अगर मैं, जो आप राजा साहब, राजा साहब कर रहें हैं, उनके बारे में बात करूंगा कि वे उस व़क्त क्या करते थे? वर्ष 1950 से पहले 1947 में वे कहां थे? तब आपको पता चलेगा। सारे राजे-रजवाड़ों को खत्म करके हिमाचल बना है, तब आप कांगड़ा में थे, आप हिमाचल में नहीं थे। आपको यह बात का मालूम नहीं है। आपने अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तो उनको एक्सपंज़ किया जाये, वरना ठीक बात नहीं होगी। -(व्यवधान)-

अध्यक्षः एक मिनट बैठ जाइये, जब ये लोग (विपक्ष) बोल रहे हैं, तो आप बैठ जाइये। मैं यह कहूंगा कि आपने (श्री सुरेश भारद्वाज) जो लफ़्ज़ नहीं बोले है, उसको एक्सपंज़ करवा देते हैं। जो आपने बात नहीं की है, उसको एक्सपंज़ किया जाता हैं।

17/03/2017/1250/टी0सी0वी0/ए0एस0/4

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल)ः भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे हैं कि 90:10 की रेशों में दिल्ली से पैसा मिल रहा है। क्या ये पहली बार मिल रहा है? ये तो पहले भी मिलता था, जितने प्रधान मंत्री हुए उनके समय में मिला है। आपने थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया था, वह गलत बात है। ये सारी स्कीमों में मिलता था और 14वें वित्तायोग की जो रिपोर्ट आई है, उसमें 32 परसेंट की जगह 42 परसेंट कर दिया है तो यह हमारा हक है, कोई भीख नहीं है। -(व्यवधान)-

अध्यक्षः मैं बार-बार रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि बीच में मत बोलिए। Don't indulge in direct fight.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल): जहां तक धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने की बात है, मेरे ख्याल में पिछले कई वर्षों से जो शीतकालीन प्रवास निचले इलाकों में चल रहा है, उसका भारी फ़ायदा लोगों को हुआ है।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

17/03/2017/1255/ एन0एस0/ए0एस0 /1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) ----- जारी

जो लोग माननीय मुख्य मंत्री जी को शिमला में मिलने नहीं आ सकते हैं, वे वहां पर मुख्य मंत्री जी को आसानी से मिलते हैं। मुख्य मंत्री जी प्रवास पर चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर में जाते हैं, इससे सरकार लोगों को घर-द्वार पर मिलती है। धर्मशाला में जो विधान सभा बनी है उससे वहां के लोगों को फायदा हुआ है क्योंकि वे लोग यहां पर (शिमला) विधान सभा देखने के लिए पहुंचते ही नहीं है। लेकिन जब से धर्मशाला में विधान सभा बनी है तब से भारी संख्या में लोग विधान सभा को देखने आते हैं। मुख्य मंत्री महोदय ने उन लोगों को इसे देखने का एक मौका दिया है। अब उसको अगर दूसरी राजधानी का रूप दे दिया है तो हमारे इन साथियों (विपक्ष) को क्यों तकलीफ हो रही है? अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से यह एक अच्छा फैसला है। यह हो सकता है कि आप लोगों (विपक्ष) ने सोच करके रखा हो कि हम करेंगे तो यह आपके हाथ से मुद्दा चला गया है और आपने इसके ऊपर ढोल पीटना शुरू कर दिया कि यह गलत हो गया है। मैं समझता हूं कि यह कोई गलत फैसला नहीं है। यह बहुत सही फैसला है और हमारे क्षेत्र के लोगों को मुख्य मंत्री जी और सरकार से नजदीक से मिलने का मौका मिलेगा। अगर वहां पर दो या तीन महीने के लिए राजधानी चलेगी तो उससे क्या प्रॉब्लम है। जम्मू-कश्मीर में भी तो चलती है। छः महीने जम्मू में और छः महीने श्रीनगर में चलती है। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें कौन-सी बुरी बात है? (व्यवधान) जिसने राजधानी बनायी है, वह पैसे का भी प्रबन्ध कर

लेगा। आजकल हमारे विपक्ष के साथी बड़े खुश हैं कि यूपी में हमारी सरकार (भाजपा) की सरकार आ गई है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि यूपी में भाजपा की सरकार नोटबंदी की वजह से आई है। मैं कहना चाहूंगा कि यूपी में भाजपा की सरकार नोटबंदी की वजह से नहीं आई बल्कि वहां पर आपने (भाजपा) अपना प्रबन्ध कर लिया और अन्यों को नोटबंदी का प्रबन्ध करने के लिए रोक दिया। आप लोग नोटबंदी की गलतफहमी में मत रहना अगर नोटबंदी की वजह से सरकारें आती तो भाजपा का लोकसभा का उम्मीदवार दो लाख

17/03/2017/1255/ एन0एस0/ए0एस0 /2

वोटों से अमृतसर से नहीं हारता। पंजाब में कांग्रेस की 77 सीटें आई हैं और वहां कांग्रेस की सरकार बनी है और तभी नोटबंदी की वजह से भाजपा की दो सीटें रह गई हैं। माननीय सदस्य जय राम ठाकुर जी बोल रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस वाले सात की गाड़ी में जाएंगे तो आपके दो स्कूटर,मोटर-साइकल में जाएंगे। वे साइकल में भी जा सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज, आप बोलिए।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष वाले गोवा और मणिपुर की बात कर रहे हैं तो यह बात हमारे (सत्ता पक्ष) गले से उतरती नहीं है। हम इस बात को मानते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आई है। वहां पर लड़ाई-झगड़ा चल रहा था तो हो सकता है कि वहां के लोगों ने इस बात का पसन्द नहीं किया हो और तभी वहां पर लोगों ने बदलाव लाया है। गोवा और मणिपुर की सरकार को आप लोगों ने(भाजपा) बड़ी बेईमानी और साजिश से खरीदा है। वहां पर आपने प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या की है। आपने वहां पर गलत तरीके से सरकार बनाने की कोशिश की है और आपने सरकार बना ली है। लेकिन अब देखते हैं कि ये सरकारें कितने दिन चलती हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष : Please don't argue. यह गलत बात है। Let him speak you nare not allowed to speak.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप थोड़ी सख्त आवाज में इन साथियों (विपक्ष) को बोल दो कि इंटरफेयर करने की कोशिश न करें। हमने भी कोई ऐसी बात नहीं की है, अगर कभी कर दी है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। हमारे मनाली के माननीय विधायक बोल रहे थे

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

17/03/2017/1300/RKS/AG/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल):...जारी

कि नोटबंदी से करोड़ों रुपये काले धन के रूप में आए हैं। वे पता नहीं किस अखबार का आंकड़ा दिखा रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली में जाकर वित्त मंत्री व प्रधान मंत्री जी से कहिए कि एक बार प्रेस कॉंफ्रेंस करके बता दें कि कितना काला धन आया है? लोक सभा/राज्यसभा में बता दें कि काला धन कहां से आया है। काला धन एक पैसा भी नहीं आया है। आज भी लाखों की संख्या में पुराने नोट पकड़े जा रहे हैं और यह नोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही पकड़े जा रहे हैं। काले धन के ऊपर बाबा रामदेव जी ने तो बोलना बंद कर दिया है। (व्यवधान)...

Speaker: Please wind-up.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल): सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

Speaker: Don't disturb, let him speak.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल): जहां तक बेरोजगारी भत्ते की बात है, जब तक मुख्य मंत्री जी ने बेरोजगार भत्ता अनाउंस नहीं किया था उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा कार्यकर्ता जहां भी भाषण देता था तो यही

कहता था कि बेरोज़गारी भत्ता कहां गया? अब जब मुख्य मंत्री जी ने प्लस टू से ऊपर के बच्चों को 1000 रुपये और विकलांगों के लिए 1500 रुपये की घोषणा कर दी तो आलोचना शुरू हो गई है। अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। आप चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ेंगे? यह भत्ता हमारे पढ़े-लिखे नौजवानों के लिए दिया गया है। जब वे फॉर्म भरने के लिए बस में जाते थे तो किराये के लिए अपने माता-पिता से पैसे मांगते थे। वे नौजवान अपने माता-पिता के ऊपर बोझ न बने और फार्म भरने के लिए पैसे न मांगे उसके लिए यह एक शुरूआत करने की कोशिश की गई है। यदि यह भत्ता बेरोजगार नौजवानों को मिलेगा तो उसमें आपको क्या तकलीफ़ है? आप किस लिए आलोचना कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि यह भत्ता एक या दो महीने ही मिलेगा। आदरणीय

17/03/2017/1300/RKS/AG/2

मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए इंतजाम किया है और यह भत्ता सभी महीने मिलेगा। आपने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जुगाड़ करते हैं। जैसा जुगाड़ गोवा और मणिपुर में हुआ है, ऐसा जुगाड़ यहां पर नहीं है। बेरोजगार बच्चों को नकद पैसा दिया जाएगा।

Speaker: Please wind-up.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल): उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने भाषण दिया कि हम बाहुबलियों को उलटा लटका देंगे। यह खबर अखबारों में भी छपी और भाषण में भी सुना है। बिना किसी सजा के उलटा लटकाने का कानून हमारे देश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उनको कहा गया कि आपको उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाएंगे। बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको यह कहा कि आपको उस कमेटी का अध्यक्ष बना देते हैं जिस कमेटी ने मुख्य मंत्री का चयन करना है। जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना वे बेहोश हो गए। मेरे ख्याल से आज वे हस्पताल में दाखिल है। वे भी बाहुबलियों में आते हैं। जैसा आप उनके बारे में कहते हैं वे ऐसे आदमी नहीं हैं।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

17.03.2017/1305/SLS-DC-1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव)....जारी

वह भी बाहुबली हैं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं। मनरेगा में जो वर्कर्ज़ काम करते हैं, हमारी जो बहनें काम करती हैं, उनमें से जो 50 दिन पूरे कर लेते हैं उनको लेबर बोर्ड रजिस्टर कर लेता है। उसके बाद उनको इंडक्शन चूल्हे, वाशिंग मशीनें, साइकिल, सोलर लैंप आदि मिलते हैं। अभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैं 590 वाशिंग मशीनें बांटकर आया हूं। अब पता नहीं कि जो यहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, इन्होंने ही दिल्ली जाकर कोई कारस्तानी की है और अब मनरेगा वर्कर्ज़ को लेबर बोर्ड के पास रजिस्टर होने से ही रोक दिया है। दिल्ली से इस बारे में चिट्ठी आ गई है कि अब मनरेगा वर्कर्ज़ रजिस्टर नहीं हो सकते।...(व्यवधान)...इन्होंने ही यह करवाया है कि यहां कांग्रेस की सरकार है और ये लोगों को ऐसी सामग्री बांट रहे हैं, इससे हमें कोई नुकसान न हो जाए। आपने बंद करवाने की कोशिश करवाई है।...(व्यवधान)...अगर नहीं करवाई है तो ईमानदारी से एक कंबाईंड रैज्योल्यूशन पास करके दिल्ली सरकार को भेजा जाए और भारत सरकार मनरेगा वर्कर्ज़ की रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दोबारा से दे।

इसके साथ ही, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जय राम ठाकुर जी और अन्य भी जितने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहां बोले हैं, इनसे कहना चाहता हूं कि मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी जितने स्कूल, अस्पताल या बाकी संस्थाएं खोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है, अगर आपमें हिम्मत है तो अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में जाकर बोलें कि जो संस्थान खोले जा रहे

हैं, इनको बंद कर दो। ...(व्यवधान)...आप कह दो कि इनको बंद कर दो।...(व्यवधान)...आप यहां पर बोल रहे हैं। आप अपने चुनाव क्षेत्रों

17.03.2017/1305/SLS-DC-2

में जाकर एक बार बोलो। ...(व्यवधान)...वहां जाकर प्रैस कॉफ्रैंस करो कि यह जितने कॉलेज, अस्पताल और स्कूल खुले हैं, मैं नहीं चाहता कि यह खुलें, इसलिए इनको बंद कर दो।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, मैं ये कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं जो किसी कवि ने कही हैं। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री के बारे में कहना चाहता हूं। कवि की भाषा में जो उसने कहा है, वही बोल रहा हूं । वह कह रहे थे कि हमारे देश को जो प्रधान मंत्री मिले, वह बहुराष्ट्रीय प्रधान मंत्री मिले। आधी दुनिया घूम ली और एक भी इनवैस्टर हिंदुस्तान में इनवैस्ट करने के लिए नहीं आया। इससे तो अच्छा था कि हमारे अपने हिंदुस्तान के जो उद्योगपति हैं, उनको ही निवेदन किया होता तो उन्होंने ही यहां हजारों उद्योग लगा देने थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि उस कवि ने कहा है। वह उद्योगपतियों को बुलाने के लिए गए थे लेकिन इन अढ़ाई सालों में एक भी इनवैस्टर हिंदुस्तान में नहीं आया है।

जारी .. श्री गर्ग ज

17/03/2017/1310/RG/AG/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री जगजीवन पाल)---जारी

अन्त में, मैं यह निवेदन करते हुए कि जैसे श्री वीरेन्द्र कंवर जी कह रहे हैं कि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में जाकर बोलूंगा कि जितने नए स्कूल-कॉलेज खुले हैं, सब कुछ सरकार

बंद कर दे। तो मैं समाचार-पत्रों में इनका बयान देखना चाहूंगा और जब भी आएगा, तो मैं उसके लिए इनको मुबारकवाद दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारे समाज और पूरे हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो बजट अनुमान यहां प्रस्तुत किए हैं मैं इनका समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद, जय हिन्द।

अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं सदन को दोपहर के भोजन के लिए स्थगित करूं, आपसे निवेदन है कि आज मुख्य मंत्री जी ने इस सारी चर्चा का जवाब देना है और जब भोजनावकाश के पश्चात वापस आएंगे, तो कृपा करके जल्दी आ जाएं क्योंकि काफी देर के पश्चात कोरम होता है। समय से आ जाएं, तो बहुत मेहरबानी होगी।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भोजनावकाश 45 मिनट का ही करें ताकि सदन की बैठक अपराह्न दो बजे से शुरू हो जाए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री जगजीवन पाल जी ने हमारी मुहब्बत का बहुत जिक्र किया, इसलिए मैं भी थोड़ा सा इज़हार कर लूं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में कहा।

Speaker : No, no. Nothing. Not to be recorded. This is not a discussion.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कम-से-कम दस बार जिक्र किया है।

17/03/2017/1310/RG/AG/2

अध्यक्ष : यह कोई चर्चा थोड़े ही है कि जो बोले, उस पर आप भी चर्चा करें।

श्री जय राम ठाकुर : इन्होंने एक बार नहीं, कई बार जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गोवा में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में उनको

झाड़ पड़ी। उसके बावजूद गोवा में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही मणिपुर में सरकार बनी है और बहुमत से बनी है। गोवा में बहुमत साबित कर दिया और मणिपुर में भी करेगी।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

17/03/2017/1415/MS/AG/1

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.15 बजे अपराह्न पुनः आरंभ हुई।

अध्यक्षः अब बजट अनुमानों पर आगे चर्चा होगी। अब चर्चा में श्री रणधीर शर्मा जी भाग लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखिएगा।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2017 को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान इस सदन में रखे और उस पर 14 मार्च से चर्चा शुरू हुई। सर्वप्रथम माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने चर्चा शुरू की। उसी चर्चा में भाग लेने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, जिस दिन मुख्य मंत्री महोदय ने बजट अनुमान रखे, उस दिन मैं सदन में अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण नहीं आ सका था परन्तु चर्चा में जो भी माननीय सदस्य बोले, सभी ने यही कहा कि मुख्य मंत्री जी साढ़े चार घण्टे खड़े होकर लगातार बोलते रहे। हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने उसको रिकॉर्ड भी कहा और ऐतिहासिक भी कहा। उस समय कई माननीय सदस्य सोते भी रहे होंगे और कई जागते भी रहे होंगे। मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता परन्तु मैंने यह ढूंढने की कोशिश की कि साढ़े चार घण्टे इन्होंने क्या पढ़ा। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले पांच बजट भी देखे। वर्ष 2012 के बजट के 85 पेज थे, वर्ष 2013 के बजट के 52 पेज थे, वर्ष 2014 के बजट के 72 पेज थे, वर्ष 2015 के बजट के 80 पेज थे, वर्ष 2016 के बजट के 76 पेज थे और वर्ष 2017 के बजट के 78 पेज थे। अब

अगर 78 पेज पढ़ने के लिए साढ़े चार घण्टे का समय लिया गया है तो उसके कारण क्या है, उस पर सरकार और कांग्रेस पार्टी को जरूर विचार करना चाहिए। मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। साढ़े चार घण्टे में जो पढ़ा गया उसमें से कितना बजट से संबंधित है और कितना सरकार की अन्य उपलब्धियों पर है वह सारा बजट पढ़ने पर भी पता चल जाता है।

अध्यक्षः यहां समय लेने का कोई कम्पीटिशन थोड़े ही है।

17/03/2017/1415/MS/AG/2

श्री रणधीर शर्मा : साढ़े चार घण्टे में जो बजट पढ़ा गया है उसमें कन्टैंट बिल्कुल कम है। चार साल की उपलब्धियों का बखान यहां पर किया गया और अध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा

17.03.2017/1420/जेके/एएस/1

श्री रणधीर शर्माः---जारी-----

यह बजट अभिभाषण है। बजट अनुमान यहां पर रखे जाने चाहिए, परन्तु चार साल की उपलब्धियों का यहां पर बखान करना ये बजट अभिभाषण की गरिमा के खिलाफ है। बहुत कम स्पेस बजट के अनुमान को रखे गए हैं। बहुत कम स्पेस बजट के जो आंकड़ें रखे गए हैं उसके लिए मिला है। बजट को अगर पढ़ना शुरू करें तो पहली लाइन में आता है कि मुझे 20वां बजट प्रस्तुत करते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। हमने तो सुना कि वीरभद्र सिंह जी छठी बार मुख्य मंत्री बनें हैं। उस हिसाब से तो 30वां बजट होना चाहिए था। जब हमने नज़र दौड़ाई और साथियों से पता किया तो लगा कि चार साल के कार्यकाल को भी फुल टर्म मानते रहे, दो साल के कार्यकाल को भी फुल टर्म मानते रहे और यहां तक कि 5 दिन की

टर्म को भी पूरी तरह मान लिया और इस तरह से छः टर्म का मुख्य मंत्री कहा जा रहा है। जो पार्टी या सरकार पांच दिन के कार्यकाल को पांच साल का कार्यकाल मानें उसके आंकड़ें बजट में क्या होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं? वे आंकड़ें इसी तरह है। दिया एक लाख जाता है और घोषणा 5 करोड़ की होती है। दिया 5 लाख जाता है और घोषणा 50 करोड़ की होती है। यह सारा कुछ बजट से भी प्रदर्शित होता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग हर बात को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं। हर आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में नीति आयोग का विरोध किया गया। अनुभवी मुख्य मंत्री है। नीति आयोग केन्द्र की सरकार ने बनाया तो इस देश को एक नई दिशा,नई सोच और नया विचार देने के लिए बनाया है। वर्षों पुरानी प्रथा को बन्द करके एक नई सोच के साथ देश आगे बढ़े, नये आर्थिक परिवर्तनों आए, यह सोच देश के सामने प्रस्तुत की। एक तरफ बात होती है संघीय ढांचे की। अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो आपको नीति आयोग का समर्थन करना चाहिए। आपको नीति आयोग के साथ कन्धे से कन्धा मिला करके चलना चाहिए। आप विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद आप बोलते हैं कि हम तो इस प्रथा को चालू रखेंगे। उस नीति आयोग के कारण आपको 14वें वित्तायोग में 40,625 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता मिली यानि 234 प्रतिशत की वृद्धि मिली। जो 13वें वित्तायोग का अन्याय

17.03.2017/1420/जेके/एएस/2

हुआ था वह सारा दूर हुआ। उसी नीति आयोग के कारण स्पैशल केटैगरी का स्टेटस हमारे हिमाचल प्रदेश को मिला। अब यहां पर राजेश धर्माणी जी बैठे-बैठे बोल रहे थे और जगजीवन पाल जी खड़े हो करके बोल रहे थे कि पहले भी ऐसा ही था। राजेश धर्माणी जी प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने बन्द कर दिया था। यह 70:30 हो गया था। स्पैशल केटैगरी का स्टेटस खत्म हो गया था। यह दोबारा शुरू किया है तो प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। हम इसके लिए उनको धन्यवाद करते हैं। जी0एस0टी0 लागू किया स्टेट के फायदे के लिए। आप तो अभी भी कह रहे हैं कि हम तो पुरानी प्रथा अनुसार

ही इसे लागू रखेंगे। क्योंकि आप लोगों में नई सोच नहीं है। आप नई सोच के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते। न तो आपके पास नई दिशा है, न नई नीति है और न ही नई सोच है। आप पुरानी प्रथाओं को ढो रहे हैं और वे प्रथाएं चाहे कर्ज़ा लेने की है, चाहे कर्ज़े में दलाली देने की है वह सारी की सारी प्रथाएं आपने शुरू की और आप द्वारा वह लागू की जा रही है। आज प्रदेश को कर्ज़े में डुबोया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा वर्ष 1993 से 1998 के बीच इस प्रदेश को कर्ज़ा लेने की संस्कृति और उसमें दलानी देने की संस्कृति अगर शुरू हुई थी तो इसी कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुई थी। इन्हीं मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी के समय में शुरू हुई थी। जिस तरह से 9वें वित्तायोग को गलत आंकड़ें दिए गए थे। प्रदेश की सही आर्थिक परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई थी, उसके कारण 9वें वित्तायोग ने जो आर्थिक सहायता प्रदेश को मिलनी थी वह नहीं मिली। फिर कर्ज़े लेने पड़े और कर्ज़े लेने में दलाली तक दी गई। वह प्रथा तब से शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। उस प्रथा को आगे बढ़ाने में आपका ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

17.03.2017/1425/SS-AS/1

श्री रणधीर शर्मा क्रमागतः

हमारे नेता आदरणीय धूमल जी और बाकी सब वक्ता बोल चुके हैं। परन्तु मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि आपने बजट में माना है कि हिमाचल प्रदेश पर 38568 करोड़ रुपये का कर्जा है। कल एक प्रश्न लगा था कि वर्ष 2016 में कितना कर्जा लिया तो जवाब आया 14382.21 करोड़। इसको मिला दिया जाए तो 52950 करोड़ रुपये कर्जा आज हिमाचल प्रदेश पर है। आपने इस नये बजट में उसी प्रथा को चालू रखते हुए कहा कि हम 22.55 परसैंट कर्जा लेकर सरकार को चलायेंगे। यह लिखकर बजट में दिया है। मैंने कैलकुलेट

किया तो 8070 करोड़ रुपया लेने की आपने और सोच रखी है। तो आप इसी साल 60 हजार करोड़ तक पहुंच जायेंगे और मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो कर्जा हिमाचल प्रदेश के सिर पर है उसमें अधिकांश कर्जा अगर किसी सरकार के समय लिया गया है तो इस कांग्रेस सरकार के समय और मुख्य मंत्री, वीरभद्र सिंह जी के राज में लिया गया है क्योंकि ये प्रथाओं को चालू रखने में विश्वास करते हैं। अपने संसाधन खड़े करना, अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठाना, इस दृष्टि से कभी इस सरकार ने प्रयास नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्री जी पॉलिटिकल मैनेजमैंट बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि मुख्य मंत्री जी लीगल मैनेजमैंट बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। मामले चाहे शिमला की या दिल्ली की अदालतों में हों तो बड़ी अच्छी मैनेजमैंट होती है। राजनीतिक मैनेजमैंट भी कर सकते हैं। परन्तु जो इकोनोमिक मैनेजमैंट या आर्थिक प्रबंधन है उसमें मुख्य मंत्री जी बहुत कमजोर हैं। यह पक्ष इनका बहुत कमजोर है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हिमाचल प्रदेश को आज आर्थिक दृष्टि से अगर किसी ने कमजोर किया है तो इसी सरकार और इन्हीं मुख्य मंत्री जी के कारण हुआ है। इसी बजट के आंकड़े हैं। आप हैरान होंगे, जहां राजस्व घाटे की बात आती है, 2012-13 का बजट माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने प्रस्तुत किया था तो उस समय 373.79 करोड़ राजस्व घाटा था। ठीक है वह घाटा बढ़ा। परन्तु जब 14वें वित्तायोग में हमारी केन्द्रीय सरकार, आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 234 प्रतिशत की

17.03.2017/1425/SS-AS/2

वृद्धि करके आर्थिक सहायता की तो राजस्व घाटा खत्म करना उसका उद्देश्य था। 2015-16 में उसके परिणाम सामने आए तो राजस्व घाटा 47 करोड़ रह गया। परन्तु आज दो साल में वह राजस्व घाटा 47 करोड़ से बढ़कर 1041 करोड़ बन गया। यह आपकी स्थिति है। वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे समय यह 1939 करोड़ था लेकिन आज 4946 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अध्यक्ष महोदय, आप किसी

भी विषय की बात कर लें। हमारे यहां बजट में ही आंकड़े दिये गए हैं। राजस्व आय की बात की जाती है। राजस्व आय में हमारे चार फैक्टर हैं। टैक्स, गैर-टैक्स, अपने संसाधन और केन्द्रीय करों में हिस्सेदार/केन्द्रीय अनुदान हैं। यह राजस्व आय हमें चार संसाधनों से प्राप्त होती है। अध्यक्ष महोदय, इसके भी अगर पिछले पांच साल के आंकड़े देखें तो इस सरकार के समय स्पष्ट नज़र आता है कि कोई अपना आर्थिक संसाधन बढ़ाने के प्रयास नहीं हुए हैं। यहां तक टैक्स कॉलैक्शन में भी कमी आती गई। आप हैरान होंगे कि 2012-13 के बजट में हमारा 100 में से 30.95 प्रतिशत इन्कम करों से होती थी, आज 2017-18 में जिसमें वृद्धि होनी चाहिए थी उसमें कमी आई है और 28.67 प्रतिशत रह गया है। ये बजट के आंकड़े बोल रहे हैं। टैक्स कॉलैक्शन बढ़ना चाहिए परन्तु आपके राज में टैक्स कॉलैक्शन कम हो रहा है। जब टैक्स कॉलैक्शन ही नहीं बढ़ रहा तो गैर-टैक्स कॉलैक्शन कहां से बढ़ेगा? उसमें तो आप कुछ करते ही नहीं हैं। आप हैरान होंगे कि हमारी सरकार के समय 12.25 प्रतिशत गैर कर कॉलैक्शन थी लेकिन आज वह घटकर 5.78 रह गई है। यह आपका गैर कर कॉलैक्शन है। राजस्व आय की यह हालत है। सरकार कर क्या रही है?

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2017/1430/केएस/डीसी/1

श्री रणधीर शर्मा जारी---

टैक्स आप नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं और गैर टैक्स में आप करते कुछ नहीं, कोई संसाधन खड़ा नहीं करते। यह सरकार की कमियां है और उल्टा केन्द्रीय करों में बढ़ौत्तरी होती जा रही है1 यू.पी.ए. की सरकार के समय 15.35 तक केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी थी जो मोदी जी की सरकार बनने के बाद 17.39 प्रतिशत हो गई है। आप केन्द्रीय अनुदान की बात करेंगें, जो यू.पी.ए. की सरकार के समय आपको 38.92 तक मिलता था वह हमारी सरकार में बढ़कर 48.16 प्रतिशत हो गया है। मतलब केन्द्र के करों की हिस्सेदारी भी बढ़ी

है। केन्द्र का अनुदान भी बढ़ा है परन्तु प्रदेश की अपनी टैक्स कलैक्शन भी कम हो गई और प्रदेश की अपनी गैर टैक्स कलैक्शन भी कम हो गई। तो कहां आपका आर्थिक प्रबन्धन है? तभी मैंने कहा कि हमारे मुख्य मंत्री जी का आर्थिक प्रबन्धन का विषय बड़ा कमज़ोर है। राजेश धर्माणी जी को अगर ये अपना आर्थिक सलाहकार रख लेते तो शायद कुछ सुधार होता।

अध्यक्ष महोदय, राजस्व व्यय की बात लीजिए। उसमें भी इसी बजट के आंकड़े बोल रहे हैं कि आपने विकास में जो पैसा जाना है, उसमें कमी लाई है। मैं इन आंकड़ों को पढ़ देता हूं, वैसे तो मेरे पास पांच साल के आंकड़े हैं लेकिन मैं उन पर नहीं जाना चाहता। मैं आपके ही पिछले साल के आंकड़ों की बात करुंगा। विकास के लिए 40.86 प्रतिशत बचा था, इस बार 39.55 प्रतिशत बचा है। पिछले साल तक हर साल बढ़ौत्तरी हो रही थी विकास के लिए जो बजट बचता है, धीरे-धीरे, बढ़ते-बढ़ते उसमें हम 40.86 तक पहुंचे थे लेकिन इस साल उसमें कमी आ गई है। 39.55 प्रतिशत आपने विकास और अन्य कामों के लिए पैसा रखा है बाकी तो क्लीयर है। आपका 26.09 प्रतिशत वेतन में जाएगा । 13.83 प्रतिशत पैंशन में जाएगा 9.78 प्रतिशत ब्याज अदायगी में जाएगा और 9.91 ऋण अदायगी में जाएगा। यह क्लीयर है इसको जोड़ लो तो 39.55 बचता है वह विकास और अन्य कामों के लिए हैं।

17.03.2017/1430/केएस/डीसी/2

अध्यक्ष महोदय, बड़ी-बड़ी घोषणाएं की है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप जो विकास और अन्य गतिविधियों के लिए पैसा रखा है उसमें तो कमी आ गई। घोषणाएं आपने बड़ी-बड़ी कर दी। आपने घोषणा कर दी बेरोज़गारी भत्ता 150 करोड़ देंगें। मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि यह 150 करोड़ आएगा कहां से? आपने उसका क्या बन्दोबस्त किया है? क्या वह 150 करोड़ इसी 39.55 में से जाएगा जो विकास के लिए हैं? अगर इसी में से जाना है तो वह तो विकास कार्यों में कमी आ जाएगी। आप पूरा बजट पढ़ लीजिए, आपने अलग से 150 करोड़ का कोई इन्तज़ाम नहीं किया है। आपने

बड़ी-बड़ी घोषणाएं भी कर दी। अभी तो 150 करोड़ में से आपने यूनिवर्सिटी को भी देना है, एच.आर.टी.सी. को भी देना है, जिला परिषद वालों को भी देना है। दीजिए, यह अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं परन्तु कहां से? आप विकास का पैसा अगर वहां देंगें तो विकास के कार्यों में कमी आएगी। जनता की जेब काटोगे, जनता को बांटोगे। आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। आपकी इसमें गलत मानसिकता है। यह आपका बजट है। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बता सकते हैं अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगें। बजट में घोषणा कर दी कि 19 हजार पोस्टें भरेंगें। अगर 19 हजार पोस्टें भरेंगें तो उनको वेतन कहां से देंगें? क्या बजट में इसका प्रावधान है? क्या आपने कैल्कुलेट किया है कि 19 हजार पोस्टों के लिए कितना वेतन बनता है? आपके बजट में तो सीधा लिखा है कि 26 प्रतिशत पैसा उसका वेतन में जाना है। वह तो पहले ही जा रहा है। आप किसको गुमराह कर रहे हैं? तभी तो कोरी घोषणाएं कहा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक और बड़ी घोषणा की। बड़ी बहस चली। श्री जगजीवन पाल जी आज मंत्री की कुर्सी पर हैं। धर्मशाला राजधानी है। क्या तकलीफ़ है? हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। बनाओ परन्तु मुझे बताओ कि उसके लिए इस बजट में कहां बजट है?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.3.2017/1435/av/ag/1

श्री रणधीर शर्मा ---जारी

आपने कहीं पर केपिटल बनाने के लिए एक रुपया भी रखा है? मैंने उस दिन कहा था कि आपने टोफियां बांटी तो टोफी भी एक-दो रुपये की आती है। यह तो कोरा शगूफा है। आप दूसरी केपिटल बनाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए बजट में एक रुपये का भी प्रावधान नहीं है। कैसे बनेगी राजधानी और उस राजधानी में क्या होगा? आप कुछ पैसे का

प्रावधान तो करते, कोरी घोषणाओं में भी दम होता है इसमें तो बिल्कुल भी दम नहीं है। (---व्यवधान---) मैं हा-हाकार तो मचाऊंगा ही जब आप इस तरह से बोलेंगे। आज स्मार्ट सिटी के बारे में एक नई परिभाषा आ गई। आज जगजीवन पाल जी ने एक नई परिभाषा दी है। कहते हैं कि हमारा स्मार्ट मंत्री इसलिए स्मार्ट सिटी। आप किसी भी ऐक्सपर्ट को बुला लो सबसे स्मार्ट कोई है तो वह श्रीमती विद्या स्टोक्स जी हैं। हमारे राजेश धर्माणी जी भी किसी से पीछे नहीं है। राजीव बिन्दल जी भी किसी से पीछे नहीं है। (---व्यवधान---) नहीं, मुझे तो आप (उद्योग मंत्री) भी पसन्द है लेकिन ऊना को भी किसी ने नहीं माना। मैं भी आपको पसन्द हूं इसीलिए आपकी ससुराल मेरे वहां है। आप कुछ मेरा ही सोच लेते। लेकिन जगजीवन पाल जी यह स्मार्टनैस क्राइटीरिया नहीं है। कुछ पैमाने/पैरामीटर होते हैं जिन पर प्रदेश सरकार को कुछ सोचना होता है, विचार करना होता है। इन पैरामीटर पर प्रदेश सरकार ने अगर गलत विचार किया है तो सुरेश भारद्वाज जी ने उसका विरोध किया है। मजाक की बात नहीं है, तथ्यों पर बात करो। दूसरी बात, आप बजट में स्मार्ट सिटी, अमृत सिटी लिखते हैं। उसके साथ यह भी लिख दिया करो कि केंद्र सरकार ने इतना दिया और मोदी जी का धन्यवाद। (---व्यवधान---) आपका योगदान कुछ नहीं है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो यहां पर कर मुक्त बजट पेश करने की प्रथा शुरू की हुई है इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। यह ठीक है कि एक की टोपी उठाई दूसरे के सिर पर और दूसरे की उठाई तीसरे के सिर पर। आप पैसा इधर-उधर बांटते रहेंगे तो प्रदेश का भला नहीं होगा। हमें प्रदेश के अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने होंगे, हमें उस बारे में विचार करना चाहिए। मुख्य मंत्री जी का तजुर्बा अगर इस

17.3.2017/1435/av/ag/2

दृष्टि से सामने आता है कि उन्होंने इस साल कोई नये संसाधन खड़े किए, पिछले चार सालों में आय के कुछ साधन जुटाये तो हम भी प्रशंसा करते। मगर ऐसा होने की बजाय उल्टा हो गया और मैं आंकड़े दे रहा हूं कि विकास कार्यों में कमी कैसे आई। (---व्यवधान-

--) मुकेश जी, आपके बजट के आंकड़े दे रहा हूं। (---व्यवधान---) मैं आपकी ही प्रशंसा कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं का इस साल और पिछले साल का बजट है। मैं कह रहा हूं कि कटौती कैसे आयेगी। वह जो 100 करोड़ रुपये या 150 करोड़ रुपये गया है उसका फर्क क्या है? आपके पिछले साल के बजट में शिक्षा पर कुल 18.44 प्रतिशत था जो इस बार घटकर 17.33 रह गया। आपका लोक निर्माण विभाग के लिए पिछले साल 9.48 प्रतिशत था जो इस साल घटकर 9.37 रह गया। बजट बढ़ता है, घटता नहीं है। हालांकि आपका टोटल बजट बढ़ा है लेकिन प्रतिशतता निकाले तो कम हो रहा है और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने दूसरी तरफ पैसा निकाला है। हैल्थ में, कौल सिंह जी, आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें पहले 5.18 प्रतिशत था अब 4.80 प्रतिशत रह गया है। आई0पी0एच0 में 7.6 प्रतिशत था और अब 6.59 प्रतिशत रह गया है। मैं आंकड़ों पर बात कर रहा हूं। इसलिए यह बजट कोई सराहना करने योग्य नहीं है और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं। हमारे बजट में उद्योग विभाग की बड़ी चर्चा है कि हम यह रियायत देंगे वह रियायत देंगे। पिछले पांच साल से बजट में यही आ रहा है और अगर आप रियायतें दे रहे होते तो उद्योग आते। यहां तो उल्टा उद्योग बंद हो रहे हैं, उद्योग पलायन कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में दो सौ से ज्यादा उद्योग बंद होकर चले गये हैं, आप ये रियायतें किसको दे रहे हैं? मुम्बई-दिल्ली जाकर कुछेक को पकड़कर लाते हैं और टाहलीवाल में खुलवा देते हैं। क्या सिर्फ टाहलीवाल ही औद्योगिक क्षेत्र है? क्या आप केवल हरोली विधान सभा क्षेत्र के ही मंत्री है? विकास कार्य तो वहां करवा ही रहे हैं, साथ में इंडस्ट्री भी वहीं खोल रहे हैं।

श्री वर्मा द्वारा जारी

17/03/2017/1440/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

श्री रणधीर शर्मा..... जारी।

मैं आपका रिश्ते में कुछ लगता हूं, वैसे भी पड़ोसी हूं। मेरे यहां भी ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र हैं। आपके कार्यकाल में वहां तीन औद्योगिक इकाईयां बन्द हो गई। आपने पिछले साल प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 9 औद्योगिक इकाईयां आ रही है, लेकिन एक भी नहीं आई। ये आपकी हालत है। माननीय सदस्य बम्बर जी यहां पर प्रश्न करते थे- पंजाब में सीमेंट सस्ता है, हिमाचल में महंगा है, कब सस्ता होगा? श्री मुकेश जी उत्तर देते थ- जल्दी मीटिंग की जाएगी और सस्ता हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कितनी मीटिंगें की? अखबार में भी आता था, आज उद्योग मंत्री सीमेंट कम्पनी मालिकों से बैठकें कर रहे हैं, लेकिन सीमेंट का रेट कम होने के वज़ाय बढ़ जाता था। आज 4 साल पूरे होने के बाद भी पंजाब में सीमेंट 295 रूपये बोरी है, मेरा तो बॉर्डर है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सीमेंट की बोरी का रेट 375 रूपये हैं। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी 5 साल में कोई उपलब्धि नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होता, आपने बजट में भी कुछ नहीं किया। उद्योग विभाग कर क्या रहा है? आपके अंडर एक और बोर्ड है, कामगार बोर्ड। अध्यक्ष महोदय, हमने भ्रष्टाचार की चार्ज़शीट सौंपी, मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता। हमने बहुत से मुद्दे उसमें लिए है और कहा है कि इनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन एक नया भ्रष्टाचार आ गया, जो मजदूरों के पैसों पर हो रहा है। ये सरकार मंदिरों के पैसों का भ्रष्टाचार तो कर ही रही थी, मन्दिरों के पैसों का दुरुपयोग तो हो रहा था, सरकारी खज़ाने को लूटा जा रहा था, परन्तु ये ऐसा घोटाला आ गया, जो मजदूरों के पैसों पर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मजदूर हैं, उनकी इंश्योरेंस होती है, उसका पैसा वे ठेकेदार देते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं। वह पैसा मजदूरों के लिए बिल्डिंग के काम में लगे, वे बीमार हों तो दिया जाता है, उनकी बेटी की शादी में दिया जाता है, उनको कोई और दुःख तकलीफ़ हों तो दिया जाता है, लेकिन इस सरकार ने वह पैसा अपनी पार्टी के वोट बैंक बढ़ाने के लिए शुरू कर दिया। अभी श्री जगजीवन पाल जी खुद कह रहे थे कि इस पैसे को मनरेगा के मुलाज़िम ले सकतें हैं, लेकिन मनरेगा के वे मुलाज़िम ही इसको ले सकते हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन्ज़ में लगे हैं, अन्य कोई नहीं ले सकते। मजदूरों को कौन टैस्ट करेगा? इंटक/सीटू का युनियन लीडर नहीं करेगा, लैबर ऑफिसर करेगा। आप जांच करवाइये, क्या आपने जिनको बेनिफ़िट दिया है, उन मज़दूरों को लैबर ऑफिसर ने टैस्ट किया है कि वे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मजदूर हैं? -(व्यवधान)-

17/03/2017/1440/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

उद्योग मंत्रीः केन्द्र में जो सरकार है, उन्होंने यह नोटिफाई किया है। ये डायरेक्शन्ज़ केन्द्र की हैं, जिन्हें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की नोटिफिकेशन्ज़ हैं, जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन्ज़ में लगे हैं, ये पैसा उनको मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये पैसा देने में क्या राजनिति हो रही है? आप बेटी की शादी, बीमार होने पर पैसे दीजिए, लेकिन आप इंडक्शन चुल्हे बांट रहे हैं, आप वॉशिंग मशीनें बांट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको बांट कौन रहा है? सरकार का मंत्री बांटे, हम मान सकते हैं, विधायक बांटे हम मान सकते हैं,लेकिन आपकी पार्टी का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बांट रहा है। मुख्य मंत्री के बेटे की आज स्टे्टमेंट है, हम शिमला ग्रामीण में 5,500 वॉशिंग मशीनें कामगार लोगों में बांटेंगे। उन्होंने किस हैसियत से वह बयान दिया है। मुख्य मंत्री का बेटा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मज़दूरों के पैसों का इस तरह से दुरुपयोग करें। क्या 5500 वॉशिंग मशीनें एक ही विधान सभा क्षेत्र में बांटने के लिए हैं, बाकी विधान सभा क्षेत्र नहीं है? मुख्य मंत्री ने कह दिया कि वह वहां से चुनाव लड़ेगा, इसलिए वह घोषणाएं कर रहे हैं। आप कहते हैं, केन्द्र सरकार को यूनेनिमस प्रस्ताव भेजो, कामगार बोर्ड में सारे मनरेगा वाले हों और श्री जगजीवन पाल जी आपके घर में जो नौकर हैं, वह भी हों, आप ये भी चाहेंगे। परन्तु अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है, यहां पर सदन में उद्योग मंत्री जी बैठे हैं, आप इस मामले की जांच करवायें, कामगार बोर्ड की गतिविधियों और जिस तरह से मजदूरों के पैसों का भ्रष्टाचार हो रहा है, मजदूरों के पैसों पर राजनीति हो रही है, उसकी जल्दी-से-जल्दी जांच होनी चाहिए। ये मैं यहां पर मांग करता हूं।

अध्यक्षः वाईंडअप प्लीज़, अब तो बहुत टाईम हो गया है।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 5 मिनट लूंगा। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग की चर्चा यहां हुई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री कौल सिंह जी सदन से उठकर चले गये हैं। इन्होंने एक नोटिफिकेशन की, हमने नहीं की और उस नोटिफिकेशन को खुद ही इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये 7 अप्रैल, 2016 की नोटिफिकेशन है, डॉक्टरों की पोस्टें कम कर दी और पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 खोलने के नॉर्मज़ तय कर दिये।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

17/03/2017/1445/ एन0एस0/ए0एस0 /1

श्री रणधीर शर्मा------जारी

अब यह सरकार नोटिफिकेशन करती है तो लागू किसने करनी है? इस नोटिफिकेशन के अनुसार पी0एच0सी0 में एक ही डॉक्टर होगा, पहले दो डॉक्टर होते थे। सी0एच0सी0 में चार डाक्टर होते थे, अब दो ही होंगे। मेरे पास ऐसी लिस्ट है जिसमें फार्मासिस्ट और नर्सों की भी पोस्टें कम हुई हैं। अध्यक्ष महोदय , मैं आपको इसी का दूसरा भाग बताना चाहता हूं। पी0एच0सी0 वहीं खुलेगा जहां जनरल में आबादी 30,000 से ऊपर हो और ट्राईबल में 20,000 से ऊपर हो। सी0एच0सी0 वहीं खुलेगा जहां जनरल में आबादी 1लाख 20 हजार हो और ट्राईबल में 80,000 हो। यहां पर फाईनैंस विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये नॉर्म्ज फॉलो हो रहे हैं। यह लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। यह अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन है। अगर आप लागू ही नहीं कर सकते हैं तो ऐसी नोटिफिकेशन्ज़ जारी क्यों करते हैं? इस मान्य सदन में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं। मैं माननीय धूमल जी और माननीय बिन्दल जी को बधाई देता हूं कि जब हमारी सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश दवाईयों को एक्सपोर्ट करने में नम्बर वन था। मैं पूछना चाहता हूं कि आज हैल्थ में हिमाचल प्रदेश नम्बर वन कहां है? आप पिछले कल का अखबार पढ़िये। देश में 40 उद्योगों की 420 दवाईयां मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं और हिमाचल प्रदेश इसमें प्रथम है। हिमाचल प्रदेश के 18 उद्योगों की 131 दवाईयां मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश इस काम में नम्बर वन है कि उसकी ज्यादा फैक्टरियों की ज्यादा दवाईयां फेल हो रही हैं। मैं इस मान्य सदन को बताना चाहूंगा कि यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ बायोलोजिकल की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही हैल्थ कार्ड है। यह इस सरकार की हालत है। बजट की किताब में स्वास्थ्य के एक-दो पैरों

के बाद लिख रहे हैं कि शिक्षा में सर्वोत्तम। अगर अब हिमाचल प्रदेश शिक्षा में सर्वोत्तम है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले

17/03/2017/1445/ एन0एस0/ए0एस0 /2

कल यहां पर चम्बा के विधायक का प्रश्न लगा था कि चम्बा जिला में अध्यापकों की सारी श्रेणियों की कितनी पोस्टें खाली हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं अलग-अलग श्रेणी नहीं बताना चाहता हूं लेकिन इसके जवाब में लिखा था कि चम्बा जिला में कुल 1050 अध्यापकों की पोस्टें खाली हैं। हिमाचल प्रदेश के एक ही जिला चम्बा, जहां केवल 5 ही विधान सभा क्षेत्र हैं, उसकी 1050 पोस्टें खाली हों और वही हिमाचल अगर देश में सर्वोत्तम है तो देश के क्या हालात होंगे? इसका मतलब यह है कि आप सही आंकड़े नहीं देते हैं और अगर ये आंकड़ें जाते तो आप को कोई सर्वोत्तम नहीं कहता। आज शिक्षा विभाग की क्या हालत है? रूसा से क्या हो रहा है? इस मान्य सदन में स्कूल खुलने की बातें आईं। माननीय जगजीवन पाल जी ने जोर-जोर से कहा कि आप में हिम्मत है तो बंद करवाओ और बोलो। माननीय जगजीवन पाल जी हमने क्यों बोलना, लोग खुद ही बंद कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पंचायत सुईंसराड़ है। इस पंचायत में सीनियर सैकेंडरी स्कूल है।

अध्यक्षः प्लीज आप वाईंडअप कीजिए। आपके पांच मिनट खत्म हो गए हैं।

श्री रणधीर शर्मा : इस पंचायत में प्राईमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडल कर दिया गया। इसका उद्घाटन हुआ और सीनियर सैकेंडरी स्कूल से एक टीजीटी वहां पर रख दिया। दोनों स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी , तब पंचायत और एस0एम0सी0 कमेटी बैठी और उन्होंने तय किया तथा मिडल स्कूल बंद किया, वहां के छात्रों को सीनियर सैकेंडरी स्कूल में ले आए, तब जा करके स्कूल चला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम उन स्कूलों को बंद नहीं करेंगे, वहां के लोग खुद बंद कर रहे हैं। हमें इसके लिए बोलने की भी जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर बस अड्डे बनाने की बात हुई। मेरे क्षेत्र स्वारघाट में बस अड्डा बनने के लिए 37.50 लाख रूपये की राशि भाजपा के समय में

दी गई थी। सरकार बदली और नोटिफिकेशन जारी होती है कि you are, therefore, requested to stop the construction work of Bus Stand at Swarghat till further order as per decision taken in the meeting of Board of director HPBSM&DA सरकार की यह हालत है। इन्होंने पैसा वापिस मंगवा लिया और बस स्टैंड का

17/03/2017/1445/ एन0एस0/ए0एस0 /3

काम रोक दिया गया। आप बोलते हैं कि हम भर्तियां कर रहे हैं। आप इसका दूसरा पहलू भी देखिए। पुलिस विभाग की चौथी, पांचवी बैटालियन में आपने 39 पोस्टें अबोलिश कर दीं। वे पद चतुर्थ श्रेणी के थे। आप किसी ऑफिसर की पोस्ट खत्म नहीं करेंगे लेकिन चतुर्थ श्रेणी की पोस्टें खत्म कर देंगे। आप इंस्टीच्यूट तो खोल रहे हैं परन्तु साथ में बंद भी तो कर रहे हैं। आपने नोटिफिकेशन जारी की The Government of Himachal Pradesh if further please to order the disband closer of the office of Chanager Area Medium Irrigation Projectg Division Bassi Scheme यह डिवीजन बंद हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि हम इंस्टीच्यूट खोल रहे हैं। आपने स्वारघाट में तहसील वेल्फेयर ऑफिस खोला, वहां पर एक ऑफिसर एक हफ्ते तक बैठा और अब चला गया है। आज तीन महीने से उस दफ्तर में ताला लगा है। वहां पर न ही कोई चपरासी, चौकीदार और न ही कोई सफाई कर्मचारी है। उस क्षेत्र की जनता कहां जाए? इस तरह के इंस्टीच्यूट खोलने से तो अच्छा है कि इंस्टीच्यूट न खुलें।

श्री आर0के0एस0------जारी।

17/03/2017/1450/RKS/AS/1

श्री रणधीर शर्मा...जारी

अध्यक्ष महोदय, यह हालत आज पूरे प्रदेश में इस सरकार की है। नैना देवी-अनंतपुर साहब रोपवे आपने बंद कर दिया। ए.ओ.यू. कैंसल कर दिया।

अध्यक्षः माननीय सदस्य बहुत समय हो गया है, कृपया आप वाईंड-अप कीजिए। Otherwise I will stop recording.

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, दो मिनट बोलने दीजिए। मैं नोटबंदी पर बोलना चाहूंगा। यह कहा गया कि-'नोटबंदी पर तैयारी नहीं थी, हड़बड़ी थी'। आप चाहते थे कि तैयारी करते, शोर मचाते और हमें भी पता चलता कि नोटबंदी हो रही है ताकि आप अपने नोट बचा लें। आपकी आदत है कि सी.बी.आई. या कोई और एजेन्सी छापा मारे तो वह भी आपको पूछ कर के मारे। छापे बता के नहीं मारे जाते हैं। नोटबंदी बता के नहीं होती है। नोटबंदी अचानक होती है, ताकि जिनके पास काला धन है वे पकड़े जाएं। यह हुआ भी है। माननीय प्रधान मंत्री जी से पत्रकारों ने पूछा कि नोटबंदी के कारण आपकी पार्टी का वोट बैंक खराब होगा। प्रधान मंत्री जी ने कहा मैंने यह निर्णय पार्टी के वोट बैंक को ध्यान में रखकर नहीं लिया है। मैंने यह निर्णण राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लिया है। मैंने यह निर्णय देश से काला धन, भ्रष्टाचार, महंगाई और नकली नोटों की समस्या को खत्म करने के लिए लिया है। आप काले धन का हिसाब मांगते हैं। काला धन बाहर नहीं आता है। जो काला धन घरों में रह गया, वह खत्म हो गया है। माननीय सदस्य श्री जगजीवन पाल जी आप सोच समझकर बात किया करें। नोटबंदी का असर आपने चुनावों में देखा है। नगर निगम में हम जीते हैं। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश तो हमने जीतना ही था लेकिन हम गोवा और मणिपुर भी जीत गए हैं। यह सब नोटबंदी का ही असर है। माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं- 'गोवा और मणिपुर में राज्यपाल भाजपा के एजैंट'।

Speaker: Not to be recorded now. ____(interruption)___ This is wrong on your part. अब श्री संजय रतन जी चर्चा में भाग लेंगे।

17/03/2017/1450/RKS/AS/2

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने 10 मार्च, 2017 को इस माननीय सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जो बजट अनुमान प्रस्तुत किये हैं, मैं उनके

बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन का 20वां 'बजट अनुमान' इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं। लगभग साढ़े चार घंटे इन बजट अनुमानों को प्रस्तुत करने में लगे हैं, जोकि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। बहुत कम लोगों को अपने जीवन में ऐसा मौका मिलता है और यह मौका हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र जी को मिला है। मेरे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि हमें मुख्य मंत्री जी को साढ़े चार घंटे सहन करना पड़ा। अभी आप आगे-आगे देखिए आपको बहुत चीजें सहन करना पड़ेगी। जब राजा साहब सातवीं बार मुख्य मंत्री बनकर आएंगे तो 6 घंटे भी बजट अनुमान प्रस्तुत किए जाएंगे। बजट अनुमान किसी भी सरकार के वित्तीय वर्ष का प्रतिबिम्ब/छाया होती है। साल भर में सरकार द्वारा क्या काम किए जाएंगे और कहां से पैसा आएगा, पैसा किस प्रकार से खर्च किया जाएगा बजट अनुमानों में यह सब प्रस्तुत किया जाता है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी..

17.03.2017/1455/SLS-DC-1

श्री संजय रतन....जारी

बहुत से विपक्ष के साथियों ने यहां कहा कि जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, इसमें कुछ नहीं हैं। 20 पैसे में 12 पैसे में यह होगा,वह होगा; इस तरह से कई फिगर्ज़ यहां देने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से विकास करेंगे। यह हमारी चिंता है, हमारी सरकार की चिंता है, हमारे वित्त मंत्री की चिंता है और हमारे मुख्य मंत्री की चिंता है। परिवार का जो मुखिया होता है, जिस तरीके से आप अपने परिवार को चलाते हैं; आप कहां से पैसा लाते हैं, अपने परिवार के रख-रखाव के लिए आप साधन कैसे देते हैं, यह आपके ऊपर

निर्भर करता है। इसलिए इसमें आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह चिंता हमारे मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री की है। ...(व्यवधान)...मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं।

पिछले सालों के बजट अनुमान भी आपके सामने थे और इस साल का बजट अनुमान भी आपके सामने है। पिछले सालों में जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट अनुमान प्रस्तुत किए, इस माननीय सदन ने ध्वनिमत से उनको पास किया और उसके अनुसार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को चलाया है; हिमाचल प्रदेश में विकास किया है।

आज आपको पीड़ा हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में नए-नए संस्थान खुल रहे हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो चाहे नए सब-डिविजन खोले हों, नई तहसीलें और उप-तहसीलें खोली हों या और विकास के काम किए हों। उनको किस तरीके से मुख्य मंत्री महोदय ने धन उपलब्ध करवाया, यह उनको मालूम है। आप लोगों ने सिर्फ़ एक ध्येय बनाया हुआ है और मुझे हाऊस में कहते हुए गुरेज़ नहीं है कि जब से मैं विधायक बनकर आया हूं, मैंने विपक्ष के लोगों द्वारा केवल मात्र विरोध ही देखा है। आपने कभी किसी काम को अच्छा नहीं कहा। हमेशा आपने विरोध किया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, जितने भी हमारे पिछले सालों के बजट अनुमान थे, या हमारा घोषणा-पत्र था, उनको चरणबद्ध तरीके से अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया। उसमें से जो इक्का-दुक्का चीजें छूट गई थीं, जब तक वह

17.03.2017/1455/SLS-DC-2

पूरी नहीं की, आप यहां से विरोध करते रहे। आप यह कहते रहे कि घोषणा-पत्र के अनुसार, जिसको हमारी सरकार ने नीति दस्तावेज़ बनाया, बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया। आप चिल्लाते रहे। जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बार के बजट में बेरोज़गारी भत्ता दे दिया तो आप फिर तड़पने लगे, फिर चिल्लाने लग पड़े, फिर विरोध करने लग पड़े कि यह कैसे देंगे? आप किसी भी चीज़ को सही नहीं कहना चाहते। मुझे लगता है कि यह

आपकी मानसिकता बन गई है। आपने जिस स्कूल में पढ़ाई की है, शायद उसमें आपको विरोध करना ही सिखाया जाता है। मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आपको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए यहां भेजा है। आप सत्ता में नहीं रह सकते; आप विरोध करना ही सीख चुके हैं और आपकी रगों में विरोध करना ही घुस चुका है। आप हमेशा विरोध करते रहेंगे, अगली बार भी यहीं बैठेंगे, फिर विरोध करते रहेंगे। हम सत्ता में रहेंगे और हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे।

आपने कहा कि यह सरकार ऋणों के ऊपर चल रही है। जब हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार थी, क्या आपने ऋण नहीं लिए? वर्ष 2012 तक आपने ऋण को 26494 करोड़ रुपये तक पहुंचाया। आज वह बढ़कर 38000 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। क्या आपने ऋण नहीं लिया? अगर आप हिमाचल प्रदेश के इतने ही हितैषी थे और आप सरकार को सही तरीके से अपने साधन जुटाकर चलाना चाहते थे तो आप ऋण नहीं लेते? मुझे मालूम है, हालांकि मैं विधायक नहीं था, कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो ट्रेज़रीज के ऊपर दो बार ओवर ड्राफ्ट का फट्टा भी लगा था।

आप लोगों की आर्थिक कैलकुलेशन्ज बड़ी पुअर है। अभी रणधीर शर्मा जी कह रहे थे कि मुख्य मंत्री महोदय की सारी मैनेजमैंट्स अच्छी हैं लेकिन आर्थिक मैनेजमैंट अच्छी नहीं है।

जारी .. श्री गर्ग जी

17/03/2017/1500/RG/DC/1

श्री संजय रतन---जारी

तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय का प्रबन्धन और आर्थिक प्रबन्धन, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। सीमित साधनों में प्रदेश को आगे ले जाने में ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं वह काबिलेतारीफ है और इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां श्री रणधीर जी कह रहे थे कि नीति आयोग का विरोध किया जा रहा है। तो यह संघीय ढांचा है, नीति आयोग का कोई विरोध नहीं कर रहा था। दिल्ली में इनकी सरकार है और ये चाहे, तो जिस तरीके के आयोग बनाते जाएं, मगर जो पहले वर्षों से चला आ रहा था, जब देश आजाद हुआ, तब से योजना आयोग चल रहा था। आप नीति आयोग को बना लेते, उसके बाद योजना आयोग को भंग कर देते। इनको किसने रोका था? कलम इनके हाथों में है और आपकी कलम में ताकत थी। लेकिन इन्होंने योजना आयोग को भी भंग कर दिया और नीति आयोग भी नहीं बना। उससे प्रदेशों को दिक्कत आई, जो प्रदेश संघीय ढांचे में शामिल हैं उनको दिक्कत आईं, उससे हम इनको अवगत करवाना चाहते हैं। मगर इन लोगों ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में बनी है, एक ही रट लगा रखी है कि हर छोटे-से-छोटे काम में ये केन्द्र सरकार का नाम लेना चाहते हैं। केन्द्र सरकार को श्रेय देना चाहते हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब यू.पी.ए. की सरकार थी तब भी तो केन्द्र में सरकार थी और तब ये लोग यहां सत्ता में बैठे हुए थे। उस समय जब ये बजट अनुमान प्रस्तुत करते थे, उस समय इन्होंने कितनी बार केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया? उसमें कितनी बार केन्द्र सरकार के बारे मे लिखा? नहीं लिखा। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इन लोगों की रगो में विरोध घुस चुका है और यह परमानेंट घुस गया है, यह निकलेगा नहीं। केन्द्र में सरकार चाहे इनकी हो या यू.पी.ए. की हो। इन लोगों के दिमाग दुरूस्त नहीं हो सकते। विरोध इनके रगो में चला गया है और उसका इंजैक्शन लगा है। इन्होंने कभी भी यू.पी.ए. के समय में केन्द्र सरकार का धन्यवाद नहीं किया। क्या यू.पी.ए. की सरकार से प्रदेश को कोई सहायता नहीं मिली?

अध्यक्ष महोदय, यहां कह रहे थे कि आज टैक्सिज का हिस्सा बढ़ गया है। क्या आप कोई खैरात दे रहे हैं? वह हमारा हक़ है और हर प्रदेश सरकार का यह हक़ है। यहां टैक्स कलैक्शन होती है और वह केन्द्र सरकार के पास जाती है

17/03/2017/1500/RG/DC/2

जिसका हिस्सा हमें मिलता है। ठीक है, केन्द्र सरकार ने यदि हिस्सा बढ़ाया है, तो केवल मात्र हिमाचल प्रदेश का ही नहीं बढ़ाया अपितु हिन्दुस्तान के सारे राज्यों का हिस्सा बढ़ाया

है जिसमें हम भी शामिल हैं और वह केन्द्र सरकार को देना पड़ेगा। वे इससे इन्कार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक सर्वे करवाया जाए कि एक साल में हिमाचल प्रदेश से सेन्ट्रल ऐक्साइज टैक्स, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स कितना कलैक्ट होता है। कितने हजार करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश से टैक्स कलैक्शन करके केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। उसी के आधार पर हमें हिस्सा मिलता है। हमारा पहाड़ी प्रदेश है और हमारे लिए स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। ये लोग रोज़ यहां जितने भी भाषण देते हैं उनमें हमेशा ही इस बात की प्रशंसा करते रहते हैं कि नरेन्द्र भाई मोदी-नरेन्द्र भाई मोदी। तो वे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। प्रदेश के इन्चार्ज भी रहे हैं। वे आप लोगों के शुभचिन्तक हैं और आप लोग ही दिल्ली में जाकर कान भरते रहते हैं। यदि वह देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हिमाचल प्रदेश के भी प्रधानमंत्री हैं। जैसे जगजीवन पाल जी ने कहा, आजकल व्हाट्स ऐप पर बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री का मैसेज आ रहा है। पूरे देश के ही नहीं वे तो विदेश के भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जैसे वास्कोडीगामा रास्तों की खोज करने के लिए भ्रमण करते थे, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व में रास्तों की खोज करने के लिए घूमते हैं। उन्हें हिन्दुस्तान की चिन्ता नहीं है। जितना समय उन्होंने विदेशों में गुजारा, अगर वे इतना हिन्दुस्तान के राज्यों में गुजारते, तो शायद हिन्दुस्तान कहीं आगे बढ़ जाता। ---(व्यवधान)--

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जनता सब जानती है कि कौन कितने पानी में है? यहां श्री सुरेश भारद्वाज जी कह रहे थे कि यहां रजवाड़ाशाही को खत्म करके हिमाचल प्रदेश बना। वे बहुत जोर-जोर से भाषण दे रहे थे। वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं और संसद में भी रह चुके हैं। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, हालांकि उनको भी पता है और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता भी जानती है। जब बुशैहर स्टेट में श्री वीरभद्र सिंह जी का जन्म हुआ था, तो उसी समय विधाता ने यह लिख दिया था कि भले ही छोटी-छोटी रियासतें खत्म हो जाएं, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश बनेगा उसका लोकतांत्रिक राजा वीरभद्र सिंह जी बनेगा।

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2017/1505/MS/AG/1

श्री संजय रतन जारी------

और आज राजा वीरभद्र सिंह लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेसी में चुनकर बहुमत से इस सरकार को बनाकर यहां आपके सामने बैठे हुए हैं। -(व्यवधान)- यह खुश करने की बात नहीं है बल्कि यह हकीकत है और आप लोग हकीकत से वाकिफ नहीं होना चाहते। श्री जगजीवन पाल जी ठीक कह रहे थे कि आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। आप संस्थान खोलने का विरोध कर रहे हैं चाहे वे शिक्षण संस्थान हों, स्वास्थ्य संस्थान हों या अन्य दूसरे संस्थान हों। इन्होंने ठीक कहा कि यदि आप लोगों में हिम्मत है तो इस सदन के अंदर नहीं बल्कि बाहर जाकर बोलो। ये प्रैस के बन्धु ऊपर प्रैस गैलरी में बैठे हुए हैं। ये भी उसमें शामिल हैं क्योंकि कई बार कुछ अखबारों के बन्धु भी लिख देते हैं कि माननीयों के लिए ये चीज भी हो गई और माननीयों के लिए वो चीज भी हो गई। ये अखबारों में लिखते हैं *** वही हिसाब आपका है। आपको हर चीज में नुक्ताचीनी करने की आदत है। आप विरोध भी कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की तरक्की भी चाहते हैं। मुख्य मंत्री महोदय की नज़र में पूरा हिमाचल प्रदेश एक है। .(व्यवधान). मैं किसी से नहीं डरता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने पत्रकारों के लिए कह दिया है। ठीक है, पत्रकार बन्धुओं ने लिखा है। मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब हमने मुख्य मंत्री जी से आप लोगों की तनख्वाह इस सदन में बढ़वाई तो किसी ने विरोध किया? आप में से किसी ने भी विरोध नहीं किया। अगर आप सोचते कि हिमाचल प्रदेश कर्ज़ में डूबा हुआ है तो आप लोग मना करते कि हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, ऐसा सिर्फ कांग्रेस के लोग चाहते हैं। परन्तु उस वक्त आपने भी तालियां बजाईं क्योंकि आपको भी ज्यादा तनख्वाह चाहिए थी। वही हिसाब पत्रकार बन्धुओं का है। *** इस तरीके का विरोध नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों में रत्ती भर भी हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो जगजीवन पाल जी ने ठीक कहा कि जाओ और प्रैस कान्फ्रैंस करो। मैं प्रैस के बन्धुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जितने यहां विपक्ष के लोग बैठे हैं, जिस-जिस ने यहां विरोध किया है,

———————————————————————————

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

17/03/2017/1505/MS/AG/2

आप कल अखबार में छाप दीजिए कि इन-इन लोगों ने कहा है कि हमारे स्कूल, अस्पताल, तहसीलें, उप-तहसीलें और सब-डिवीजन्ज बन्द होने चाहिए। फिर देखते हैं कि आप लोग कैसे चुनाव के समय जनता के बीच जाते हैं और लोग कैसे आपसे हिसाब मांगते हैं। परन्तु आप में हिम्मत नहीं है। आप यहां सदन में ऐसा कहेंगे और जब बाहर जनता के बीच में जाएंगे तो कहेंगे कि ये तो हमें भाजपा की तरफ से भाषण देना ही पड़ना था। ये शब्द आपके होंगे। विरोध केवल-मात्र विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छा होता अगर आप इस बजट अनुमान के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में ऐसी चीजें सुझाते, ऐसे संसाधन सुझाने की बात करते जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी बढ़ती।

आप विरोध कर रहे हैं कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना दिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के समय में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं बनें? आपने भी हारे हुए लोग बनाए थे। जब आप बना सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुख्य मंत्री जी, इनकी एक पीड़ा है और वह पीड़ा मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं तथा आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि इनकी जो पीड़ा है उसकी दवाई आपके पास है। अध्यक्ष जी, पूरे हिमाचल प्रदेश में अथाह विकास हो रहा है। किन्नौर से लेकर चम्बा तक और लाहौल से लेकर सिरमौर तक अथाह विकास हो रहा है। उस विकास की जो गाथा लिखी जा रही है उस पर हर जगह मुख्य मंत्री जी आपका स्टोन लग रहा है और उस पर लिखा जा रहा है कि श्री वीरभद्र सिंह के कर-कमलों द्वारा यह उद्घाटन सम्पन्न हुआ, श्री वीरभद्र सिंह के कर-कमलों द्वारा यह भूमि पूजन हुआ। इनकी पीड़ा यह है कि इनका भी आपके साथ नाम लगना चाहिए क्योंकि ऐसे इनको मौका नहीं मिलेगा। ये चाहते हैं कि उस प्लेट के ऊपर इनका भी नाम लग जाए इसलिए ऐसे कोई नॉर्म्ज बना दिए जाएं कि जब आप उद्घाटन या भूमि पूजन के लिए किसी क्षेत्र में जाएं तो उस पट्टिका में इन इलैक्टिड विधायकों का नाम भी लिखा जाए। तब जाकर इनकी पीड़ा खत्म होगी जिसकी दवाई आपके पास है। ये चाहते हैं कि जब लोग श्री वीरभद्र सिंह को याद करे तो इनको भी छोटा-मोटा कोई सोच लें कि ये भी उस वक्त विधायक थे। ये ऐसा चाहते हैं। .(व्यवधान). आपको उनकी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। वे हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं। जिस तरीके से

आपने अपनी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को सरकार बनने पर ओहदे दिए थे उसी तरीके से हमारी सरकार ने भी उनको ओहदे दिए हैं और वे कन्स्टीच्यूशनल ओहदे हैं। वे हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना रखे हैं। जब कोई कारपोरेशन/बोर्ड बनता है तो उसमें चेयरमैन

17/03/2017/1505/MS/AG/3

और वाइस चेयरमैन का पद क्रिएट किया जाता है। उसी के आधार पर हमने वे बनाए हुए हैं। उसकी आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने साथ इनको भी मौका दे दें क्योंकि पता नहीं इनको भविष्य में मौका मिले या न मिले। इसलिए ऐसे नॉर्म्ज बना दिए जाएं ताकि इनका नाम भी उस उद्घाटन पट्टिका में शामिल हो जाए। .(व्यवधान). पक्का है,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

17.03.2017/1510/जेके/एजी/1

श्री संजय रतनः------जारी-------

सरकार में हम ही बैठेंगे आप वहीं बैठेंगे हंस राज जी, आप चिन्ता न करो। यहां पर डी0पी0आर्ज0 की बात हुई कि हमारी डी0पी0आर0 नहीं बन रही है। बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनकी डी0पी0आर्ज0 बनी। कई जगह कई कारण रहे हैं। फोरैस्ट लैंड है, कई दूसरे कारण हैं जहां पर डी0पी0आर्ज0 नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी ने इसलिए डी0पी0आर0 नहीं बनाई कि वह विपक्ष का चुनाव क्षेत्र है। मेरे बड़े भाई रविन्द्र रवि जी यहां पर बैठे हैं। मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ जाने का मौका मिला। बनखंडी में 23 करोड़ रूपए की आई0पी0एच0 की स्कीम सेंक्शन हुई। अगर डी0पी0आर0 नहीं बनती तो सेंक्शन भी नहीं होती। डी0पी0आर0 बनी तो सेंक्शन हुई। भले ही वह स्कीम विधायक प्राथमिकता में हो। मैं विधायक प्राथमिकता की ही बात कर रहा हूं कि यहां कहते हैं कि डी0पी0आर0 नहीं बनती है। डी0पी0आर्ज0 बनी हैं। 23 करोड़ की आपकी बनी और सड़कों की बनी। ऐसे ही जसवां चुनाव क्षेत्र की बनी और दूसरे चुनाव क्षेत्रों की बनी। मुख्य मंत्री जी के ज़हन में कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, एक समान विकास है।

अगर मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन डिग्री कॉलेज खुले हैं तो भाई रविन्द्र जी के भी तीन डिग्री कॉलेज खुले हैं। जसवां विधान सभा क्षेत्र में भी तीन डिग्री कॉलेज खुले हैं। ढलियारा में आपका है, देहरा चुनाव क्षेत्र में है। वह भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है। इन्होंने टेक ओवर किया है। देहरा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कॉलेज दिया है। हरिपुर में भी कॉलेज है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि धूमल जी ने नहीं दिया। मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन डिग्री कॉलेज हैं तो आपके भी तीन डिग्री कॉलेज हैं। जसवां में भी तीन डिग्री कॉलेज हैं। जरयाल जी, आपने डिमाण्ड ही नहीं की होगी और आप मुख्य मंत्री के पास जाते ही नहीं है। अगर आप मुख्य मंत्री महोदय के पास मांग करेंगे और लोगों की मांग होगी तो आपके भी खुलेंगे। मुख्य मंत्री जी के ज़हन में कभी क्षेत्रवाद नहीं रहा। मुख्य मंत्री जी के ज़हन में कभी भाई-भतीजावाद नहीं रहा। येह सिर्फ आप लोगों की उपज है। क्षेत्रवाद की राजनीति करना, भाई-भतीजावाद की राजनीति करना, जात-पात की राजनीति करना, यह केवलमात्र आपकी सोच है। वीरभद्र सिंह जी की सोच नहीं है। तीन कॉलेज बंजार में भी है। इसी तरह से कई जगह हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब मैंने बी0डी0ओ0 ऑफिस में पैसे का यहां पर प्रश्न लगाया था कि बी0डी0ओ0 ऑफिस में बहुत ही अनस्पैंट पैसा पड़ा था

17.03.2017/1510/जेके/एजी/2

, अरबों रूपया पड़ा है। माननीय मुख्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री महोदय ने उसका ज़वाब दिया। एकदम से आप लोगों ने उस प्रश्न की सप्लीमेंटरी बदल दी। आप उस प्रश्न को किसी और जगह ले गए। आप उस प्रश्न को स्वच्छ भारत की ओर ले गए। आपने स्वच्छ भारत के ऊपर सप्लिमेंटरी करनी शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ भारत में ईनाम मिला। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार बधाई की पात्र है। आप लोगों ने कहा कि गलत आंकड़ें केन्द्र सरकार को दिए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार वर्ष 2012 में थी। अगर आपको शक होगा और यह मैं माननीय सदन में कह रहा हूं, वर्ष 2012 में केन्द्र में यू0पी0ए0 की सरकार थी और हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार थी। जो उस वक्त सैंसस हुआ वह किसने भेजा। वह आपकी सरकार ने भेजा। आपने गलत आंकड़ें केन्द्र को क्यों भेजे? अगर आपने सही आंकड़ें भेजे होते तो कोई ऐसा घर, ऐसा संस्थान नहीं रहता जिसमें शौचालय नहीं बनता। जो छूटे हुए शौचालय हैं, जिनकी आपने बात की

कि कई जगह शौचालय नहीं बने हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश को स्वच्छता में ईनाम मिल चुका है, वह आपकी गलती थी। आपने गलत आंकड़ें केन्द्र सरकार को दिए। आप अपनी गलती को छिपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वह भी आपका आरोप निराधार है। आपने यहां पर क्षेत्रवाद की बात की, राजधानी की बात की और कल सुरेश भारद्वाज जी बहुत ज्यादा राजधानी के ऊपर बोल रहे थे। हम इस चीज में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे ज़हन में, हमारे मुख्य मंत्री के ज़हन में और हमारी सरकार के ज़हन में कोई क्षेत्रवाद नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय निचले हिमाचल में वर्षो से सर्दियों में जाते रहे हैं। वहां से महीना-दो महीना सर्दियों में सरकार को चलाते आए हैं। आपकी सरकार आई आपने भी उस परम्परा का निर्वाह किया। आपने भी वहां से सरकार चलाई। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छा काम किया कि ऐसे किराये के भवनों से सरकार चलानी, किराये के भवनों में रहना, माननीय मुख्य मंत्री जी ने धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी डिक्लेयर कर दिया।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

17.03.2017/1515/SS-AS/1

श्री संजय रतन क्रमागतः

इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? हमारे आदरणीय बड़े भाई सुरेश भारद्वाज जी कल बहुत चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि शिमला का अस्तित्व खत्म हो गया। शिमला का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। शिमला हिमाचल प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और किसी वक्त हिन्दुस्तान की राजधानी रही है। शिमला को सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। न ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है कि शिमला को डिलीट करके धर्मशाला को अपग्रेड किया जाए। धर्मशाला में अगर एक महीने या दो महीने सर्दियों में सरकार चलती है तो इसके लिए मैं नहीं समझता कि आपको कोई विरोध करना चाहिए। आपको हमारा सहयोग करना चाहिए। आपने जगजीवन पाल जी को कहा

कि आप कांगड़ा के विरोधी हैं। कांगड़ा से आपने कभी मुख्य मंत्री नहीं बनाया। मुख्य मंत्री कांगड़ा, शिमला, चम्बा या हमीरपुर से नहीं बनता है। सुरेश भारद्वाज जी, मुख्य मंत्री वह बनता है जिसको विधायक दल का समर्थन हो और हाईकमान का आशीर्वाद हो। आपके मुख्य मंत्री, माननीय प्रेम कुमार धूमल जी बने, उस वक्त शांता कुमार जी भी लाइन में थे। उस वक्त किशोरी लाल जी भी पहले शांता कुमार जी के साथ लाइन में थे, कंवर दुर्गाचंद जी भी लाइन में थे मगर समर्थन शांता कुमार जी को था, हाईकमान का समर्थन भी शांता कुमार जी को था और विधायकों का समर्थन भी शांता कुमार जी को था तो वे कांगड़ा से मुख्य मंत्री बन गए। जब बाद में विधायकों का समर्थन माननीय प्रेम कुमार धूमल साहब को था तो धूमल साहब मुख्य मंत्री बन गए। कल आपको (श्री सुरेश भारद्वाज) समर्थन हो जायेगा तो शिमला से आप भी इसके लिए क्लेम कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सपने देख सकते हैं। कांगड़ा के लोग विरोध के मारे वीरभद्र सिंह जी को मुख्य मंत्री नहीं बनाते। वीरभद्र सिंह जी अगर मुख्य मंत्री हैं तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के सी0एल0पी0 के लीडर हैं। विधायकों का समर्थन वीरभद्र सिंह जी को है। हाईकमान का आशीर्वाद मुख्य मंत्री जी के साथ है। इसलिए मुख्य मंत्री हैं। किसी की खैरात पर मुख्य मंत्री नहीं हैं। कांगड़ा के विरोधी होने के ऊपर शिमला के मुख्य मंत्री नहीं हैं। मुख्य मंत्री हमेशा समर्थन से बनते हैं। भविष्य में क्या होगा, कौन बनेगा, कहां से बनेगा, यह भी विधायकों के ऊपर निर्भर करता है। आज पूरी सी0एल0पी0 मुख्य मंत्री, वीरभद्र सिंह जी के साथ है और हाईकमान भी वीरभद्र सिंह जी के साथ है इसलिए हमारा प्रतिनिधित्व वीरभद्र सिंह जी कर रहे हैं। छठी बार प्रतिनिधित्व किया है और सातवीं बार भी वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री बन

17.03.2017/1515/SS-AS/2

कर आयेंगे। यह मैं कहना चाहता हूं। न तो हमारे ज़हन में क्षेत्रवाद है और न ही मुख्य मंत्री के ज़हन में है। मुख्य मंत्री महोदय पूरे हिमाचल का एक समान विकास करवा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो विकास माननीय मुख्य मंत्री, वीरभद्र सिंह जी पूरे हिमाचल का करवा रहे हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश को एक माला में पिरो रहे हैं जैसे डॉ0 वाई0एस0 परमार ने इस प्रदेश का निर्माण किया, उसी तरीके से मुख्य मंत्री जी आज नये हिमाचल को बनाकर एक आधुनिक हिमाचल बना रहे हैं। उसमें रंग भर रहे हैं जिसकी कल्पना डॉ0 वाई0एस0 परमार ने की थी। उस कल्पना को और अच्छा रूप वीरभद्र सिंह जी दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपका भी नज़रिया चेंज होना चाहिए। आपके नज़रिये में भी जो प्रदेश हित के लिए

बात है उसको आपको यहां पर रखना चाहिए और मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आपको ये सुझाव देने चाहिएं, बताना चाहिए कि मुख्य मंत्री जी प्रदेश के हित में यह चीज़ है इसको आप करिये। मुख्य मंत्री जी उसे करेंगे। आप रोज़ नरेन्द्र मोदी जी का गुणगान करते हैं। आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे। आज आपकी केन्द्र में सरकार है। मैंने सुबह भी रवि जी से निवेदन किया था कि मेरी एक 200 करोड़ रुपये की सिंचाई की मीडियम इरिगेशन स्कीम लम्बित पड़ी हुई है, उसकी डी0पी0आर0 केन्द्र को गई है आप पैसा लाईये। हम आपका धन्यवाद करेंगे। आपका 900 करोड़ रुपये का धौलासिद्ध प्रोजैक्ट आज गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के पास पड़ा है, आपकी सरकार है, उसको लाईये। सैंक्शन करवाईये। हिमाचल के लिए वह 65 मैगावाट की बिजली पैदा करेगा और हिमाचल आर्थिक रूप से सम्पन्न होगा, उस प्रोजैक्ट को आप सैंक्शन करवाईये। इस तरीके से कई ऐसे प्रोजैक्टस हैं जो केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं। केन्द्र सरकार से जो हमें मिलना है उसको लाईये। स्मार्ट सिटी के मामले में आप धर्मशाला से क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं। आप भारद्वाज जी, शिमला को भी ले आईये। सोलन, हमीरपुर को ले आईये। आप 12 के 12 जिलों को स्मार्ट सिटी बना दीजिये। आप नरेन्द्र मोदी जी का इतना गुणगान करते हैं, वे यहां के इंचार्ज रहे हैं उनको हिमाचल प्रदेश की हर भौगोलिक स्थिति का पता है और प्रधान मंत्री के पास ऑवर एंड एबव डिस्क्रिशनरी पावर्ज़ होती हैं, आप उनके पास जाईये और उनसे निवेदन करिये कि हमें हिमाचल प्रदेश में 12 स्मार्ट सिटीज़ दे दीजिये। हम आपको तब मानेंगे। हम खुले मन से आपका धन्यवाद करेंगे।

17.03.2017/1515/SS-AS/3

अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हमें भी साथ ले चलिये। हम भी आपके साथ चलेंगे। हमें जाने में कोई गुरेज़ नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश को कोई चीज़ मिलती है तो हम खुले मन से उनका धन्यवाद करेंगे और आपका भी धन्यवाद करेंगे। जहां तक कर्ज़ की बात है। आपने अपने समय भी भी कर्ज़ लिया, हमने भी कर्ज लिया है

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2017/1520/केएस/एजी/1

श्री संजय रतन जारी---

हम भी सरकार को चलाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप नरेन्द्र भाई मोदी जी, प्रधान मंत्री जी के पास जाइए। कम से कम और कुछ नहीं तो जितना भारतीय जनता पार्टी के समय में आपने कर्ज लिया उतना पैकेज तो हिमाचल के लिए ले कर आइए। जब केन्द्र में हमारी सरकार बनेगी, हम उसको भी ले आएंगें। आपने भी अपने समय में कर्ज लिया है, उसको ले आइए। हम धन्यवाद करेंगें। पैकेज़ लाओ। यहां पर पूरे ध्वनिमत से प्रस्ताव होना चाहिए। आज केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । हिमाचल की खुशकिस्मती यह होनी चाहिए कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री वे हैं जो कभी आपके इन्चार्ज हुआ करते थे। उनको हिमाचल प्रदेश के बारे में सभी कुछ मालूम है। वे शिमला में भी आते थे, धर्मशाला भी जाते थे, हमीरपुर भी जाते थे और मण्डी में भी जाते थे परन्तु मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि वे मण्डी में आए, हिमाचल में आए लेकिन वे एक भी पैसा हिमाचल के लिए नहीं दे कर गए, जहां के वे इन्चार्ज हुआ करते थे। आप जाओ और पैसा ले कर आओ। हम खुले मन से आपका धन्यवाद करेंगें। हम भी आपके साथ चलेंगें। हमें भी खुशी होगी कि एक व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश का इन्चार्ज रहा हो, जिसको हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का पता हो, वह आदमी हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री है और उसने हिमाचल प्रदेश के लिए यह किया। आप जाएं और उनसे पैसा ले कर आओ, हम आपको धन्यवाद करेंगें।

17.03.2017/1520/केएस/एजी/2

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट अनुमान वर्ष 2017-18 के इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं, मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे आपने पिछले सालों में अपने बजट अनुमान प्रस्तुत किए और इस सदन ने ध्वनिमत से उनको पास किया और पिछले सालों में जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश का एक समान विकास हुआ, उसी तरीके से 2017-18 के जो बजट अनुमान हैं, ये भी इस माननीय सदन में ध्वनि मत से पास होंगें और आप इस साल भी उनको मध्यनज़र रखते हुए हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं रखेंगें और हिमाचल प्रदेश एक समान

विकास में आपकी रहनुमाई में आगे बढ़ेगा और हिमाचल प्रदेश की जनता पुनः आपको फिर अपनी कमान देगी, हिमाचल प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाएगी। आप सातवीं बार मुख्य मंत्री बनेंगें और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी आपकी रहनुमाई में इस माननीय सदन में दोबारा से आने का मौका मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

17.03.2017/1520/केएस/एजी/3

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्षः चर्चा में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता।

अध्यक्षः आपने बोला फिर उन्होंने बोला । अब क्या आप उसका जवाब देंगें? जवाब तो माननीय मुख्य मंत्री ने देना है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? यह बजट पर चर्चा है इसमें प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा क्लैरीफाई करना चाहता हूं। कुछ चीज़ रिकॉर्ड में गलत चली जाए तो वह ठीक बात नहीं है और उसको सुधारा जाना चाहिए। यहां पर वर्ष 2011 की सैंसस का जिक्र हुआ। सैंसस गवर्नमैंट ऑफ इंडिया करती है। उसके पैरा मीटर्ज़ अलग होते हैं। जनगणना का एक अलग प्रोविज़न होता है लेकिन जो मैंने ओ.डी.एफ. का जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश को बाह्य शौचमुक्त घोषित किया, यह टोटल सैनिटेशन केम्पेन के अंतर्गत आता है और इसकी अधिकांश औपचारिकताएं हमारी सरकार के दौरान पूर्ण हो चुकी थी और सारी बातें हमने केन्द्र तक पहुंचाई थी। केन्द्र सरकार ने उनको स्वीकार भी कर लिया था लेकिन बाद में किसी कारण से उसको रोक दिया गया था अभी वह हुआ है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। (व्यवधान) इसलिए रिकॉर्ड में जो गलत चीज़ गई है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह 2012 के आंकड़ों के हिसाब से हुआ है। अब जो आप कह रहे हैं कि कुछ जगह नहीं है, वह उसके बाद के बने हुए मकान हैं।

संसदीय कार्य मंत्री अ0व0 की बारी में---

17.3.2017/1525/av/dc/1

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा जो कि दिनांक 14.3.2017 को आरम्भ हुई थी (---व्यवधान---) एक मिनट। (---व्यवधान---)

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल आपसी सहमति से यह निर्णय हुआ था कि दो सदस्य विपक्ष से बोलेंगे और दो हमारी तरफ से बोलेंगे। उसमें इनकी तरफ से जय राम जी और रणधीर जी का नाम था तथा सत्ता पक्ष से जगजीवन पाल जी व संजय रतन जी का नाम था। माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र सिंह जी से आग्रह है कि कल हुए फैसले के मुताबिक चलें और माननीय मुख्य मंत्री जी के जवाब को आगे बढ़ने दें। (व्यवधान--) नहीं, कल ही फैसला हो गया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी तीन बजे बोलेंगे, अब तो समय उससे ज्यादा हो गया है। मैं माननीय सदस्य से रिक्वैस्ट करूंगा (-व्यवधान) बिल्कुल, सुरेश भारद्वाज जी आपकी तरफ से रिप्रेजैंट कर रहे थे और यह सहमति हुई थी। (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने (श्री रविन्द्र सिंह) नाम नहीं दिया । (---व्यवधान--) मेरे पास आपका कोई नाम नहीं आया है। (---व्यधान---) आपका नाम अगर लिस्ट में होता तो मैं क्यों नहीं पुकाराता? मैंने किसी को बोलने के लिए मना नहीं किया है। मैंने कहा कि आपका नाम अगर (---व्यवधान---) I won't allow. I stop the discussion. मैं चर्चा को विराम देता हूं।

अब वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा जो कि दिनांक 14.3.2017 को आरम्भ हुई थी। इसमें कुल 39 सदस्यों ने भाग लिया और यह चर्चा 16 घंटे 25 मिनट तक चली। अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

17.3.2017/1525/av/dc/3

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने नहीं दिया, यह डैमोक्रेसी में सबसे बड़ा कुठाराघात है। चर्चा पर बोलने नहीं देना (व्यवधान-)

Speaker: What is democracy, your name is not here. माननीय सदस्य, मेरे पास आपका नाम नहीं है। (---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : यह आपका कोई पैतृक अधिकार नहीं है। आपकी पार्टी को आपका नाम नम्बर एक पर डालना चाहिए था। (---व्यवधान---) नहीं, आपके यहां इतने मैम्बर बोले और आप इतने वरिष्ठ मैम्बर है। आपकी पार्टी की तरफ से बोलने वालों के जो नाम दिए गए हैं उसमें आपका नाम पहले होना चाहिए था।

(---व्यवधान---)

17.3.2017/1525/av/dc/2

Chief Minister: Mr. Speaker Sir, 39 Hon'ble Members of the House have participated in the budget discussion from 14th to 17th March,2017. The discussion on the budget has been in very cordial atmosphere. I want to put cordial atmosphere in inverted commas. The participation of such a large number of Members in the Budget discussion itself shows that the Budget of 2017 -18 has enthused the Hon'ble Members, as it has many new policies and programmes, benefiting all sections of the society. I am sorry that Hon'ble Member Shri Ravinder Singh brought the matter and he has also given the name for discussion.

Speaker: No I didn't had his name.

Chief Minister: I will be very happy if such a senior Member of the BJP should have been should have been among the first two to speak. It is for them to give the name and for you to accept it. It is not for us to give his name. People of Himachal Pradesh and Members from Treasury Benches have immensely appreciated the budget. However a feeble criticism has come from the Opposition benches. Now, I will reply, one by one on the important issues raised in the Hon'ble House by the Hon'ble Members.

Continued by DC in eng….

17.3.2017/1530/TCV/dc/1

Continued by Hon'ble Chief Minister:-

Mr. Speaker Sir, Hon'ble Shri Prem Kumar Dhumal , Shri Suresh Bhardwaj, Col. Inder Singh, Dr. Rajiv Bindal and Dr. Rajiv Sehjal have mentioned about certain things. They have talked about the loans taken by the State Government over and above the limit prescribed under Article 293(3) of the Constitution of India and there is no Prudent Financial Management.

The increase in the debt during the recent years in mainly because of sharp reduction in Revenue Deficit Grant during the years 2013-14 and 2014-15 coupled with the increased salary burden due to pay scale revision by Punjab Government and followed by HP Government in 2012. The Revenue Deficit Grant which was awarded was Rs. 2,223 crores for the first year (2010-11) of

the award period reduced sharply to Rs. 406 crores for the last year i.e. (2014-15) of the 13th Finance Commission's award period.

Moreover, there was overestimation in the recommendations of the 13th Finance Commission on account of share in central taxes for the year 2013-14 and 2014-15. Actual receipt during these two years remained Rs. 528 crores less as compared to the amount estimated by the 13th Finance Commission. Thus in 2013-14 and 2014-15 the State had to borrow more than 3 % of the GSDP, to keep the pace of the development in the State. The 14th Finance Commission had also overestimated the tax devolution for the year 2015-16 and 2017-18. During the year 2015-16, the State Government received RS. 3,611 crores as against the estimate of Rs.4,441 crores. The tax devolution will be Rs.4,343 crores during current year 2016-17 as against RS.4,778 crore estimated by the 14th Finance Commission in its recommendations. As such we

17.3.2017/1530/TCV/dc/2

have received Rs.966 crores less during first two years of 14th Finance Commission award period. This is very important point which we have to take note of.

The State Government has succeeded in bringing down the debt -GSDP ratio to 34.8 during the year 2014-15 as against 40.1 targeted by the 13th Finance Commission.

Continued by AG……

17032017/1535/AG-NS/1

Chief Minister Continues . . .

Further, the State Government has raised all market loans only after obtaining the approval of Government of India under the Article 293(3) of the Constitution of India. The efforts of the State Government have been to raise need based borrowing within authorized ceiling and during current year too we have decided not to go beyond the authorized limit.

Himachal Pradesh has very low tax base. However the State Government has been making efforts to increase tax revenue through efficient tax collection. The tax revenue of the State Government which was Rs. 4,626 crore in 2012-13 has increased to Rs. 6,341 crore in 2015-16 and likely to be increased to Rs. 7,945 crore during 2017-18.

Mr. Speaker, Sir, Hon'ble Shri Prem Kumar Dhumal, Leader of the Opposition raised the issue that the State is financially surviving on Centre's mercy. I am sorry he is very sadly missing the facts. Speaker, Sir, I wish it was so but as I have stated earlier that devolution from the Centre has decreased and we have been able to raise our own resources in past years. We have also taken selective loans to complete our schemes within the provisions of the Constitution with the permission of the Government of India. We are not raised a penny without the permission of the Government of India.

Speaker Sir, India is nothing but a Union of States. This is known to everybody. India is a Union of States. The Constitution of India prescribes a well established mechanism through the Finance Commissions to devolve funds from the Union Government to the States and Union Territories. The Finance Commission is constituted under the Article 280 of the Constitution of India and makes recommendations to devolve funds to the States for a period of five years.

17032017/1535/AG-NS/2

The Government of Himachal Pradesh has put up its case strongly before the 14th Finance Commission and the Commission was kind enough to accept our demands and recommended devolution of funds to the Union Government. The Union Government has devolved the funds to all the States including Himachal as per the recommendations of the Commission. These recommendations of the Finance Commission are based on objective criteria which are applicable to all the States without any discrimination.

Continued by AG in English . . .

17032017/1540/AG-RKS/1

Chief Minister Continues . . .

Thus, the devolution by the centre are purely as per the Constitutional provisions and have not been determined by exercising any discretion by the Union Government.

Speaker Sir, Government of Himachal Pradesh used to get plan grants from the Planning Commission. However, the present Central Government abolished the Planning Commission due to which a grant of about Rs. 3,000 crore per annum has been discontinued. Earlier, we took money also from the Planning Commission to the extent of Rs. 300/- crores every year which has been discontinued now with the formation of the NITI Ayog. This is also a serious reduction in the revenues of the State.

Mr. Speaker, Sir, Shri Prem Kumar Dhumal, Shri Maheshwar Singh, Shri Satpal Singh, Shri Inder Singh and Dr. Rajiv Sehjal have raised the issue that Budget Announcements are not being implemented.

A criticism levelled by some members of the opposition is that my Government has not implemented many Budget announcements.

I wish to strongly rebut this allegation. The State Government has implemented most of the budget announcements made in the last four budgets. However, in some cases there are delays due to forest clearances. The State Government has actively pursued forest and land clearance cases which were a major impediment to implement those schemes in spite of the fact that we had the money and cases were properly pursued, but in many cases in spite of the strenuous efforts we are not able to get forest clearances and we continue to pursue the matters. I hope that we will be able to get forest clearances in many of the cases. As soon as they are received, the projects will be implemented. This is not only about the forest land for the roads but it is also for

17032017/1540/AG-RKS/2

drinking water and Irrigation projects etc. A Committee headed by the Chief Secretary has been regularly monitoring these projects. My Government has laid special emphasis on forest clearance cases by regularly following up at District and State Headquarters. This has resulted in clearance of hundreds of DPRs which have been proposed to funding agencies.

I would like to remind the Hon'ble Members of the Opposition about the budget announcements of the previous Government. In 2008-09 Budget Speech, in para 62, new Medical Colleges were announced to be opened in Private Sector in Mandi .

Continued by AS in English . . .

17.03.2017/1545/SLS-AS-1

Hon'ble Chief Minister…continue

I would like to remind the Hon'ble members of the opposition about the Budget announcements of the pervious Government. In 2008-09, Budget Speech at para-62, New Medical Colleges were announced to be opened in Private Sector in Mandi,in that time it was in Private Sector but now we are opening in the Government Sector and Hamirpur and Una. I request the opposition benches to enlighten the House about the status of these Private Medical College. In 2009-10 Budget Speech of the BJP Government at para-49, an Engineering College was announced for Bilaspur. This announcement never saw the light of the day.

Speaker, Sir, may I say here:

मेरे ऐबों को तलाशना बंद कर दिया लोगों ने
मैंने तोहफ़े में उन्हें जब से आईना दे दिया।

पहले अपनी शक्ल आईने में देखो, फिर जाकर आप दूसरों के ऊपर टिप्पणियां करो।

Shri Prem Kumar Dhumal and Shri Suresh Bhardwaj raised issued of Dharamshala as second capital of the State.

Speaker, Sir, During my winter visit to Kangra, I had announced that Dharamshala will be made second Capital of the State. To meet the aspirations of the people of merged areas, my Government had set up Vidhan Sabha in Dharamshala. Since 2005, Winter Session of the State Legislative

Assembly is being convened there regularly. In every year during winter months, my Government has been undertaking official tours to Kangra, Hamirpur, Una and Chamba for redressal of public grievances and for disposal

17.03.2017/1545/SLS-AS-2

of other administrative business. Meetings of various boards constituted by the Government are also being held at Dharamshala during winter tour.

Zonal Government office of several Department like Chief Engineer PWD, Chief Engineer IPH, Chief Engineer HPSEBL, HP Board of School Education, Chief Conservator of Forests, Divisional Commissioner and IG Police etc. have already been established at Dharamshala. Most of these offices are set up by Congress Government.

These measure taken by the Government from time to time have been much appreciated by the people of the area and has ensured emotional integration of these areas with the rest of the State.

Mr. Speaker, Sir, if we have a Administrative set-up at Dharamshala as of now it does not any way lower the dignity of Shimla. Shimla was the summer capital and after integration of Himachal Pradesh, Shimla became capital of Himachal Pradesh. For some time, after the partition, Shimla was also the capital of Punjab. So it is a city with a great history. We are proud that Shimla is our Capital and its remain so.

Continue by AS

17/03/2017/1550/RG/AS/1

Hon'ble Chief Minister…continue

If we move to some place for some time and give facilities to some other region or administrative facilities to them, it does mean that, in any way, it bears the importance of Shimla. Some vested interest trying to make noise of it as per the people. I am happy that the people are wiser then the people who are instigating them. I want to make it carry forward. There is not question of moving Secretariat lock, stock and barrel to Dharamshala.

श्री रणधीर शर्मा : फिर क्यों बनाया?

मुख्य मंत्री : इसलिए बनाएंगे कि more officers are coming in future. Because set up of some of the offices there. यहां कर्मचारियों को यह बताया जा रहा है कि नई राजधानी बन रही है और आपके दफ्तर यहां से वहां जाएंगे। आपको वहां जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। If you open some office there it will that office which will be new office which will be established there. इसलिए आप इस किस्म की झूठी बातें करके लोगों को न बहकाएं और उनको गुमराह करने की कोशिश मत करिए। when you say that it is the second capital it so. It is the second Capital of the Himachal Pradesh. यदि आपको तकलीफ है, तो आप अकेले (स्वयं) से ही बोलिए। I have not bothered what you say about it. हम वह कर रहे हैं जो जनता के हित में है। Which for the unity and integrity of Himachal Pradesh and it is for the betterment of all regions of Himachal Pradesh. आप लोग पहले से ही जब से आपने चुनाव लड़ा, शुरू से आप लोग निचला पहाड़, ऊपर का पहाड़, नया हिमाचल और पुराना हिमाचल, इस किस्म के नारे देते रहे हैं और लोगों को गुमराह करते रहे हैं। लेकिन आज अब लोग इस नारे से गुमराह होने वाले नहीं हैं जिसका आपको दुःख है। don't read in it what is not it.

Hon'ble Shri Prem Kumar Dhumal raised the issue that the growth in Gross State Domestic Product (GSDP) had declined to 6.8 percent.

17/03/2017/1550/RG/AS/2

Mr. Speaker, Sir, Economic growth of Himachal Pradesh is predominantly governed by agriculture/horticulture and allied activities. Any fluctuation in its production has overall impact on other sectors via input linkages. The growth in Gross State Domestic Product (GSDP) during 2016-17 is estimated at 6.8 percent. This attributable to weather uncertainties this year which resulted in decrease in Agriculture and Horticulture production particularly, apple. Demonetization adversely affected Trade and Tourism sectors. National Growth has been estimated for first three quarters of 2016-17 and impact of demonetization on National economy has not been taken into consideration in its estimation.

Continue by DC ...

17.3.2017/1555/MS/dc/1

Continued by Hon'ble Chief Minister:-

On the other hand, growth of Himachal economy has been estimated for all the four quarters of 2016-17. In the past four years the State economy grew at an average rate of 7.4 percent as compared to National growth rate of 6.8 percent.

The issue was raised by Sh. Prem Kumar Dhumal, Sh. Maheshwar Singh, Sh. Satpal Satti, Col Inder Singh, Sh. Vikram Singh Jaryaal that what is the present status of and how many Non Government Organizations and Government Organizations are managing the Gosadaans in the State?

Speaker Sir, at the end of the year 2014-15, there were 74 Gosadans run by the Non Government Organizations with about six thousand animals. Currently, there are 129 Gosadans being run by the Non-Government Organizations and one by the State Government at Khajjiayan in Kangra district. These Gosadans have ten thousand and four hundred animals in them. The State Government has constituted Govansh Samvardhan Board to ensure smooth functioning of these Gosadans in the State.

Again, Sh. Prem Kumar Dhumal also raised that Himachal was ranked first as destination by various agencies in 2012 whereas it has slipped down to seventeenth rank in the recent rankings done with regard to the ease of doing business.

Speaker Sir, two rankings mentioned by the Hon'ble Leader of Opposition have been made by following different methodologies and have entirely different context. The first ranking done by a famous media group in the year 2012 was mainly based on the socio - economic indicators including food grains yield, ratio of area under cash crops, literacy rate, girl enrolment

17.3.2017/1555/MS/dc/2

ratio, sex ratio, infant mortality rate etc. These yardsticks generally assess the States primarily on social sector performance indicators. The recent ranking done by the World Bank is based on an entirely different set of indicators like access to information and transparency, online single window mechanism, simplification of procedures, obtaining NOCs/ permits/clearances under various Acts and inspection procedures etc. In the World Bank assessment done in the Year 2016, our State has been ranked seventeenth by scoring sixty six percent points. Out of 340 action points we were implementing 220 points.

This year, my Government is vigorously working on the pending points to bring our State in the category of top ranked States with regard to the ease of doing business. So these keep on fluctuating and sometime different surveys have different bases for the for awarding the position.

17.3.2017/1555/MS/dc/3

Prof. Prem Kumar Dhumal: Will you yield for as minute.

Speaker: Prof. Prem Kumar Dhumal Ji want to say something.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी प्वाइंट-वाइज उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप डेलीबरेटली कुछ वाइटल इन्फोरमेशन नहीं दे रहे हैं।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा------

17.03.2017/1600/जेके/डीसी/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः---**जारी**----

आपने डैफिसिट ग्रांट का डिफरैंस बताया वह 945 करोड़ का आप कह रहे हैं कि अन्तर रहा। कर्ज़ा आपने 4500 करोड़ रूपए का फालतू ले लिया। 945 करोड़ अगर कम भी आया तो 4500 करोड़ रूपए का कर्जा लेने का औचित्य क्या है? मैंने एक प्वाईंट और रेज़ किया था वर्ष 2015-16 में 11 महीने की तनख्वाह शो की गई। उसमें पैंशन भी और तनख्वाह भी बताई गई। उसमें आप साइलैंट हैं। आपने कहा कि devolution of Central share और रेवन्यू डैफिसिट के कारण आपको कमी आई है। मैं जानना चाहूंगा और बजट स्पीच में आपने माना है कि लगभग 66 परसेंट devolution of Central share and taxes और

दूसरा जो रेवन्यू डैफिसिट ग्रांट है उन दोनों को मिला करके 65 प्वाईंट कुछ बनता है लगभग 66 प्रतिशत। आपने ही कहा कि 22.55 परसेंट आप कर्ज़ा लेंगे। तो 88.10 एग्जैक्ट बनता है। इन बातों पर ये साइलैंट है। अगर रेवन्यू डैफिसिट ग्रांट कम हो गई, डीवेल्युएशन ऑफ सैंट्रल टैक्सिज़ में भी कमी आ गई तो फिर उसका आपके बजट में 66 प्रतिशत कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ? आपने एक बात का और ऑर्गुमेंट दिया, वह आपने नहीं दिया, आपके ऑफिसर्ज़ ने लिख कर दिया कि 'Revision of Grades'. रीविज़न ऑफ ग्रेड्ज़ हो गया 2011-12 में, हमने 2012 में इम्पलीमेंट कर दिया। उसका इम्पैक्ट 2014-15 में, 2015-16 में बता रहे हैं। आपने कहा फाईनैंस कमिशन के कारण आपकी रेवन्यू डैफिसिट ग्रांट कम हो गई, मुख्य मंत्री महोदय, जो 13वां वित्तायोग था, उसमें 20,600 करोड़ हिमाचल प्रदेश को रेवन्यू डैफिसिट ग्रांट के तौर पर मिला था। 14वें वित्तायोग में मिल रहा है 40,625 करोड़, तो यह कम हुआ या डबल हो गया? फोरैस्ट क्लीयरैंसिज़ के कारण कुछ काम रुके हैं लेकिन गौ सदन बनाने हैं, आपने खुद ही कहा कि हम पंचायतों को ग्रांट देंगें, एन.जी.ओज़ को ग्रांट देंगें। हमने पूछा था कि किस-किस पंचायत को दी, किस-किस एन.जी.ओ. को दी, कितनी दी, कितने गौ सदन बनें? आपने हमसे कहा कि आपने घोषणाएं की थी प्राईवेट मैडिकल कॉलेजिज़ की। सोलन जिला में बद्दी में नहीं बना लेकिन सोलन के पास महर्षि मार्कण्डेश्वर प्राईवेट मैडिकल कॉलेज बना । नैरचौक में ई.एस.आई. मैडिकल कॉलेज, हमीरपुर में जो आपको फोरैस्ट क्लीयरैंस

17.03.2017/1600/जेके/डीसी/2

की दिक्कत आई, और अब भी आ रही है। जो गवर्नमैंट कॉलेज बनना है, उसमें अब भी आपको दिक्कत आ रही है। हमने जो प्राईवेट लैंड अलॉट की थी, उसमें फोरैस्ट क्लीयरैंस ही नहीं मिली थी। ऊना और सरकाघाट में भी हमने इन्वाइट किए थे। उसमें हमने पहले ही कहा था प्राईवेट पार्टीज़, इसमें तो कहा है कि सरकार करेगी, सरकार तो फैसिलिटेट करेगी इसलिए जो तथ्य आपको बताए गए हैं वे सही नहीं है। जो आप उत्तर दे रहे हैं, ठीक

है आप वह पढ़ रहे हैं जो आपको लिखकर दिया है लेकिन यह हाऊस के लिए मिसलीडिंग है। अध्यक्ष जी, मुझे कहीं अरजैंट जाना है इसलिए मैंने निवेदन किया है।

अध्यक्ष जी, ऊपर-नीचे का इश्यू तो किसी ने खड़ा ही नहीं किया। नया हिमाचल, पुराना हिमाचल।

Chief Minister: This is your Election Manifesto.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः राजधानी बना रहे हैं तो हमने पूछा कि उसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगें। आप कह रहे हैं कि log stock and barrel नहीं ले जाएंगें। दफ्तर नहीं जाएंगें, नए दफ्तर बनाएंगें। शिमला में कर्मचारियों के लिए तो क्वार्टर बन नहीं रहे हैं और वहां पर नए दफ्तर बना देंगें? इसलिए गुमराह करने की कोशिश आप कर रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः जब हम वहां नए दफ्तर बनाएंगें तो हम वहां कर्मचारियों के लिए क्वार्टर भी बनाएंगें। मगर जो अभी यहां पर हैं, किसी को नहीं भेजा जाएगा। स्टाफ वहीं अप्वाइंट करेंगें।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः यहां पर तो स्टाफ पूरा नहीं है, वहां क्या करेंगें? ये सचमुच में खोखली घोषणाएं हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अब जा रहा हूं।

(नेता प्रतिपक्ष के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य भी बाहर चले गए)

मुख्य मंत्री जी, एस0एस0 की बारी में---

17.03.2017/1605/SS-AG/1

Chief Minister: Mr. Speaker, Sir, the points raised by Hon'ble Leader of the Opposition are baseless, based on conjecture and wishful thinking. What I have stated is the factual position. I am speaking from the records of the State

Government and also from the records of the Central Government. मगर जहां तक यह वॉक आउट था, इन्होंने जाना था, मुझे पता है क्योंकि ये जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं। Their mentality is always dictatorial. इन्होंने (प्रो0 प्रेम कुमार धूमल) कहा कि मैं जा रहा हूं। इन्होंने कहा - "मेरा काम है तो मैं बाहर जा रहा हूं।" तो ये सारे एम0एल0ऐज़ क्यों बाहर चले गए? It was pre-planned. It doesn't matter, Sir. We are in majority here and we continue it. Whatever has been said by the Hon'ble Leader of the Opposition is baseless and not based on facts and what I have stated is authentic, based on records of the State and the Union.

Mr. Speaker, Sir, Shri Prem Kumar Dhumal, Dr. Rajiv Bindal, Shri Maheshwr Singh and Shri Inder Singh raised some developmental issues and also raised issue regarding expenditure of the State.

Speaker Sir, many Opposition Members have raised the issue that there is less budget kept for the developmental activities of the State. During 2017-18, I have kept a budget provision of rupees 39.55 for every 100 rupees for the developmental activities. While going through budget provision of 2012-13 which was presented by Shri Prem Kumar Dhumal, there was a provision of only rupees 34.51 for every 100 rupees. Thus, my Government is providing 14.60 per cent more money for developmental expenditure compared to 2012-13. I think this figure speaks for itself.

Mr. Speaker, Sir, Shri Prem Kumar Dhumal, Dr. Rajiv Bindal, Shri Inder Singh, Shri Bikram Singh Jaryal, Shri Hans Raj, Shri Govind Ram, Shri Maheshwar Singh and Shri Suresh Kumar raised the issue that no application has been received for taking benefit under the "मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना" despite keeping a budget provision of Rs. 25 crores for 2016-2017.

Mr. Speaker, Sir, there is a provision for providing a subsidy of 60 percent on the total cost of installing fencing energized with the solar power. 148

17.03.2017/1605/SS-AG/2

applications from the farmers have been approved for solar/electric fencing in 2016-17. Many farmers did not apply earlier as they felt that the State Government is going to raise the subsidy as per the newspaper reports. I have already announced in my Budget speech to enhance the subsidy on the scheme to 80 percent from the existing 60 percent to make the scheme more popular. The farmers will be given option for installation of solar fencing by themselves provided that the technical specifications are fulfilled. I am sure, now more and more farmers will take benefit of the increased subsidy.

Continued by AG in English . . .

17032017/1610/AG-KS/1

Chief Minister Continues . . .

Mr. Speaker, Sir, Dr. Rajiv Bindal, Shri Hans Raj, Shri Maheshwar Singh and Shri Baldev Singh Tomar raised the issue regarding development of tourism sites other than Dharamshala and Shimla.

The Department of Tourism is also developing Tourism Infrastructure under Asian Development Bank Financial Assistance. A project amounting to Rs. 640/- crores has been sanctioned for this infrastructure development. Under this project, Jawalaji Town, Kangra, Chamba, Mandi, Una, Manali, Markanday (Bilaspur), Naina Devi etc. are being developed. In addition to this, a master plan for Naina Deviji, Chintpurniji and Kangra has also been proposed under ADB funded project. Thus, it is incorrect to say that ADB funded infrastructure project is limited to Dharamshala. This is due to the misinformation. I would like to tell them before making a speech they should try to find out the facts. There is no question of any discrimination. For us Himachal Pradesh is one. Himachal

is full of ancient temples, great historical sites and very scenically beautiful areas and all these areas need to be developed and looked after.

Issue was raised that how Himachal Pradesh is declared as Open Defecation Free State. This has pinched them very much. I have not been able to clear their political muck, but other much we have cleared. It is not for nothing that we are able to get national recognition for the work done in this field. For this they don't rely on our figures. All the figures given are checked by Central Government Teams, who visit all the areas and after that they announce the prize. I am happy that Himachal Pradesh has been announced number one State in the country in this field. We should be proud of it. Our effort is to continue it further and improve it further and to see that the toilets are properly made and it becomes a habit with all the people whether in urban areas or in rural areas. They should have

17032017/1610/AG-KS/2

appreciated the efforts of the State Government and the recognition which has been given to us by the Modi Government in this field. It is their philosophy to criticise everything. They will not see if something good is done. When good is done, they deny that also.

Continued by AS in English . . .

17/03/2017/1615/AV/AS/1

They are habitually in denial.

Mr. Speaker Sir, Dr. Rajiv Bindal raised issue that the Central Scheme for eradication of Tuberculosis has been renamed as the State scheme.

Besides the centrally funding National Tuberculosis Control Project the "मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना" has been introduced by the State Government as a State scheme considering the large prevalence of this disease in Himachal Pradesh. The State will bear the cost of the scheme from its own resources. The Government of Himachal Pradesh will provide gap filling in financial, technical and human resource not available under the Centrally Sponsored Programme. "मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना" will work in campaign mode for TB control by searching patients house to house and providing treatment to TB patients at door step. State Government will provide the nutritional support to each and every MDR TB patient which does not exist under the RNTCP programme. Biometric presence will be marked while providing medicines to the TB patients.

By these measures the State proposes to control and eradicate theTB by 2021 as announced by me in the Budget Speech. Thus, it is incorrect to say that the Government has merely renamed the Central TB Project. Both are going on side by side. They are complimentary and supplementary to each other and aim is to eradicate Tuberculosis by 2021.

17/03/2017/1615/AV/AS/2

Sir, Shri Prem Kumar Dhumal raised issue; What activities have been undertaken with the State innovation Fund and how they are being implemented?

Speaker, Sir, With a view to promote innovation in day to day working of the Government Departments of the State, the state innovation Fund was

instituted in 2013-14. During the last four years, eleven schemes/projects of various departments amounting to Rs. 2.50 crore have been funded form this fund. These funds have been provided to different departments for undertaking innovative activities like Blood Bank Management Information System, Video Conferencing Facilities, Document Management System, Digital Libraries, Online-Planning Permissions for Town and Country Planning, Online Inventory Management, System for Medicines etc. A State Innovation Council under the chairmanship of the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh has been constituted to approve and fund the departmental proposals.

In order to promote innovation, the State Government has started Himachal Pradesh State Innovation Award Scheme from the year 2014-15 in the six identified sectors namely-Agriculture and Horticulture, Academics, Food Processing and Manufacturing, Social Development, Tourism and Government Sector. The awards for the year 2015-16 have been finalized and will be given on 15th April 2017.

Continue by AS ……

17/03/2017/1620/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

Hon'ble Chief Minister continue….

Hon'ble Speaker, Sir, I am asking to each and every point raised by the Hon'ble Members of the Opposition but they have Walked Out. Because they can't face the truth. I think it is my duty to state the facts as they are in the Hon'ble House so they become the part of the record. ढ़ीला वॉक्आउट है यदि इनको अर्जेंट काम है तो क्या सभी को अर्जेंट काम हो गया?

Shri Prem Kumar Dhumal raised issue that the benefit of the scheme of providing Anti Hail Nets was made available only to a few people. Speaker, Sir, 473 .73 hectares area has been covered under Anti Hail Net Scheme benefiting 1,514 orchardists during last four years in the State. The State government will cover more farmers in the financial year 2017-18 under Anti Halt Net Scheme.

Speaker, Sir, our Government has raised the subsidy on Anti Hail Nets from 50 percent to 80 percent in the Budget Speech for the year 2014-15.

Speaker, Sir, I think most of the points are raised by the Opposition, those who are not here, there replies I want to put on the Table of the House. So that it becomes record of the proceedings.

The Issue was raised by Professor Prem Kumar Dhumal that the Electricity production in the State has come down. How much is the electricity generation in the last four years.

Speaker Sir, the Leader of Opposition mentioned that generation of electricity has come down. This was mainly due to shutting down of Bhaba Hydel Project as a result of a calamity in the year 2014-15. The temporary closure of this project adversely affected the power production of the Himachal Pradesh State Electricity Board Limited in the short run. However, overall power production in the State has not declined. The power production in the State sector has increased from 7,745 million units in 2013-14 to 8,371 million units in 2015-16. The generation during 2016-17 is 8,976 million units. Hence,

17/03/2017/1620/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

the power production in the State is continuously increasing. The total installed capacity with regard to the hydel power generation from all the projects has increased by 2,067 mega watts between April, 2013 and March, 2017 in the State.

Again the issue was raised by Professor Prem Kumar Dhumal, Sh. Maheshwar Singh, Sh. Satpal Satti, Col. Inder Singh and Sh. Vikram Singh Jaryal that what is the present status of and how many Non-Government Organizations are managing the Gosadans in the State?

Speaker Sir, at the end of the year 2014-15, there were 74 Godsadans run by the Non Government Organizations with about six thousand animals. Currently, there are 129 Gosadans being run by the Non -Government Organizations and one by the State Government at Khajjiayan in Kangra district. These Gosadans have ten thousand and four hundred animals in them. The State Government has constituted Govansh Samvardhan Board to ensure smooth functioning of these Gosadans in the State.

The issue was raised by Professor Prem Kumar Dhumal, Sh. Govind Sharma, Dr. Rajiv Bindal, and Sh. Rajeev Sehjal that Medical claims not being paid to pensioners.

Speaker Sir, the State Government is very much committed about the timely release of medical claims of the pensioners in last 4 years, an amount of Rs. 247 Crore was released to clear medical bills of retirees. For 2017-18, 67 Crore have been provided for this purpose. Further, I assure this August House that additional funds will be provided for medical reimbursement of the pensioners, as and when required.

Professor Prem Kumar Dhumal, Sh. Maheshwar Singh, Dr. Rajiv Bindal, Sh.. Baldev Singh Tomar, Col. Inder Singh Sh. Rajeev Sehjal, Sh. Suresh Kumar, and Sh. Vikram Singh Jaryal also raised the issue that there has been a delay in the preparation of DPRs for declared National Highways in the State.

17/03/2017/1620/टी0सी0वी0/ए0एस0/3

Speaker Sir, The Union Government conveyed "in principle" approval declaring 56 National Highways in July, 2016 which were subsequently raised to 61

National Highways with a total length of 3,880 kilometers in November, 2016 subject to preparation of the DPRs the State Government took proactive action and initiated the process of inviting tenders for appointing consultants for preparation of DPRs. The ministry of Road Transport and Highways revised guidelines for procurement, preparation, review and approval of DPRs in August, 2016. The State Government had to recall the tenders for preparation of DPRs due to the revision of guidelines by the Central Ministry causing delay in appointing the consultants. As per the revised guidelines, rebidding is required to be done where single bid is received even after second tender. Despite all odds, consultancy tenders in accordance with the directions of the Central Ministry are being processed by the State Government. There is no delay on part of the State Government in appointment of consultant. In fact, the delay has been caused due to the poor response from the consulting firms, change of guidelines and instructions of the Central Ministry for recalling tenders.

The issue was raised by Sh. Maheshwar Singh, Col. Inder Singh, Dr, Rajiv Sehjal, Sh. Baldev Tomar and Sh. Vikram Singh Jaryal that DPRs of MLA priority schemes are not prepared.

Speaker Sir, the State Government has issued instructions to the departments of Public Works and IPH to accelerate the process of preparation of MLA priority schemes. The State Government has also approved preparation of DPRs through outsourcing. As a result, the process of preparation of DPRs has been improved. The DPRs about Rs. 1,100 crore have been prepared and posed to NABARD during the current financial year itself.

The issue was raised by Professor Prem Kumar Dhumal, Dr. Rajiv Bindal, Sh. Hans Raj, Sh. Maheshwar Singh, Sh. Baldev Tomar, Col. Inder Singh, Sh.

17/03/2017/1620/टी0सी0वी0/ए0एस0/4

Vikram Jaryal and Sh. Suresh Kumar related to Unemployment Allowance announced in this Budget.

Speaker Sir, Hon'ble Members are aware that my Government has been very concerned about providing employment opportunities to the youth of the State. In 2013, we had implemented Skill Development Allowance scheme which has benefitted over 1.55 lakh youth in last four years. The youth have been provided employment enhancing skills in the field of ITI training, polytechnic courses, paramedical courses, computer/electronic trades and certified training in trades like beautician, cutting and Tailoring, electrician, fashion designing etc. I have announced unemployment allowance to unemployed youth at the rate of 1,000 Rupees per month in my Budget Speech. My government will come out with a detailed policy guidelines in this regard at the earliest. The 100 crore rupees Skill Development Allowance budgetary outlay is in additional to the proposed budget of Rupees 150 crore for Unemployment Allowance.

Sh. Satpal Satti, Sh. Baldev Tomar, Col. Inder Singh, Sh. Suresh Kumar have raised the issue of Law and Order situation in the State.

The Law and order situation in the State of Himachal Pradesh as analyzed from the Sate Crime Record Bureau data is under control. The Police force of the State had played a praiseworthy role in containing and detecting the crime working with scientific temperament and sensitivity required to deal with the dynamics of crime arising due to social change. Himachal Pradesh Police has kept itself abreast with latest technology, legal know how and the changing where- withal of the crime scenario. With the introduction of various new schemes backed by technological knowhow, Himachal Pradesh Police has been successfully in effective enforcement of the legal mandate and meeting the expectation of the society. 17,221 cases were registered during the year 2015 and 17,249 cases have been registered during 2016. Therefore, there is an increase of only 28 cases during the year 2016 as compared to 2015.

Speaker Sir, I am unable to understand why few Members of Opposition have failed to see the new polices programmes and initiatives in the budget. If one goes through my speech with open mind, the budget 2017-18 has provided relief to all sections of the society.

This budget gives a clear cut direction for investments in critical sectors of Agriculture, Horticulture, Irrigation, Industries and Power. This budget opens up employment opportunities for youth in Government as well as in Non-Government sectors.

Speaker Sir, I have tried to cover most of the issues raised by the Hon'ble Members in my reply. Some points might have been left out, but no Member should doubt the determination of my Government for all round development of State. In a democratic set up, there is a big room for discussion and debate. However, criticism should be objective and not merely for the sake of criticism. We are working in a right direction and no obstacle can come in our way to deter us from the path of inclusive development of the State. May I conclude by saying:-

"हरेक राह में चिराग जलाना है मेरा काम,
तेवर हवाओं के मैं देखा नहीं करता।"

Jai Hind,

Jai Himachal.

Hon'ble Speaker, Sir, I thank all the Hon'ble Members who participated in the debate. I also thank the Members not only from the Opposition but of the Ruling Party who made a biggest reply and contributed very forcefully in the debate and put forwarded the point of view of the Party and highlighted the achievements of the Government. I also thanks all the Officers/Officials who worked very hard to prepare the Budget and also matters connected with it.

अध्यक्षः इससे पूर्व कि मैं आज सभा की बैठक स्थगित करूं, सदन की विभागीय स्थाई समितियों से अपेक्षा है कि वे सत्र के स्थगन के दौरान अनुदान मांगों का बारीकी से

17/03/2017/1620/टी0सी0वी0/ए0एस0/6

अध्ययन करें। उसके बाद अपने-अपने प्रतिवेदन 27 मार्च 2017 को जब सभा की बैठक पुनः आरम्भ होगी प्रस्तुत करें। मुझे पूर्ण आशा है कि समितियों के सभापति एवं सभी सदस्य गहन रूचि लेकर इस कार्य को संपन्न करेंगे और अपनी-अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां सरकार को देंगे।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

17/03/2017/1625/ एन0एस0/डी0सी0 /1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय विपक्ष द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों का विस्तृत तौर पर जवाब दे रहे थे और अभी तक इन्होंने आधा ही जवाब दिया था, तभी विपक्ष के नेता खड़े हो गए। मैंने उनको कहा कि आप पूरी स्पीच तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे किसी अर्जेंट काम पर जाना है, मैं अपने काम पर जा रहा हूं और मैं अकेला ही जा रहा हूं। So it should not be treated as a walkout by the Opposition. That is my submission to you. क्योंकि इन्होंने पहले कभी नहीं कहा कि मुझे जाना है और मुझे अर्जेंट काम है। बाकी सदस्य तो ऐसे ही साथ चले गए। इसको वाकआउट नहीं कहा जाएगा।

अध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक सोमवार 27 मार्च, 2017 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनांकः 17-03-2017 **सचिव।**